JOTI JOURNAL
SUBJECT- INDEX
FEBRUARY – DECEMBER – 2022

Editorial		1
Editorial		67
Editorial		117
Editorial		161
Editorial		219
Editorial		267

PART-I
(ARTICLES & MISC.)

1.	Appointment of Judges in High Court of Madhya Pradesh	7
2.	Hon'ble Shri Justice Rajeev Kumar Dubey demits Office	226
3.	Hon'ble Shri Justice Satish Kumar Sharma demits office	122
4.	Hon'ble Shri Justice Rajeev Kumar Shrivastava demits office	274
5.	Transfer of Hon'ble Shri Justice Purushaindra Kumar Kaurav to the High Court of Delhi	121
6.	Obituary	74
7.	Photographs	3
8.	Photographs	69
9.	Photographs	119
10.	Photographs	221
11.	Photographs	163
12.	Photographs	269
13.	Annual Report of the activities of MPSJA	275
14.	Applicability of Section 50 NDPS Act in case of Composite Search	123
15.	Assessment of Mesne Profits – Various aspects	181
16.	Complaint by Court u/s 340 CrPC – Various aspects	84
17.	Detailed Accident Report: Need of the Hour	172
18.	Intellectual Property Rights : Scope of grant of Injunctive Relief	191
19.	Law of partition: Preliminary Decree and Final Decree	254
20.	M.P. Amendment in Order XVIII of the C.P.C. – An Overview	167
21.	Order of Acquittal under Section 232 of Cr.P.C.	247
22.	Patent Illegality : A Bird's Eye View	130
23.	Permanent Disability : Principles for Assessment	75

24.	Principles of determination of juvenility under Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015	47
25.	Procedure of Delayed Registration of Births and Deaths	152
26.	Public Policy : A conspectus	288
27.	Recording of Statement under Section 164 CrPC	296
28.	Right of private defence is momentary : Begins with apprehension and ends by the disappearance of apprehension	206
29.	Sections 207 and 208 CrPC : Rights of Accused	102
30.	Section 258 CrPC : Elucidated	317
31.	Some guiding principles of appreciation of evidence in civil cases	20
32.	Trademark Infringement	144
33.	Unlocking accused's Phone : A case comment	324
34.	न्यायालय फीस तथा क्षेत्राधिकार के प्रयोजन से वाद का मूल्यांकन : मार्गदर्शी सिद्धांत	11
35.	मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015	227
36.	भू–अर्जन संबंधित विधिः एक सिंहावलोकन	236
37.	मोटर दुर्घटना दावों पर मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का प्रभाव	96
38.	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का अनुदत्त किया जाना : मार्गदर्शी सिद्धांत	198
39.	वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत व्यादेश तथा निष्कासन के वादों के संबंध में संशोधन अधिनियम, 2013 का सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता पर प्रभाव	139
40.	यात्रा देयक विचारणीय बिन्दु	306
41.	विधिक समस्यायें एवं समाधान	
	(1) क्या हिन्दू देवता अथवा मूर्ति को शाश्वत अवयस्क (perpetual minor) माने जाने से देवता अथवा मूर्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाहियों में परिसीमा विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं?	62
	(2) क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत प्रस्तुत अवधि बाधित परिवाद में अपराध का संज्ञान लेने के उपरांत विलम्ब क्षमा किया जा सकता है?	64
	(3) क्या किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के किशोर की आयु निर्धारण संबंधी प्रावधान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अभियोक्त्री की आयु निर्धारण में भी लागू होते है? और क्या आयु निर्धारण के लिए अस्थि संयोजन परीक्षण के निष्कर्ष निर्णयात्मक होंगे?	65

(4) क्या शासन के विरूद्ध पारित धन सम्बन्धी डिक्री के निष्पादन के अपालन की दशा में शासकीय अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है? 113

(5) क्या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में धारा 389 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दण्डादेश के निष्पादन का निलम्बन किया जा सकता है?

(6) क्या किसी अभियुक्त को जो फरार है या जिसके विरूद्ध स्थाई गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है?

(7) क्या आदेश 23 नियम 1 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत वाद के प्रत्याहरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का प्रत्याहरण किया जा सकता है?

(8) क्या आदेश 7 नियम 11 (घ) सि.प्र.सं. के अन्तर्गत ''विधि द्वारा वर्जित'' शब्दावली में ''विधि'' के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी आते हैं?

(9) परिवाद पर संस्थित मामलों में क्या दण्डादेश की वृद्धि हेतु परिवादी द्वारा पुनरीक्षण याचिका प्रचलनशील है? 157

(10) क्या सिविल मामलों में केवल निष्कर्ष (finding) के विरूद्ध अपील प्रचलनशील है?

(11) क्या एक बार किसी साक्षी के कथन धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध करने के उपरांत पुनः उसी साक्षी के कथन दुबारा लेखबद्ध किये जा सकते हैं?

(12) क्या सेशन न्यायालय पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में तथा आपराधिक अपील को पुनरीक्षण याचिका में परिवर्तित कर सकता है?

(13) क्या अपील के लंबित रहने तक अपील न्यायालय ''दोषसिद्धि के निष्कर्ष'' को निलंबित कर सकता है? 216

(14) किसी आपराधिक प्रकरण में जप्त/प्रस्तुत कूटरचित दस्तावेजों की अभिरक्षा के संबंध में विचारण के दौरान क्या आदेश किया जाना चाहिए?

(15) क्या मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण, अपने द्वारा पारित अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है?

(16) क्या जमानत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या पूर्व में प्रदत्त जमानत को निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रचलनशील है?

(17) जिला न्यायालय स्तर पर आर्विट्रेटर की नियुक्ति के संबंध में क्या व्यवस्था है। 265

(18) क्या आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत हुये बिना न्यायालय द्वारा वाद स्वमेव (*Suo motu*) निरस्त किया जा सकता है।

(19) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 में वर्णित मामला में धारा 340 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व प्रारंभिक जांच एवं प्रस्तावित अभियुक्त को सुना जाना आदेशात्मक है।

(20) क्या ऐसे अपराध जो 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है जमानतीय है ?

(21) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत अर्जित भूमि के संबंध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान लागू होते हैं।

PART-II
(NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)		
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)		
Sections 12(1) and 13 – (i) Protection against eviction – Section 13 would apply even if the ground of eviction is not one u/s 12(1) (a) of the Act. (ii) Duty of tenant to deposit rent – If suit is instituted on any ground mentioned u/s 12, the tenant is obliged to deposit the amount of rent throughout the proceedings. (iii) Execution of decree – Compliance of section 13 does not amount to stay of the decree for eviction.		
धाराएं 12(1) एवं 13 – (i) निष्कासन के विरूद्ध संरक्षण – यदि अधिनियम की धारा 12(1)(क) के अंतर्गत निष्कासन का आधार न हो तो भी धारा 13 प्रयोज्य होगी। (ii) किराया निक्षिप्त करने का अभिधारी का कर्तव्य – यदि वाद धारा 12 में उल्लेखित किसी आधार पर संस्थित किया गया है, अभिधारी संपूर्ण कार्यवाही के दौरान किराये की राशि निक्षिप्त करने के लिए बाध्य है। (iii) डिक्री का निष्पादन – धारा 13 का अनुपालन, निष्कासन की डिक्री के स्थगन के समतुल्य नहीं होगा।	**166**	**189**
Section 23A – Eviction suit – Necessary party – Impleadment of third party claiming title on rented premises – Not permissible.		
धारा 23क – बेदखली वाद – आवश्यक पक्षकार – किरायाधीन परिसर पर स्वामित्व का दावा करते हुए तीसरे पक्ष को पक्षकार बनाना – अनुज्ञेय नहीं है।	**167**	**190**
Section 23-A(b) – Eviction under Chapter-III-A – There is a presumption of *bona fide* requirement in favour of the applicant but the same is rebuttable.		
धारा 23–क(ख) – अध्याय 3–क के अंतर्गत निष्कासन – आवेदक के पक्ष में सदभाविक आवश्यकता की उपधारणा होती है परन्तु वह खण्डनीय है।	**217**	**249**
Section 23J – Specific category of landlord – Definition – Extended to employees of the companies, corporations or public undertakings of the State Government as well as the Central Government.		
धारा 23ञ – भू–स्वामी का विनिर्दिष्ट प्रवर्ग – परिभाषा – राज्य सरकार के साथ–साथ केंद्र सरकार की कंपनियों, निगमों या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों तक इसका विस्तार है।	**168**	**191**
APPRECIATION OF EVIDENCE :		
साक्ष्य का मूल्यांकन :		
– See sections 3, 8, 17 and 68 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8, 17 एवं 68।	**20**	**22**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– See sections 3 and 9 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 9।	**71**	**79**
– See sections 3 and 145 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 145।	**21**	**24**
– See section 27 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27।	**22**	**26**
– See sections 34 and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34 एवं 302।	**30**	**36**
– See sections 101 and 106 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 101 एवं 106।	**25**	**30**
– See section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
– देखें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166।	**48**	**54**
– See sections 299 and 300 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 299 एवं 300।	**32**	**41**
– See sections 300, Exception 4 and 304 Part II of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300, अपवाद 4 एवं 304 भाग–दो।	**33***	**42**
– See section 376(2)(g) of the Indian Penal Code, 1860 and Section 3 of the Evidence Act, 1872		
–देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(छ) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	**141**	**157**
ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996		
माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996		
Sections 2(1) (h), 7, 8, 11, 16 and 37 – Group of companies doctrine – Non-signatory party when bound by the agreement – Deciding factors enumerated.		
धाराएं 2(1) (h), 7, 8, 11, 16 एवं 37 – 'कंपनियों का समूह' सिद्धांत – गैर–हस्ताक्षरकर्ता पक्षकार कब समझौते से बाध्य हो सकते हैं – निर्णायक कारक प्रगणित।	**273**	**323**
Sections 11 and 34 – Effect of award passed with consent of parties on subsequent reference petition.		
धाराएं 11 एवं 34 – पक्षकारों की सहमति से पारित अधिनिर्णय का पश्चातवर्ती निर्देश याचिका पर प्रभाव।	**218**	**249**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 16 and 34 – Application against award where exclusive jurisdiction is provided.		
धाराएं 16 एवं 34 – अधिनिर्णय के विरूद्ध आवेदन जहाँ न्यायालय का एकमात्र क्षेत्राधिकार प्रावधानित है।	**219**	**250**
Sections 16 and 34 – Objection – Though no objection regarding jurisdiction was raised before the Arbitration Tribunal, such objection can be raised before the Court in application u/s 34 of the Act.		
धाराएं 16 एवं 34 – आक्षेप – यद्यपि क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई आक्षेप माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष नहीं उठाया गया था परंतु ऐसा आक्षेप अधिनियम की धारा 34 के अतंर्गत आवेदन में न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है।	**169 (ii)**	**191**
Sections 28 (3) and 34 – Arbitral award – The ground of patent illegality is attracted when matter is not decided as per the terms of the contract which governs the parties.		
धाराएं 28(3) एवं 34 – माध्यस्थम् पंचाट – प्रकट अवैधता का आधार तब आकर्षित होता है जब पक्षकारों को शासित करने वाली संविदा की शर्तों के अनुसार मुद्दे का निराकरण नहीं किया जाता है।	**56**	**65**
Section 34 – Arbitral award – Court cannot use its appellate power while dealing with any petition filed u/s 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
धारा 34 – माध्यस्थम् पंचाट – माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अतंर्गत प्रस्तुत की गयी याचिका पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।	**57***	**65**
Section 34 – Rewriting of contract – Award based on changed circumstances after execution of contract does not mean that the contract has been rewritten by the Arbitrator.		
धारा 34 – संविदा का पुनर्लेखन – संविदा के निष्पादन के पश्चात् परिवर्तित परिस्थितियों पर आधारित अधिनिर्णय का तात्पर्य यह नहीं होता है कि मध्यस्थ द्वारा संविदा का पुनर्लेखन किया गया है।	**108**	**119**
Section 34 (4) – Remission of matter to Arbitrator – Arbitrator may be given a chance to give reasons in support of award and an opportunity to fill up the gaps by the Court on request of a party .		
धारा 34 (4) – मध्यस्थ को प्रकरण का प्रेषण – किसी पक्षकार के निवेदन पर न्यायालय द्वारा मध्यस्थ को अवार्ड के समर्थन में कारण दिये जाने का और कारणों की कमियों को भी पूरा करने का अवसर दिया जा सकता है।	**170**	**193**
Sections 34 and 36 – Whether the jurisdiction of an Arbitrator to pass the award can still be challenged in the execution proceeding of the award in the civil court? Held, no.		
धाराएं 34 एवं 36 – क्या एक मध्यस्थ के पंचाट पारित करने के क्षेत्राधिकार को पंचाट के निष्पादन की कार्यवाही में चुनौती दी सकती है? – अभिनिर्धारित नहीं।	**58***	**66**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 37 – The provision of Section 5 of the Limitation Act is applicable to appeals which are filed u/s 37 of the Arbitration Act related to commercial disputes of specified value.		
धारा 37 – परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत प्रस्तुत उन अपीलों पर भी लागू होते हैं जो विशिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित हैं।	**1**	**1**
ARMS ACT, 1959		
आयुध अधिनियम, 1959		
Sections 4 and 25 – (i) Ballistic report – Bullet recovered not matching with fire arm – Effect of – Not possible to reject credible and reliable deposition of eye-witness – Recovery of the weapon used in commission of offence not a *sine qua non*. (ii) Expert opinion – Statement given by doctor at the most is his opinion.		
धाराएं 4 एवं 25 – (i) प्राक्षेपिकी रिपोर्ट – जब्तशुदा कारतूस आग्नेयास्त्र से मेल नहीं खाता – प्रभाव – चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता – अपराध को प्रमाणित करने के लिये हथियार की बरामदगी अनिवार्य शर्त नहीं है। (ii) विशेषज्ञ साक्षी की राय – चिकित्सक द्वारा दिया गया कथन मात्र उसकी राय है।	**137**	**153**
Sections 25 and 27 – See sections 34, 302 and 307 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 25 एवं 27 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34, 302 एवं 307।	**76**	**82**
Sections 25 and 27 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 25 एवं 27 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	**77**	**84**
Section 27 – Injury caused by fire arm which is a dangerous weapon – Accused cannot escape from punishment for using arms prescribed u/s 27 of the Arms Act.		
धारा 27 – उपहति, अग्नायुध से कारित, जो खतरनाक आयुध है – आरोपी अग्नायुध के उपयोग के फलस्वरूप दिये जाने वाले दण्ड, जो धारा 27 आयुध अधिनियम में वर्णित है से बच नहीं सकता।	**253 (ii)**	**301**
CIVIL COURTS ACT, 1958 (M.P.)		
सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (म.प्र.)		
Section 3 – See sections 8, 12, 26 and 27 of the Public Trusts Act, 1951 (M.P.).		
धारा 3 – देखें लोक न्यास अधिनियम, 1951 (म.प्र.) की धाराएं 8, 12, 26 एवं 27।	**101**	**105**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CIVIL PRACTICE :		
सिविल प्रथा :		
– See section 96 and Order 41 Rule 31 of the Civil Procedure Code, 1908.		
– देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 31।	**4**	**5**
– See sections 101 and 102 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 101 एवं 102।	**24**	**29**
CIVIL PROCEDURE CODE, 1908		
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908		
Section 9 – Jurisdiction of Civil Court – Jurisdiction to decide question of title and nature of sale deed is vested with the Civil Court and not with the Revenue Court.		
धारा 9 – सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार – स्वत्व का प्रश्न एवं विक्रय पत्र की प्रकृति विनिश्चित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में निहित है न कि राजस्व न्यायालयों में।	**109***	**119**
Section 9 – See section 10 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.		
धारा 9 – देखें शहरी भूमि (सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 10।	**164**	**184**
Section 9 – Question of title – Jurisdiction – Proof – Whether Tehsildar has any jurisdiction to consider a disputed Will and pass an order of mutation? No – Revenue Court does not have any jurisdiction to dwell upon the question of title of a party – Civil rights of the party are to be determined by the Civil Court and not by the Revenue Court.		
धारा 9 – स्वत्व का प्रश्न – क्षेत्राधिकार – प्रमाण – क्या तहसीलदार के पास ऐसा कोई क्षेत्राधिकार है जो विवादित वसीयत पर विचार कर नामांतरण का आदेश पारित करे – नहीं – राजस्व न्यायालय पक्षकारों के स्वत्व को अभिनिर्धारित करने के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं रखता है – पक्षकारों के सिविल अधिकार सिविल न्यायालय द्वारा ही अभिनिर्धारित किए जाते है न कि राजस्व न्यायालय द्वारा।	**148**	**167**
Sections 9 and 21 – Jurisdiction – When any claim in the suit is founded by an employee on the provisions of Industrial Disputes Act, then such suit cannot be entertained by the Civil Court.		
धाराएं 9 एवं 21 – क्षेत्राधिकारिता – जहां किसी कर्मचारी द्वारा वाद में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर कोई दावा किया जाता है वहां ऐसा वाद व्यवहार न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता।	**59**	**66**
Sections 10 and 151 – (i) Stay of suit – Applicability of Section 10 – Test is whether on final dicision being reached in the previously instituted suit, such decision would operate as *res judicata* in the subsequently instituted suit.		

(ii) Consolidation of suits – In previously instituted suit, relief of injunction was sought and in subsequently instituted suit relief of declaration and injunction were sought – Final decision in previously instituted suit would not operate as *res judicata* in the subsequent suit – To avoid multiplicity of proceedings, consolidation of both suits would be in the interest of justice.

धाराएं 10 एवं 151 – (i) वाद का रोका जाना – धारा 10 की प्रयोज्यता – परीक्षण यह है कि क्या यदि पूर्व संस्थित वाद में अंतिम विनिश्चय होगा तो ऐसा निर्णय पश्चातवर्ती संस्थित वाद के लिए पूर्व न्याय का प्रभाव रखेगा।

(ii) वादों का समेकन – पूर्व संस्थित वाद में निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई थी तथा पश्चातवर्ती संस्थित वाद में घोषणा तथा निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई थी – पूर्व संस्थित वाद का अंतिम विनिश्चय पश्चातवर्ती संस्थित वाद पर पूर्व न्याय का प्रभाव नहीं रखेगा – कार्यवाही की बाहुल्यता को रोकने के लिए, दोनों वादों का समेकन न्यायहित में है। **110* 120**

Sections 10 and 151 – Stay of suit – Former suit cannot be stayed as that would be travelling beyond the scope of Section 10.

धाराएं 10 एवं 151 – वाद का रोका जाना – पूर्व में प्रस्तुत वाद को स्थगित नहीं किया जा सकता यह धारा 10 की परिधि से बाह्य है। **274* 324**

Section 11 – *Res judicata* – Effect of change in law – Earlier decision would not create any binding precedent.

धारा 11 – *पूर्व न्याय* – विधि में परिवर्तन का प्रभाव – पूर्व निर्णय बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखेगा। **187 (ii) 209**

Section 11 – *Res judicata* – Previous suit decided on erroneous facts – Binding upon the parties cannot be challenged – Principle of *res judicata* applicable.

धारा 11 – *पूर्व न्याय* – पूर्व वाद त्रुटिपूर्ण तथ्यों पर निर्णित – पक्षकारों पर बाध्यकारी – *पूर्व न्याय* का सिद्धांत लागू होगा। **211 (ii) 240**

Sections 11 & 47 and Order 21 Rules 54, 64 and 66 – Execution of decree – Applicability of *res judicata*.

धाराएं 11 एवं 47 तथा आदेश 21 नियम 54, 64 एवं 66 – आज्ञप्ति का निष्पादन – *पूर्व न्याय* की प्रयोज्यता। **2 2**

Section 11 and Order 23 Rules 3 & 3A – (i) *Res Judicata* – Whether plea of *res judicata* can be decided as a preliminary issue?

(ii) *Res judicata* – Whether issues conclusively decided in previous suit?

(iii) *Res judicata* and compromise decree.

धारा 11 एवं आदेश 23 नियम 3 एवं 3–क – (i) *पूर्व न्याय* – क्या *पूर्व न्याय* का अभिवाक् प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में निर्णीत किया जा सकता है?

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) *पूर्व न्याय* – क्या पूर्ववर्ती वाद में विवाद्यकों को अंतिम रूप से निर्णीत किया गया था? (iii) *पूर्व न्याय* एवं समझौता आज्ञप्ति।	**3**	**3**
Sections 11 Expln. 7 and 8, Order 34 Rule 1 and Order 21 Rules 101 and 103 – See Sections 59A, 60 and 91 of the Transfer of Property Act, 1882. **धाराएं 11 स्पष्टीकरण 7 एवं 8, आदेश 34 नियम 1 एवं आदेश 21 नियम 101 एवं 103** – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धाराएं 59क, 60 एवं 91।	**106**	**113**
Section 47 – See sections 34 and 36 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 **धारा 47** – देखें माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 34 एवं 36।	**58***	**66**
Section 96 and Order 41 Rules 31and 33 – See Hindu Law. **धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 31 एवं 33** – देखें हिन्दू विधि।	**301**	**353**
Secton 96 r/w Order 41 Rule 31 – First appeal – Mandatory requirements – Conscious application of mind must be reflected in the judgment of the Appellate Court and findings on all questions of fact and law must be supported by reasons – Arguments rendered by parties should also be mentioned in the judgment. **धारा 96 सहपठित आदेश 41 नियम 31** – प्रथम अपील – अनिवार्य अपेक्षाएं – अपीलीय न्यायालय के निर्णय में मस्तिष्क के सचेतन उपयोग का प्रदर्शन होना ही चाहिए एवं तथ्य और विधि के सभी प्रश्नों के निष्कर्ष कारणों से समर्थित होने चाहिए – निर्णय में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का भी विवरण दिया जाना चाहिए।	**111**	**120**
Section 96 and Order 41 Rule 31 – (i) First appeal – Procedure for deciding. (ii) Specific performance of contract – Readiness and willingness of plaintiff – Affidavit stating that he is ready and willing to execute the sale deed cannot be relied upon in absence of pleadings. **धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 31** – (i) प्रथम अपील – निराकृत करने की प्रक्रिया। (ii) संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन – वादी का तत्पर एवं इच्छुक होना – शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया गया कि वह विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक है, अभिवचनों के अभाव में इस पर अवलंब नहीं लिया जा सकता है।	**4**	**5**
Section 151 – Consolidation of suit – Purpose. **धारा 151** – वादों का समेकन – प्रयोजन।	**5***	**8**
Sections 151, 152 & 153 and Order 23 Rule 3 – (i) Compromise in civil case – Vitiated by fraud, misrepresentation or mistake – Would not serve as estoppels. (ii) Consent decree – Exercise of inherent power – The illegality and validity of a compromise can be examined u/s 151 CPC.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 151, 152 एवं 153 और आदेश 23 नियम 3 – (i) सिविल मामलों में समझौता – कपट, मिथ्या – दुर्व्यपदेशन अथवा त्रुटि से दूषित – विबंध के रूप में पर्याप्त नहीं होंगे। (ii) सहमति डिक्री – अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग – समझौते की अवैधता और वैधता को सीपीसी की धारा 151 के अन्तर्गत परीक्षण किया जा सकता है।	**275**	**324**
Order 1 Rule 10 and Order 6 Rule 4 (a) – Impleadment of State as party – Dispute exists between plaintiff and Krishi Upaj Mandi with regard to boundary wall – No agricultural land is involved – Relief could not be sought against the State and provisions of Order 6 Rule 4 (a) of the Code shall not be attracted. **आदेश 1, नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 4(क)** – राज्य को पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना – वादी तथा कृषि उपज मण्डी के बीच चारदीवारी के सम्बंध में विवाद विद्यमान है – कृषि भूमि संलिप्त नहीं है – राज्य के विरूद्ध कोई सहायता नहीं मांगी जा सकती थी और संहिता के आदेश 6 नियम 4(क) के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे।	**112***	**121**
Order 1 Rule 10 – Unregistered sale agreement does not create any right in favour of purchaser specially when sale of property is stayed. **आदेश 1 नियम 10** – अपंजीकृत विक्रय का करार क्रेता के पक्ष में कोई अधिकार निर्मित नहीं करता है विशेष रूप से तब जब संपत्ति के व्ययन पर रोक है।	**220***	**251**
Order 1 Rule 10 and Order 6 Rule 17 – (i) Incorporation of amendment – Change in nature of suit – Such an amendment cannot be allowed. (ii) Civil Suit – Joinder of parties – Principle of dominus litis – Applicability – Only when the party is necessary or proper party. **आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17** – (i) संशोधन का समावेश – वाद की प्रकृति में परिवर्तन – ऐसे संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (ii) सिविल वाद – पक्षकारों का जोड़ा जाना – डोमिनस लिटिस का सिद्धांत – प्रयोज्यता – केवल तभी जब पक्षकार आवश्यक या उचित हो।	**276***	**325**
Order 3 Rules 1 and 2 – Recording of evidence through power of attorney – Scope explained. **आदेश 3 नियम 1 व 2** – मुख्तारनामा धारक द्वारा साक्ष्य दिया जाना – विस्तार बताया गया।	**277**	**325**
Order 7 Rule 11 – (i) Application under Order 7 Rule 11 – Factors to be considered. (ii) Determination of preliminary issues. **आदेश 7 नियम 11** – (i) आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन – विचार में लिये जाने वाले तथ्य। (ii) प्रारम्भिक विवाद्यकों का निर्धारण।	**221**	**252**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 7 Rule 11 – Jurisdiction – Objection – Two contradictory stands before two different courts cannot be permitted.		
आदेश 7 नियम 11 – क्षेत्राधिकार – आक्षेप – दो भिन्न न्यायालयों के समक्ष दो परस्पर विरोधाभासी रूख की अनुमति नहीं दी जा सकती।	**222**	**252**
Order 7 Rule 11 – Rejection of plaint – Long possession of any caretaker or servant on the property of real owner never converts into adverse possession – Suit for declaration and permanent injunction based on such possession is liable to be rejected due to lack of cause of action.		
आदेश 7 नियम 11 – वाद का नामंजूर किया जाना – किसी अभिरक्षक (रखवाल) या नौकर का वास्तविक स्वामी की संपत्ति पर दीर्घ आधिपत्य कभी भी विरोधी आधिपत्य में परिवर्तित नहीं होता है – ऐसे आधिपत्य के आधार पर घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश के लिये प्रस्तुत वाद नामंजूर किये जाने योग्य होता है क्योंकि इसमें वाद हेतुक का अभाव होता है।	**60**	**67**
Order 7 Rule 11 – Rejection of plaint – Non-disclosure of cause of action – Such a plaint should be rejected for non-disclosure of cause of action under Order 7 Rule 11 of CPC.		
आदेश 7 नियम 11 – वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वाद हेतुक प्रकट नहीं होना – ऐसा वादपत्र, वाद हेतुक प्रकट न करने के आधार पर सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के अधीन नामंजूर किया जाना चाहिए।	**6**	**9**
Order 7 Rule 11 – Scope of revision in civil case – Revisional Court can only analyze jurisdictional error or any procedural irregularity or impropriety caused by the trial Court.		
आदेश 7 नियम 11 – सिविल मामलों में पुनरीक्षण की सीमा – पुनरीक्षण न्यायालय केवल विचारण न्यायालय द्वारा की गई क्षेत्राधिकार की त्रुटि अथवा कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता या अनौचित्यता का विश्लेषण कर सकता है।	**223**	**254**
Order 7 Rule 11 (a) and (d) – Jurisdiction of Civil Court – Cancellation of license by Krashi Upaj Mandi Samiti – Civil Court has no jurisdiction.		
आदेश 7 नियम 11 (क) एवं (घ) – सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार – कृषि उपज मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति का निरस्त किया जाना – सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है।	**171**	**194**
Order 7 Rule 11 (d) – (i) Rejection of plaint – Facts to be considered. (ii) Grounds – Whether plaintiff is entitled to any relief or not has to be considered at the time of trial.		
आदेश 7 नियम 11 (घ) – (i) वादपत्र का नामंजूर किया जाना – विचार करने योग्य तथ्य। (ii) आधार – वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है या नहीं इस पर विचारण के समय विचार किया जाना चाहिए।	**224**	**254**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Order 7 Rule 11(d) – Rejection of plaint – Generally the plaint should not be rejected on the ground of limitation because answer to such ground depends on evidence.

आदेश 7 नियम 11(घ) – वाद का नामंजूर किया जाना– सामान्यतः वाद को परिसीमा के आधार पर नामंजूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे आधार का उत्तर साक्ष्य पर निर्भर करता है। **61** **68**

Order 7 Rule 11 (d) and Order 23 Rule 3A – Rejection of plaint – Bar of jurisdiction – Suit for challenging compromise decree is not maintainable.

आदेश 7 नियम 11 (घ) एवं आदेश 23 नियम 3क – वादपत्र का नामंजूर किया जाना – क्षेत्राधिकार का वर्जन – समझौता आज्ञप्ति को चुनौती देने वाला वाद पोषणीय नहीं है। **172** **194**

Order 7 Rule 14 – Exercise of discretion – Courts of civil judicature also have to adhere to the procedure prescribed in the Code.

आदेश 7 नियम 14 – विवेकाधिकार का प्रयोग – सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय को संहिता में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। **225*** **256**

Order 7 Rule 14 – Production of documents – At the last stage of defendant's evidence, production of documents by the plaintiff should not be allowed.

आदेश 7 नियम 14 – दस्तावेजों की प्रस्तुति –प्रतिवादी साक्ष्य के अंतिम स्तर पर वादी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। **62** **68**

Order 8 Rule 6A – Counter-claim – Can be filed after filing written statement – Counter-claim filed on the cause of action which arose after filing of written statement – Not permissible.

आदेश 8 नियम 6क – प्रतिदावा – लिखित कथन प्रस्तुत करने के पश्चात् पेश किया जा सकता है – प्रतिदावा, जिसका वाद कारण लिखित कथन प्रस्तुत करने के पश्चात् उत्पन्न हुआ – अनुज्ञात नहीं। **226*** **256**

Order 8 Rule 10 – Limitation to file written statement – Exclusion of period of pandemic – Extended to filing of written statement in suit related to commercial disputes.

आदेश 8 नियम 10 – लिखित कथन दाखिल करने हेतु परिसीमा – महामारी की अवधि का अपवर्जन – व्यावसायिक विवादों से संबंधित वादों में लिखित कथन दाखिल करने तक विस्तारित। **173** **195**

Order 9 Rule 9 and Order 17 Rules 2 & 3 – Dismissal of suit – Plaintiff did not appear on date of evidence – Case will fall under Order 17 Rule 2 and not under Rule 3 – Remedy available to plaintiff enumerated.

आदेश 9 नियम 9 एवं आदेश 17 नियम 2 एवं 3 – वाद की खारिजी – साक्ष्य की दिनांक पर वादी अनुपस्थित – प्रकरण आदेश 17 नियम 3 का न होकर नियम 2 का है – वादी को उपलब्ध उपचार बताए गए। **278** **328**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 9 Rule 13 – Exparte decree; setting aside of – Matrimonial dispute.		
आदेश 9 नियम 13 – एकपक्षीय आज्ञप्ति का अपास्त किया जाना – विवाह संबंधी विवाद।	**7**	**10**
Order 9 Rule 13 – Ex parte decree – Remedies available to judgment-debtor.		
आदेश 9 नियम 13 – एकपक्षीय डिक्री – निर्णीत ऋणी को उपलब्ध उपाय।	**300**	**352**
Order 14 – Framing of issue – Omission to frame an issue does not vitiate the trial where the parties go to trial fully knowing the rival case and lead evidence in support of their respective contentions.		
आदेश 14 – वाद प्रश्न की विरचना – जहां पक्षकार दूसरे पक्ष के प्रकरण को पूरी तरह से जानते हुए विचारण के लिए जाते हैं और अपने–अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, किसी वाद प्रश्न को विरचित करने में चूक विचारण को दूषित नहीं करती है।	**162 (ii)**	**181**
Order 14 Rule 2 and Order 41 Rules 24 and 25 – (i) Preliminary issue – Issue is a mixed question of fact and law or issue of law depends on the decision of fact – Cannot be tried as preliminary issue. (ii) Duty of court – The court should pronounce judgment on all issues so as to facilitate the Appellate Court to avoid possibility of remand back.		
आदेश 14 नियम 2 एवं आदेश 41 नियम 24 व 25 – (i) प्रारंभिक वाद प्रश्न – वाद प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है या विधि का प्रश्न तथ्यों के निष्कर्ष पर आधारित है – प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता। (ii) न्यायालय का कर्तव्य – न्यायालय को सभी वाद प्रश्नों पर निर्णय सुनाना चाहिए ताकि इससे अपीलीय न्यायालय को सुविधा हो और प्रतिप्रेषण की संभावना को टाला जा सके।	**227**	**256**
Order 18 Rule 19 and Order 26 Rule 4A – (i) Rejection of evidence – Conduct ofcross-examination of defendant by co-defendant before Commissioner in absence of plaintiff, is the only on irregularity – Does not vitiate proceeding. (ii) Order of examination of defendant – Explained.		
आदेश 18 नियम 19 एवं आदेश 26 नियम 4क – (i) साक्ष्य की अस्वीकार्यता – कमिश्नर के समक्ष सह–प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी का प्रतिपरीक्षण, वादी की अनुपस्थिति में किया गया, केवल अनियमितता है, कार्यवाही को दूषित नहीं करता – मात्र इस आधार पर प्रतिपरीक्षण को रिकार्ड से पृथक नहीं किया जा सकता। (ii) प्रतिवादी के परीक्षण का क्रम – व्याख्या की गई।	**279**	**329**
Order 20 Rule 18 – Limitation prescribed for procuring Final decree.		
आदेश 20 नियम 18 – अंतिम डिक्री हेतु प्रावधानित परिसीमा।	**228 (ii)**	**258**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 21 Rule 16 Explanation r/w/s 47 and 146 – Execution by transferee – Explanation of Order 21 Rule 16 avoids separate suit proceedings by transferee of decree and Order 21 Rule 16 of CPC does not affect the provisions of section 146.		
आदेश 21 नियम 16 स्पष्टीकरण सहपठित धाराएं 47 एवं 146 – अंतरिती द्वारा निष्पादन – आदेश 21 नियम 16 का स्पष्टीकरण डिक्री के अंतरिती द्वारा पृथक वाद कार्यवाही को परिवर्जित करता है और सि.प्र.सं. का आदेष 21 नियम 16 धारा 146 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है।	**63**	**69**
Order 21 Rules 97, 99 and 101 – In execution of a decree for possession, all questions including questions relating to right, title or interest, resistance or obstruction to possession of the property arising between the parties to proceeding shall have to be determined by the executing court on an application filed under rules 97, 99 and 101.		
आदेश 21 नियम 97, 99 एवं 101 – आधिपत्य की डिक्री के निष्पादन में संपत्ति के अधिकार, स्वत्व या हित, आधिपत्य में प्रतिरोध या अवरोध सहित सभी प्रश्न, जो कार्यवाही के पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होते हैं, नियम 97, 99 एवं 101 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर निष्पादन न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाएंगे।	**113**	**122**
Order 22 – See section 5 of the Limitation Act, 1963.		
आदेश 22 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5।	**229**	**260**
Order 23 Rule 3 – See Section 21 of the Legal Services Authorities Act, 1987.		
आदेश 23 नियम 3 – देखें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21।	**230**	**263**
Order 26 Rule 9 – Appointment of Commissioner – When there is a dispute about identity & demarcation of the property and both the parties are claiming it to be their own – Incumbent upon court to issue Commission.		
आदेश 26 नियम 9 – कमिश्नर की नियुक्ति – जब संपत्ति के पहचान एवं सीमांकन का विवाद हो और दोनों पक्ष अपने अधिकारों का दावा करें तब न्यायालय के लिये अनिवार्य है कि वह स्वयं कमीशन का आदेश पारित करे।	**280**	**330**
Order 32 Rule 3 – Guardian of minor not appointed by Court – Compromise decree drawn on the basis of consent on behalf of minor through respondent – Award of Lok Adalat on the basis of such compromise is unlawful and unsustainable.		
आदेश 32 नियम 3 – अवयस्क का वाद मित्र न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं – समझौता डिक्री प्रत्यर्थी के माध्यम से अवयस्क की सहमति द्वारा रचित की गई – ऐसे समझौते के आधार पर लोक अदालत का पंचाट अवैध है और स्थिर रखे जाने योग्य नहीं।	**281***	**331**
Order 39 Rules 1 and 2 – Temporary injunction – Only owner can transfer a good title – Plaintiff not entitled for temporary injunction.		
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – अस्थायी व्यादेश – केवल स्वामी अच्छा स्वत्व अंतरित कर सकता है – वादी अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं।	**282***	**331**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Order 39 Rules 1 and 2 – See section 307(2) and (5) of the Municipal Corporation Act, 1956.

आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – देखें नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (म.प्र.) की धारा धाराएं 307 (2) एवं (5)। **318 377**

Order 39 Rules 1, 2 and 2-A – Effect and implementation – Implementation of order of temporary injunction and order of contempt do not fall in the same category – For violation of temporary injunction order, Civil Courts have very vast power and for such violation, property of violator may also be attached and he may also be imprisoned – In case of contempt, offender may be punished with fine or jail or both.

आदेश 39 नियम 1, 2 एवं 2–क – प्रभाव एवं क्रियान्वयन – अस्थायी व्यादेश एवं अवमान आदेश का क्रियान्वयन समान श्रेणी में नहीं आता है – अस्थायी व्यादेश के उल्लंघन की दशा में सिविल न्यायालय की शक्तियां अधिक विस्तृत हैं और ऐसे उल्लंघन के लिये उल्लंघनकर्ता की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है और उसे कारावास में भी भेजा जा सकता है – अवमान के प्रकरण में अवमानकर्ता को जुर्माने से या कारावास से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। **114 123**

Order 41 Rule 1 – Civil appeal – Duty cast on the Appellate Court to adjudicate first appeal both on question of law and facts.

Civil appeal – Reversing a judgment – Appellate Court must be more conscious of its duty in assigning reason for doing so.

आदेश 41 नियम 1 – सिविल अपील – अपीलीय न्यायालय पर प्रथम अपील को कानून और तथ्यों दोनों के प्रश्नों पर न्यायनिर्णीत करने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है।

सिविल अपील – निर्णय को उलटना – अपीलीय न्यायालय को निर्णय को उलटने का कारण बताने में अपने कर्तव्य के प्रति अधिक सचेत होना चाहिए। **123 (ii) & (iii) 132**

Order 41 Rule 27 – (i) First appeal – Additional evidence – Permission when to be granted?

(ii) Proof – Applicant has to prove the existence, authenticity and genuineness of the documents including contents thereof, in accordance with law.

आदेश 41 नियम 27 – (i) प्रथम अपील – अतिरिक्त साक्ष्य – अनुमति कब दी जानी चाहिए?

(ii) प्रमाण– अपीलार्थी को दस्तावेजों की अंतर्वस्तु सहित उनका अस्तित्व, प्रमाणिकता और वास्तविकता विधि के अनुसार प्रमाणित करना होगी। **257 306**

Order 47 Rule 1 – (i) Review – Power of review may be exercised when some mistake or error apparent on the face of the record is found.

(ii) Judgment obtained by fraud – Cannot be said to be a judgment or order in law – But it need to be established that the judgment or order has been obtained by practicing fraud.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
आदेश 47 नियम 1 – (i) पुनर्विलोकन – जब अभिलेख को देखने से ही कोई भूल अथवा गलती प्रकट होती है तब पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। (ii) कपट द्वारा निर्णय की प्राप्ति – उसे विधि की दृष्टि में निर्णय अथवा आदेश नहीं कहा जा सकता – परन्तु यह स्थापित करना आवश्यक है कि ऐसा निर्णय अथवा आदेश कपट कारित करते हुए प्राप्त किया गया है।	**64**	**70**
COMMERCIAL COURTS, ACT, 2015		
वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015		
Section 13 – See section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
धारा 13 – देखें माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37।	**1**	**1**
Section 16 – See Order 8 Rule10 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 16 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 8 नियम 10।	**173**	**195**
CONSTITUTION OF INDIA		
भारत का संविधान		
Article 20(3) – (i) Order of taking voice sample – Whether amounts to compelling the witness against himself? (ii) Opportunity of hearing – When the matter is at the investigating stage where the prosecution is only collecting the evidence – Opportunity of hearing the accused is not warranted.		
अनुच्छेद 20(3) – (i) आवाज का नमूना लेने का आदेश – क्या स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने को बाध्य करने जैसा है? (ii) सुनवाई का अवसर – जब मामला अन्वेषण के स्तर पर है जहां अभियोजन केवल साक्ष्य एकत्र कर रहा है – अभियुक्त को सुनवाई का अवसर अपेक्षित नहीं है।	**65**	**71**
Article 21 – See Sections 346 and 364-A of the Indian Penal Code, 1860.		
अनुच्छेद 21 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 346 एवं 364–क।	**80**	**88**
Article 50 – See Section 389 (1) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 50 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389(1)।	**69**	**75**
CONSUMER PROTECTION ACT, 1986		
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986		
Section 2(1)(g) – See sections 101 and 102 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 2(1)(छ) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 101 एवं 102।	**24**	**29**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 12 – Motor Insurance – Theft of vehicle – Delay in informing insurance company about theft of vehicle is not a ground to reject the owner's claim.		
धारा 12 – मोटर बीमा – वाहन की चोरी – बीमा कम्पनी को वाहन की चोरी के सम्बंध में देरी से सूचना देना वाहन के स्वामी के दावे को नामंजूर करने का आधार नहीं है।	**66***	**73**
Section 21 – Deficiency in service – The insurer was duty bound to inform the policy holders about the limitations which it was imposing in the policy renewed – Failure to inform the policy holders resulted in deficiency of service.		
धारा 21 – सेवा में कमी – बीमाकर्ता इस दायित्व के अधीन था कि वह पॉलिसी धारक को उन सीमाओं के संबंध में जानकारी दे जो नवीनीकृत पॉलिसी में अधिरोपित की गई थी – पॉलिसी धारक को सूचना देने में असफलता सेवा में कमी के रूप में परिणित होगी।	115	124
Section 21 – Duty of Insured and Insurance Company, explained.		
धारा 21 – बीमा धारक तथा बीमा कम्पनी के कर्तव्य समझाए गए	**116**	**125**
Section 24-A – Bar of limitation – Consumer complaint – Where cause of action continues even after the date of agreement, the limitation period of two years will begin from last of such dates.		
धारा 24–क – परिसीमा का वर्जन – उपभोक्ता परिवाद – जहां अनुबंध की तिथि के बाद भी वाद हेतुक जारी रहता है, दो वर्ष की परिसीमा अवधि ऐसी तिथियों में से अंतिम से प्रारंभ होगी।	**8**	**11**
– Consumer dispute – When does cause of action arise where appellant failed to execute the Deed of Conveyance despite receiving notice from the complainant? Cause of action only after the expiry of period of notice.		
– उपभोक्ता विवाद – वादकारण कब उत्पन्न होगा, जहाँ अपीलार्थी परिवादी से सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद भी अन्तरण विलेख निष्पादित करने में असफल रहा? परिवाद प्रस्तुत करने के प्रयोजन से वादकारण नोटिस की समयावधि समाप्त होने के उपरांत ही उत्पन्न होगा।	**283**	**332**
CONTRACT ACT, 1872		
संविदा अधिनियम, 1872		
Sections 67 and 73 – Difference between "breach of contract" and "abandonment of contract" – Explained.		
धाराएं 67 एवं 73 – ''संविदा के भंग'' तथा ''संविदा के परित्याग'' के मध्य अंतर – व्याख्या की गई।	**231**	**264**
Section 73 – See sections 101 and 102 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 73 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 101 एवं 102।	**24**	**29**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
COPYRIGHT ACT, 1957		
प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957		
Sections 63 and 65 – Whether offence u/s 63 is cognizable and non-bailable? Held, Yes.		
धाराएं 63 एवं 65 – क्या धारा 63 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है? अभिनिर्धारित, हाँ।	**284**	**333**
COURT FEES ACT, 1870		
न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870		
Section 7(iv)(d) – Suit valuation for mandatory injunction.		
धारा 7 (iv)(घ) – आज्ञापक व्यादेश हेतु वाद का मूल्यांकन।	**232**	**265**
Section 35 – Exemption from payment of court fees – Notification not applicable to memo of appeal – Appeal against decree filed by two minor children through their guardian mother – Order of exemption, set aside.		
धारा 35 – न्याय शुल्क अदायगी से छूट – अधिसूचना अपील के ज्ञापन पर प्रयोज्य नहीं – डिक्री के विरूद्ध दो अवयस्क बच्चों ने अपनी संरक्षक माँ के माध्यम से अपील प्रस्तुत की – छूट का आदेश अपास्त।	**285* (i)**	**334**
CRIMINAL PRACTICE :		
आपराधिक प्रथा :		
– Contradiction – A prosecution case may be discredited on the basis of a completely contrary version between ocular and medical evidence.		
– विरोधाभास – चक्षुदर्शी एवं चिकित्सकीय साक्ष्य के मध्य पूर्णतः विपरीत वृत्तान्त वर्णन के आधार पर अभियोजन के प्रकरण को अविश्वसनीय माना जा सकता है।	**117**	**126**
– See Article 20(3) of the Constitution of India.		
– देखें भारत का संविधान का अनुच्छेद 20(3)।	**65**	**71**
– See section 32 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	**78**	**85**
– See sections 34, 302 and 307 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34, 302 एवं 307।	**76**	**82**
– See sections 134 and 154 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 134 एवं 154।	**244***	**280**
– See sections 136, 148 and 165 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 136, 148 एवं 165।	**26**	**31**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– See sections 148 and 302/149 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 148 एवं 302/149।	**131**	**146**
– See sections 346 and 364-A of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 346 एवं 364–क।	**80**	**88**
– See section 389 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389।	**17**	**18**
– See sections 376 and 511 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376 एवं 511।	**39**	**46**
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973		
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		
Sections 41 and 170 – Arrest – It is not obligatory for SHO to arrest the accused while filing charge-sheet when he has reasons to believe that accused will obey the summons and will not flee away – Such accused who cooperates with investigation should not be arrested in a routine manner.		
धाराएं 41 एवं 170 – गिरफ्तारी – थाने के भारसाधक अधिकारी के लिये अभियोग पत्र प्रस्तुति हेतु अभियुक्त को गिरफ्तार करना बाध्यकारी नहीं है जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त समन का पालन करेगा और भागेगा नहीं – ऐसा अभियुक्त जो अन्वेषण में सहयोग करता है, नियमित अनुक्रम में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।	**118**	**127**
Section 53-A – Effect of omission to carry out DNA profiling.		
धारा 53–क – डीएनए प्रोफाईलिंग करने में लोप का प्रभाव।	**251 (ii)**	**295**
Section 91 – Power to summon document – Can be invoked by a stakeholder at any stage – Accused cannot apply during investigation.		
धारा 91 – दस्तावेज आहूत करने की शक्ति – किसी भी स्तर पर हितधारकों द्वारा आव्हान किया जा सकता है – अभियुक्त अन्वेषण के स्तर पर ऐसा आवेदन नहीं कर सकता है।	**286**	**334**
Sections 91 and 311 – (i) Summoning nodal officer of Cellular Company – Power of Court is not constrained by closing of evidence. (ii) Whether court can order production of decoding register when it was not part of investigation? Held, yes.		
धाराएं 91 एवं 311 – (i) सेलुलर कंपनी के नोडल अधिकारी को समन – साक्ष्य के समाप्त होने से न्यायालय की शक्ति बाधित नहीं होती। (ii) क्या न्यायालय द्वारा डिकोडिंग रजिस्टर की प्रस्तुति का आदेश दिया जा सकता है, जहाँ वह जाँच का हिस्सा नहीं था – अभिनिर्धारित, हाँ।	**287**	**335**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Section 145 – Multiplicity of litigation – When a civil litigation is pending between the parties, parallel proceedings u/s 145 cannot be continued.

धारा 145 – मुकदमों की बाहुल्यता – जबकि पक्षकारों के मध्य दीवानी मुकदमेबाजी लंबित है तब धारा 145 के अंतर्गत समानांतर कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। **67** **73**

Sections 145 and 146(1) – Attachment – Attachment of crops of disputed land ordered by SDM – Civil suit pending between the parties – Relief can be sought from civil court – Order u/s 146 CrPC not proper unless urgency is shown.

धाराएं 145 एवं 146 (1) – कुर्की – अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा विवादित भूमि की उपज की कुर्की आदेश जारी किये गये – पक्षकारों के मध्य सिविल वाद लंबित था – सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है – जब तक की अत्यावश्यकता दर्शित नहीं होती है तब तक धारा 146 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पारित आदेश उचित नहीं। **288** **339**

Section 154 – Preliminary inquiry before registration of FIR – Can accused be granted a chance to explain his conduct at the time of inquiry?

धारा 154 – प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किए जाने के पूर्व प्रारम्भिक जांच – क्या ऐसी जांच के समय अभियुक्त को अपने आचरण का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है? **9** **12**

Sections 154 and 228 – (i) Matrimonial dispute – Delayed FIR – When not fatal.

(ii) Framing of charge – Roving and detailed enquiry at the stage of framing of charge – Not permissible.

धाराएं 154 एवं 228 – (i) वैवाहिक विवाद – विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट– कब घातक नहीं।

(ii) आरोप की विरचना – आरोपों की विरचना की अवस्था में अतिगामी और विस्तृत जांच – अनुज्ञेय नहीं। **174** **196**

Sections 156 and 157 – Investigation – Doctrine of fairness – An Investigation Officer being a public servant is expected to conduct the investigation fairly – Pliable change is required in the mind of Investigation Officer – Being an Officer of the Court, he should not take sides, either of the victim or the accused – Should be guided by law and be an epitome of fairness in his investigation.

धाराएं 156 एवं 157 – अन्वेषण – निष्पक्षता का सिद्धांत – अन्वेषण अधिकारी एक शासकीय कर्मचारी है जिससे निष्पक्ष अन्वेषण की अपेक्षा की जाती है – मानसिकता लचीली होनी चाहिए – न्यायालय का अधिकारी होने के कारण किसी एक पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए – विधि अनुरूप निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। **130 (i)** **144**

Section 161 – Recording of statement – Mere delay in recording the statement u/s 161 of CrPC is not sufficient to discard the evidence of witnesses outrightly.

धारा 161 – कथन का अभिलेखन – धारा 161 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन के अभिलेखन में विलम्ब मात्र साक्षी की साक्ष्य को सिरे से खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। **199 (ii)** **228**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 167 (2) – Default bail – Right of accused – Accrues only prior to filing of challan and does not survive or remain enforceable after challan is filed.		
धारा 167 (2) – व्यतिक्रम जमानत – अभियुक्त का अधिकार – केवल अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व प्राप्त होता है एवं अभियोग पत्र प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् प्रभावशील नहीं रहता।	**175**	**197**
Section 167(2)(a)(i) – Default bail – Period of filing of the charge sheet – Principles laid down in ***Rakesh Kumar Paul v. State of Assam, (2017) 15 SCC 67*** reiterated.		
धारा 167(2)(क)(i) – व्यतिक्रम जमानत – अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की अवधि – ***राकेश कुमार पॉल विरूद्ध आसाम राज्य, (2017) 15 एससीसी 67*** में प्रतिपादित सिद्धांत दोहराये गये।	**10***	**13**
Section 173 – Further investigation – Direction for further investigation can be given to ensure fair investigation.		
धारा 173 – अग्रिम अन्वेषण – निष्पष अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम अन्वेषण के लिए निर्देश दिया जा सकता है।	**11***	**13**
Sections 177 and 178 – See section 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 177 एवं 178 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498क।	**201***	**230**
Sections 184, 218, 220, 227, 300 and 461 – (i) Discharge – Alleged threats were not constituting such offence to form a series of acts with offence of rape – Accused is liable to be discharged for want of territorial jurisdiction.		
(ii) Segregation of charge – What is meant by same transaction? No universal formula can be applied – Purely a question fact.		
धाराएं 184, 218, 220, 227, 300 एवं 461 – (i) उन्मोचन – धमकी दिया जाना बलात्कार के अपराध के साथ की श्रृंखला का गठन नहीं कर रहा था – अभियुक्त क्षेत्राधिकार के अभाव में उन्मोचित किए जाने का पात्र है।		
(ii) आरोपों का पृथकीकरण – एक जैसे संव्यवहार से क्या आशय है? कोई सर्व सामान्य नियम लागू नहीं किया जा सकता – पूर्णतः तथ्य का प्रश्न है।	**289**	**339**
Section 188 – Jurisdiction – Sanction for prosecution – Offence committed partly in India – Victim was lured by accused for coming to India – Without any sanction, offence can be tried by courts of India.		
धारा 188 – क्षेत्राधिकार – अभियोजन की मंजूरी – अपराध आंशिक रूप से भारत में घटित किया गया – अभियोक्त्री को अभियुक्त द्वारा बहला–फुसलाकर भारत बुलाया गया – बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का विचारण भारत के न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।	**233**	**266**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 190 – Sanction for Prosecution – Proper stage for applicability is when competent court takes cognizance of the offence and not from any prior or posterior stage.		
धारा 190 – अभियोजन अनुमति – उचित स्तर वह है जब सक्षम न्यायालय अपराध का संज्ञान ले न कि उससे पूर्व या पष्चात् का स्तर।	**290**	**341**
Section 190(1)(b) – Cognizance – Whether a Magistrate taking cognizance of an offence on the basis of a police report in terms of section 190(1)(b) can issue summon to any person not arraigned as an accused in police report?		
धारा 190 (1)(ख) – संज्ञान – क्या मजिस्ट्रेट धारा 190 (1)(ख) दं.प्र.सं. के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध संज्ञान ले सकता है जिसे पुलिस रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में संयोजित न किया गया हो?	**234**	**267**
Section 200 – See sections 406, 420 and 120 (b) of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 200 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 406, 420 एवं 120(ख)।	**247**	**284**
Sections 200 and 204 – Issuance of process – Vicarious liability of Chairman, Managing Director, Managers or Planners of company – Specific allegations and/or averments against them with respect to their individual role in their capacity is a must.		
धाराएं 200 एवं 204 – आदेशिका जारी किया जाना–कंपनी के चेयरमेन, प्रबंध निदेशक, प्रबंधकों या योजनाकारों का प्रतिनिधिक दायित्व – उनकी पदीय क्षमता के अधीन व्यक्तिगत भूमिका के संबंध में उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट आक्षेप और/या अभिकथन आवश्यक है।	**12**	**14**
Sections 205, 273, 299, 353, 367 and 391 – See sections 30 and 33 of the Evidence Act, 1872		
धाराएं 205, 273, 299, 353, 367 एवं 391 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 30 एवं 33।	**176***	**199**
Sections 227 and 228 – (i) Framing of charge – Trial Court is not expected or supposed to hold mini trial.		
(ii) Post Mortem Report – Evidentiary value elaborated.		
(iii) Charge to be framed for higher offence – Prosecution case is necessarily limited by charge.		
धाराएं 227 एवं 228 – (i) आरोप की विरचना – न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं रहती है कि वह लघु विचारण करे।		
(ii) शव परीक्षण रिपोर्ट – साक्ष्य मूल्य विस्तार से बताए गए।		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(iii) उच्चतर अपराध के लिये आरोप तय किया जाना – अभियोजन मामला आवश्यक रूप से आरोप द्वारा सीमित है।	291	342
Sections 273 and 317 – (i) Dispensation from personal attendance – If personal attendance of an accused has been dispensed with, the evidence in the presence of his pleader can be taken on any condition which may be imposed by the Court. (ii) Examination of witness in absence of accused – Accused has given an under taking that their counsel would cross-examine the witness in their absence – Examination of witness in the absence of accused cannot be said to be violative of section 273 Cr.P.C.		
धाराएं 273 एवं 317 – (i) वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति – यदि अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान की गई है, तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली शर्त के अधीन, साक्ष्य अभिलिखित की जा सकती है। (ii) अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्षी का परीक्षण – अभियुक्त द्वारा अपने आवेदन में यह परिवचन दिया गया कि उसकी अनुपस्थिति में उसके अभिभाषक साक्षी का प्रतिपरीक्षण करेंगे – अभियुक्त की अनुपस्थिति में परीक्षण धारा 273 दं.प्र.सं. का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।	68*	74
Sections 304 and 374 – Criminal appeal – If accused does not appear through counsel appointed by him on the date of hearing, Court is obliged to appoint amicus curiae.		
धाराएं 304 एवं 374 – आपराधिक अपील – यदि अभियुक्त उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय को न्याय मित्र नियुक्त कर सुनवाई करनी चाहिये।	177*	199
Section 311 – (i) Determination of age – Duty of court. (ii) Summoning of witness by the court – Cannot be termed as a witness of any particular party – Court should give right of cross-examination to the complainant.		
धारा 311 – (i) आयु का निर्धारण – न्यायालय का कर्तव्य। (ii) न्यायालय द्वारा आहूत साक्षी – किसी पक्ष विशेष का साक्षी होना निरूपित नहीं किया जा सकता – न्यायालय को परिवादी को प्रतिपरीक्षण का अधिकार प्रदान करना चाहिए।	200	228
Section 313 – (i) Duty of court conducting the trial/appeal. (ii) Examination of accused – Admission – No conviction could be based on the statement of the accused recorded u/s 313 of the CrPC.		
धारा 313 – (i) विचारण/अपील का संचालन करने वाले न्यायालय का कर्त्तव्य। (ii) अभियुक्त की परीक्षा – स्वीकृति – अभियुक्त के केवल धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित कथन के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है।	235* (iii) & (iv)	271

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 319 – Summoning of accused – Exercise of discretion.		
धारा 319 – अभियुक्त को आहुत किया जाना–विवेकाधिकार का प्रयोग।	**236**	**272**
Section 319 – Summoning of new accused – Caution required.		
धारा 319 – नये अभियुक्त को समन करना – सतर्कता आवश्यक।	**13**	**15**
Section 320 – Compromise – The fact of compromise filed in a case related to non-compoundable offence can be considered while awarding sentence – While doing so, other aggravating and mitigating factors should also be considered.		
धारा 320 – समझौता – अशमनीय अपराध से संबंधित प्रकरण में समझौता प्रस्तुत होने के तथ्य पर दण्डादेश पारित करते समय विचार किया जा सकता है – ऐसा करते समय अन्य गुरूत्तरकारी एवं लघुत्तरकारी तथ्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए।	**14**	**16**
Section 357 (1)(b) – See Sections 138 and 143 Negotiable Instruments Act, 1881.		
धारा 357 (1)(ख) – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138 एवं 143।	**319**	**378**
Section 360 – Sentencing policy – Duty of court – Twin objective of sentencing is deterrence and correction – Inadequate and inappropriate sentence cannot be imposed only on the ground that long period has elapsed.		
धारा 360 – दण्डनीति– न्यायालय के कर्तव्य – दण्डादेश का आशय निवारण एवं सुधार है – केवल इस आधार पर कि लंबी अवधि व्यतीत हो चुकी है, अनुपयुक्त और अपर्याप्त दण्डादेश नहीं दिया जा सकता।	**252**	**300**
Section 374 – See section 460 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 374 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 460।	**40***	**48**
Section 378 – Appeal against acquittal – When can be interfered with by the appellate court?		
धारा 378 – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील – कब अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है?	**15***	**17**
Section 378 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 378 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	**307***	**362**
Sections 378 and 384 – Appeal against order of acquittal – When the testimony of witness is not believed on cogent reasoning, conviction cannot be based on an inference or mere surmise.		
धाराएं 378 एवं 384 – दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध अपील – साक्षी की अभिसाक्ष्य पर ठोस आधारों के बिना विश्वास नहीं किया जा सकता, दोषसिद्धी केवल अंदाजे या अनुमान के आधार पर नहीं की जा सकती।	**189**	**214**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 378 and 386 – Appeal against acquittal – Powers of Appellate Court – General principles summarized.		
धाराएं 378 एवं 386 – दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील – अपील न्यायालय की शक्तियां – सामान्य सिद्धांत संक्षेपित किए गए।	**178**	**200**
Section 386 – Retrial – When can be ordered?		
धारा 386 – पुनः विचारण – पुनः विचारण कब आदेशित किया जा सकता है ?	**16**	**17**
Section 389 – (i) Suspension of sentence – Factors to be considered.		
(ii) Suspension of sentence – Recording of reasons by Appellate Court – Held, is mandatory.		
(iii) Suspension of sentence – Maintainability of subsequent application.		
धारा 389 – (i) दण्डादेश का निलंबन – विचार किए जाने वाले कारक।		
(ii) दण्डादेश का निलंबन – अपीलीय न्यायालय द्वारा कारण लेखबद्ध किया जाना – अवधारित, आज्ञापक है।		
(iii) दण्डादेश का निलंबन – उत्तरवर्ती आवेदन की पोषणीयता।	**17**	**18**
Section 389 (1) – (i) Revocation of suspension of sentence – Accused was implicated in an offence u/s 302 IPC during the period when his sentence was suspended – Bail granted to the accused cancelled by the Supreme Court.		
(ii) Judicial independence – Judicial independence of the District Judiciary is cardinal to the integrity of the entire system – Apprehension expressed by the presiding officer should be duly enquired in order to secure fair administration of justice.		
धारा 389 (1) – (i) दण्डादेश के स्थगन का निरस्तीकरण – अभियुक्त दण्डादेश के निलंबन की अवधि के दौरान भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध में आलिप्त किया गया – अभियुक्त को प्रदान की गई जमानत उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त की गई।		
(ii) न्यायिक स्वतंत्रता – जिला न्यायपालिका की न्यायिक स्वतंत्रता समग्र व्यवस्था की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है – पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिव्यक्त आशंका की सम्यक् जांच की जानी चाहिए यदि वह सही पाई जाए तो न्याय के बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।	**69**	**75**
Section 436-A – Child in conflict with law – Cannot be treated as under-trial prisoner as contemplated u/s 436-A of CrPC.		
धारा 436–क – विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को धारा 436–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचाराधीन बन्दी नहीं माना जा सकता है।	**237***	**273**
Section 437 – See section 53 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 437 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 53।	**31**	**37**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 437(2) and 439(2) – Cancellation of bail – Reasons to be assigned.		
धाराएं 437(2) एवं 439(2) – जमानत का निरस्त किया जाना – कारण बताना चाहिए।	**238**	**273**
Sections 437 (5) and 439 (2) – Cancellation of bail.		
धाराएं 437 (5) एवं 439 (2) – जमानत का निरस्त किया जाना।	**18**	**20**
Sections 437(5) and 439(2) – Cancellation of bail – Effect when conduct of accused has evoked a *bona fide* fear in the mind of complainant.		
धाराएं 437(5) एवं 439(2) – जमानत का निरस्तीकरण – प्रभाव, जहाँ अभियुक्त का आचरण परिवादी के मस्तिष्क में सद्भाविक भय उत्पन्न करता है।	**292**	**344**
Section 438 – Anticipatory bail – Second bail application – Maintainability of – First bail application rejected on incorrect facts whereas subsequent bail filed on correct facts – Held, Court can reconsider such application as it would not amount to review or re-appreciation.		
धारा 438 – अग्रिम जमानत – द्वितीय जमानत आवेदन – पोषणीयता – प्रथम जमानत आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर अस्वीकार किया गया जबकि पश्चातवर्ती आवेदन सही तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया – अभिनिर्धारित, न्यायालय ऐसे आवेदन पर पुनर्विचार कर सकता है क्योंकि इसका परिणाम पुनर्विलोकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।	**119**	**128**
Section 438 – (i) Anticipatory bail – Whether a person who is declared as an absconder or proclaimed offender in terms of section 82 CrPC be granted relief of anticipatory bail? (ii) Anticipatory bail – Whether accusation arising out of business transaction is a factor to be considered while deciding anticipatory bail?		
धारा 438 – (i) अग्रिम जमानत – क्या द.प्र.सं. की धारा 82 के अधीन फरार अथवा उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है? (ii) अग्रिम जमानत – क्या अभियोग व्यापारिक लेनदेन से उत्पन्न हुआ है, इस तथ्य पर अग्रिम जमानत का निराकरण करते समय विचार किया जाना चाहिए?	**19**	**21**
Section 439 – Bail – Law of parity – While deciding bail on parity, court should also consider the allegations in FIR, role attributed to accused, likelihood to tamper the evidence if enlarged on bail, seriousness and gravity of the offence.		
धारा 439 – जमानत – समानता का आधार – समानता के आधार पर जमानत आवेदन के निराकरण के समय न्यायालय को अभियुक्त के द्वारा किया गया विशिष्ट कृत्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरूद्ध एकत्रित की गई साक्ष्य, जमानत पर छोड़े जाने की दशा में साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना, अपराध की गंभीरता को भी देखा जाना चाहिए।	**120***	**128**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 439 – Bail – While deciding bail application, possibility of the accused threatening, influencing the witness, gravity of offence and factum of previous enmity should be considered.		
धारा 439 – जमानत – जमानत आवेदन का विनिष्चय किये जाते समय अभियुक्त द्वारा साक्षी को धमकाने, प्रभावित करने की संभाव्यता, अपराध की गंभीरता, पूर्व वैमनस्यता होने का तथ्य को विचार में लिया जाना चाहिए।	**179**	**203**
Section 439 – Grant of bail – Factors to be considered.		
धारा 439 – जमानत प्रदान किया जाना – विचार में लिये जाने वाले तथ्य।	**293**	**345**
Section 439 – (i) Nature of victim's rights. (ii) Victim has a right to be heard.		
धारा 439 – (i) पीड़ित के अधिकार की प्रकृति। (ii) सुनवाई का अधिकार।	**239**	**275**
Section 439(2) – Cancellation of bail – Bail granted should not be cancelled in a mechanical manner – Requires cogent and overwhelming circumstances.		
धारा 439(2) – जमानत का निरस्त किया जाना – एक बार प्रदत्त जमानत को यांत्रिकी तरीके से निरस्त नहीं किया जाना चाहिए – प्रभावशाली एवं अभिभूत परिस्थितियाँ आवश्यक है।	**240**	**275**
Section 457 – Interim custody of vehicle – Information of confiscation – There was no communication of intimation by the confiscating authority to the Court which cannot be considered as compliance of section 47-A(3)(a) of the Act and bar u/s 47-D would not be attracted.		
धारा 457 – वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी – अधिहरण की सूचना – विचारण न्यायालय को अधिहरण प्राधिकारी द्वारा दी गई सूचना की कोई संसूचना नहीं थी जिसे धारा 47–क(3)(क) की पालना नहीं समझा जा सकता है और धारा 47–घ का वर्जन लागू नहीं होता है।	**70***	**78**
Section 464 – See sections 148, 149 and 302 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 32 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 464 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 148, 149 एवं 302 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	**248**	**288**
Sections 468 and 482 – Calculation of limitation for application u/s 12.		
धारा 468 एवं 482 – धारा 12 के आवेदन की परिसीमा गणना।	**266**	**314**
Section 482 – See sections 406, 419 and 420 of the Criminal Procedure Code, 1973		
धारा 482 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 406, 419 एवं 420।	**143**	**159**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CRIMINAL TRIAL :		
आपराधिक प्रथा :		
– See sections 9 and 60 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 9 एवं 60।	**181**	**204**
– See sections 136, 148 and 165 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 136, 148 एवं 165।	**26**	**31**
– See section 306 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 306।	**37**	**45**
DAKAITI AUR VYAPHARAN PRABHAVIT KSHETRA ADHINIYAM, 1981 (M.P.)		
डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (म.प्र.)		
Sections 11 and 13 – See sections 392 and 397 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 11 एवं 13 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 392 एवं 397।		
Section 13 – See sections 346 and 364-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 13 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 346 एवं 364–क।	**80**	**88**
DOWRY PROHIBITION ACT, 1961		
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961		
Section 3 – Definition of dowry – Demand of money for construction of house – Falls within the meaning of the word "dowry".		
धारा 3 – दहेज की परिभाषा – भवन निर्मित करने के लिये राशि की मांग – दहेज के अर्थ के अंतर्गत आयेगी।	**198 (iii)**	**226**
EMPLOYEES COMPENSATION ACT, 1923		
कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923		
Sections 2(1)(e), 3 and 4 – Total disablement – Effect of amputation of the right upper limb above wrist joint when appellant is not in a position to discharge his duty as a driver.		
धाराएं 2(1)(ड़), 3 एवं 4 – पूर्ण अशक्तता – कलाई जोड़ के दाहिने ऊपरी अंग के विच्छेद का प्रभाव जहाँ अपीलार्थी इस स्थिति में नहीं है कि वह चालक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।	**294**	**346**
Section 4-A – Assessment of interest – Whether interest is payable from the date of accident? Held, yes.		
धारा 4–क – ब्याज का निर्धारण – क्या ब्याज दुर्घटना दिनांक से भुगतान योग्य होगा? अभिनिर्धारित, हाँ।	**180***	**204**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

EVIDENCE ACT, 1872
साक्ष्य अधिनियम, 1872

Section 3 – Categories of oral testimony of eye-witnesses.

(ii) Reliance on sole testimony when informant eye-witness was not present at the time of incident.

धारा 3 – (i) चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा दी गई मौखिक साक्ष्य की श्रेणियाँ।

(ii) एकल साक्ष्य पर भरोसा जब घटना के समय सूचनाकर्ता चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद नहीं। **249** **290**

Section 3 – (i) Related witness – Evidence of witness cannot be discarded solely on the ground that they are the relatives of the deceased.

(ii) Material contradictions – Weightage should not be given to minor contradictions which are not material and does not affect the case of prosecution as a whole.

धारा 3 – (i) हितबद्ध साक्षी – साक्षी की साक्ष्य को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वे मृतक के रिश्तेदार है।

(ii) तात्विक विरोधाभास – ऐसे सूक्ष्म विरोधाभास को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो तात्विक नहीं है और अभियोजन के प्रकरण को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हों। **241*** **278**

Section 3 – See sections 34 and 300 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34 एवं 300। **190** **216**

Section 3 – See sections 34 and 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34 एवं 302। **30** **36**

Section 3 – See sections 96, 97, 149 and 302 of the Indian Penal Code, 1860 and Sections 156 and 157 of the Criminal Procedure Code, 1973

धारा 3 –देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 96, 97, 149 एवं 302 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 156 एवं 157। **130** **144**

Section 3 – See sections 300, Exception 4 and 304 Part II of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300, अपवाद 4 एवं 304 भाग–दो। **33*** **42**

Section 3 – See section 324 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 27 of the Arms Act, 1959.

धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 324 एवं आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27। **253** **301**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 3 – See section 304-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304–क।	**309**	**364**
Section 3 – (i) Testimony of eye witness – Where the ocular evidence of the eye witness is cogent, reliable and trustworthy, medical opinion pointing to alternative possibilities should not be accepted.		
(ii) Discrepancies in evidence – The evidence of witness should be read as a whole – On the basis of minor discrepancies, the evidence of witness cannot be rejected.		
धारा 3 – (i) चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य – जहां चक्षुदर्शी साक्षी की मौखिक साक्ष्य अकाट्य, भरोसेमंद तथा विश्वसनीय हो वैकल्पिक संभावनाओं को इंगित करने वाला चिकित्सीय अभिमत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।		
(ii) साक्ष्य में विसंगतियां – साक्षी की साक्ष्य को सम्पूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए – सूक्ष्म विसंगतियों के आधार पर साक्षी की साक्ष्य को नामंजूर नहीं किया जा सकता है।	**136**	**151**
Section 3, 8, 17 and 68 – (i) Will; admission of.		
(ii) Will – Suspicious circumstances.		
धाराएं 3, 8, 17 एवं 68 – (i) वसीयत की स्वीकृति।		
(ii) वसीयत – संदिग्ध परिस्थितियाँ।	**20**	**22**
Sections 3 and 9 – Identification of accused – When eye witnesses narrate the event without material discrepancies and attribute a specific role to the accused then non-conduction of test identification parade becomes immaterial.		
धाराएं 3 एवं 9 – अभियुक्त की पहचान – जब चक्षुदर्शी साक्षी किसी सारभूत विसंगति के बिना घटना का वर्णन करते हैं और अभियुक्त को किसी विशिष्ट भूमिका के लिये उत्तरदायी बताते हैं, तब चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा की गई सकारात्मक पहचान के प्रकाश में पहचान परेड नहीं कराया जाना सारहीन हो जाता है।	**71**	**79**
Sections 3, 15, 24 and 45 – (i) Circumstantial evidence and last seen theory.		
(ii) Evidentiary value of extra-judicial confession.		
धाराएं 3, 15, 24 एवं 45 – (i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत का अभिमूल्यन।		
(ii) न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य मूल्यांकन।	**250**	**292**
Sections 3 and 27 – See sections 53 and 394 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 27 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 53 एवं 394।	**129**	**142**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 3 and 32 – See sections 299 and 300 of the Indian Penal Code, 1860. **धाराएं 3 एवं 32** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 299 एवं 300।	**32**	**41**
Sections 3 and 106 – (i) Theory of last seen together – Once the theory is established, the accused is expected to offer some explanation as to under what circumstances, he had parted the company of the victim. (ii) Shifting of burden of proof on accused in view of Section 106 of the Evidence Act. **धाराएं 3 एवं 106** – (i) अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – एक बार जब सिद्धांत प्रमाणित कर दिया जाता है, अभियुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ स्पष्टीकरण दे कि किन परिस्थितियों में पीड़ित की संगत पथ्थक हुई। (ii) धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त पर सबूत के भार का परिवर्तन।	**235* (i) & (ii)**	**271**
Sections 3 and 113-B – (i) Dowry death – Pre-requisites to prove the offence – Enumerated. (ii) Words "soon before" is different from the phrase "immediately before". **धाराएं 3 एवं 113–ख** – (i) दहेज मृत्यु – अपराध साबित करने की पूर्व आवश्यकताएं – प्रगणित की गई। (ii) शब्द ''ठीक पूर्व'' ''तुरंत पूर्व'' से भिन्न है।	**198 (i) & (ii)**	**226**
Section 3 and 114-A – Presumption – The provision would not apply until and unless it is proved that the sexual intercourse was committed by the accused. **धाराएं 3 एवं 114–क** – उपधारणा – तब तक नहीं की जा सकती जब तक अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना प्रमाणित नहीं हो जाता।	**141 (ii)**	**157**
Sections 3 and 145 – (i) Contradiction in testimony of witnesses – Whether witnesses must be confronted by the defence to seek advantage of the contradictions? (ii) Inconsistency amongst witnesses as to the date of incident – Appreciation of. (iii) Rape and murder – Time of death. **धाराएं 3 एवं 145** – (i) साक्षियों की परिसाक्ष्य में विरोधाभास – क्या विरोधाभास का लाभ लेने के लिए बचाव पक्ष द्वारा साक्षियों का उससे सामना करना आवश्यक है? (ii) घटना की तिथि के बारे में साक्षियों के बीच असंगतता का मूल्यांकन। (iii) बलात्कार और हत्या – मृत्यु का समय।	**21**	**24**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 9 and 60 – Test identification parade – Could not by itself be relied upon to establish the identity of the assailants.		
धाराएं 9 एवं 60 – पहचान परेड – हमलावरों की पहचान स्थापित करने हेतु केवल इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।	**181**	**204**
Sections 15, 27 and 45 – (i) Expert opinion – Appreciation of. (ii) Circumstantial evidence – Dead body which was in a concealed condition is recovered from an unused and dilapidated building at the instance of accused – Recovery is a crucial evidence.		
धाराएं 15, 27 एवं 45 – (i) विशेषज्ञ की राय का अभिमूल्यन। (ii) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन के आधार पर अप्रयुक्त और जीर्णशीर्ण इमारत में गुप्त स्थान से शव बरामद किया गया – जप्ती महत्वपूर्ण साक्ष्य है।	**251 (i) & (iii)**	**295**
Section 21(1) – Multiple dying declarations – Reliability.		
धारा 21(1) – एकाधिक मृत्युकालीन कथन – विश्वसनीयता।	**295**	**347**
Section 27 – (i) Disclosure statement and resultant recovery – Appreciation of. (ii) Disclosure statement and resultant recovery – Factors affecting credibility of recovery enumerated.		
धारा 27 – (i) प्रकटन कथन और परिणामतः बरामदगी का मूल्यांकन। (ii) प्रकटन कथन और परिणामतः बरामदगी – बरामदगी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक रेखांकित किए गए।	**22**	**26**
Section 27 – (i) Nature and object – It is an exception to sections 24 to 26 – Theory of "confirmation by subsequent facts" facilitating connection to the chain of events. (ii) Burden of proof. (iii) Duty of the courts – Consciousness required in recording evidence of recovery u/s 27.		
धारा 27 – (i) प्रकृति और उद्देश्य – यह धारा 24 से 26 का अपवाद है – ''पश्चात्वर्ती तथ्य के द्वारा पुष्टि'' का सिद्धांत तथ्यों की श्रृंखला से संबंध सुगम करना है। (ii) सबूत का भार। (iii) न्यायालयों का कर्तव्य – धारा 27 के तहत बरामदगी संबंधी साक्ष्य लेने के समय सजग रहना आवश्यक।	**296**	**347**
Sections 30 and 33 – Statement of co-accused – Admissibility of.		
धाराएं 30 एवं 33 – सह अभियुक्त का कथन – ग्राह्यता।	**176***	**199**

Section 32 – (i) Dying declaration – Evaluation of – Under the Indian law, a dying declaration is relevant whether the person making it was or was not under the expectation of death at the time of declaration.

(ii) Dying declaration – Credibility of – General principle – When a party is at the point of death and every hope of world is gone, motive to falsehood is silenced and mind is induced by the most powerful consideration to speak only the truth – Weightage can be given to such dying declarations.

धारा 32 – (i) मृत्युकालिक कथन – मूल्यांकन – भारतीय विधि के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन सुसंगत है, भले ही मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति इसकी घोषणा के समय मृत्यु से आशंकित रहा हो अथवा नहीं।

(ii) मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – सामान्य सिद्धांत – जब एक पक्ष मृत्यु की कगार पर होता है और दुनिया की सारी उम्मीद समाप्त हो जाती है, तब झूठ का उद्देश्य शांत हो जाता है और सर्वशक्तिमान विचार मस्तिष्क को केवल सच बोलने के लिये प्रेरित करता है – इस तरह के मृत्युकालिक कथन को महत्व दिया जा सकता है। **121 129**

Section 32 – Dying declaration – Evidence of person who recorded it – No need to depose *verbatim* of the maker.

धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – अभिलिखित करने वाले की साक्ष्य – कथनकर्ता के अक्षरशः शब्दों के बयान की आवश्यकता नहीं होती। **135 (iii) 149**

Section 32 – (i) Dying declaration – Evidentiary value – Conviction can be recorded solely on the basis of a dying declaration or even on the basis of an oral dying declaration.

(ii) Multiple oral dying declarations – Reliability – Serious inconsistency and contradictions in the dying declaration which makes the second dying declaration doubtful.

(iii) Last seen theory – Last seen evidence is a weak piece of evidence and on the basis of this theory alone conviction cannot be affirmed.

धारा 32 – (i) मृत्युकालिक कथन – साक्ष्यिक मूल्य – केवल मृत्युकालिक कथन अथवा यहां तक कि मौखिक मृत्युकालिक कथन के आधार पर भी दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सकती है।

(ii) कई मौखिक मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – मृत्युकालिक कथन में गंभीर असंगतता एवं विरोधाभास दूसरे मृत्युकालिक कथन को संदेहास्पद बना देते हैं।

(iii) अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – अंतिम बार साथ देखे जाने की साक्ष्य दुर्बल प्रकृति की साक्ष्य है और केवल इस सिद्धांत के आधार पर दण्डादेश की संपुष्टि नहीं की जा सकती है। **78 85**

Section 32 – Reliability of dying declaration.

धारा 32 – मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता। **248 (ii) 288**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 32 – Dying declaration without corroboration & When to be believed? Principles summarized.		
धारा 32 – असंपुष्टिकारक मृत्युकालिक कथन कब विश्वसनीय? सिद्धांतों को संक्षेप में बताया गया।	**297**	**349**
Section 32 – Multiple dying declarations – If there was inconsistency between both of them, dying declaration recorded by higher officers like Magistrate can be relied upon.		
धारा 32 – एक से अधिक मृत्युकालिक कथन – यदि दोनों मृत्युकालिक कथन परस्पर असंगत हैं तो जिसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखा गया, उस पर विश्वास किया जाना चाहिये।	**298**	**350**
Section 32 (1) – Admissibility of dying declaration.		
धारा 32(1) – मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता।	**242**	**278**
Section 35 – Documentary evidence – Public documents should be given preference over private ones.		
धारा 35 – दस्तावेजी साक्ष्य – लोक दस्तावेज को प्राइवेट दस्तावेज पर वरीयता दी जानी चाहिए।	**145 (ii)**	**162**
Section 35 – See section 94 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.		
धारा 35 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94।	**182***	**206**
Sections 40 and 44 – See sections 34, 302, 341, 447, 504 and 506 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 40 एवं 44 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34, 302, 341, 447, 504 एवं 506।	**191**	**217**
Section 45 – Opinion of medical expert – Evidentiary value of.		
धारा 45 – चिकित्सीय विशेषज्ञ के अभिमत का साक्ष्यिक मूल्य।	**23***	**28**
Sections 63 and 65 (c) – Secondary evidence – Admissibility of – When photocopy of document can be admitted? Held, parties are required to lay factual foundation that alleged copy is true copy of the original – Possession of original and circumstances under which photocopies were prepared and compared with original – Mere production does not satisfy the condition u/s 63 – Benefit u/s 65 cannot be granted.		
धाराएं 63 एवं 65 (ग) –द्वितीयक साक्ष्य – ग्राह्यता – दस्तावेजों की छायाप्रति कब स्वीकार की जा सकती है? अभिनिर्धारित, इस आशय का वास्तविक आधार प्रस्तुत करना होगा कि कथित प्रति, असल दस्तावेज की सत्यप्रति है – दस्तावेज किसके आधिपत्य में था और किन परिस्थितियों में उसकी छायाप्रति तैयार की गई और असल से मिलान की गई इसके वास्तविक आधार बताना		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
आवश्यक है – केवल दस्तावेज को प्रस्तुत कर देने मात्र से धारा 63 की शर्ते पूर्ण नहीं होती और धारा 65 का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।	**122**	**131**
Sections 63, 65 and 76 – See section 7 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.		
धाराएं 63, 65 एवं 76 – देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7।	**53**	**60**
Sections 65-A and 65-B – (i) Electronic Evidence – Without certificate u/s 65-B, electronic evidence is not admissible.		
(ii) Circumstantial Evidence – Standard of proof.		
धाराएं 65–क एवं 65–ख – (i) इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य – धारा 65–ख के प्रमाण पत्र के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।		
(ii) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – प्रमाण का मानक।	**299**	**350**
Section 65-B – Electronic evidence – Certified copy of CCTV footage – Original not played in Court, only certified copy was played – Neither objection was raised during trial nor any request was made to play the original – Court can rely on the certified copy of CCTV footage.		
धारा 65–ख – इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य – सीसीटीव्ही फुटेज की प्रमाणित प्रतिलिपि – मूल फुटेज न्यायालय में नहीं दिखाया गया केवल सत्यापित फुटेज दिखाया गया – विचारण के दौरान न तो कोई आपत्ति उठाई गई और न ही मूल फुटेज दिखाने हेतु कोई निवेदन किया गया – न्यायालय सीसीटीव्ही फुटेज की प्रमाणित प्रति पर विश्वास कर सकता है।	**243***	**279**
Section 68 – See section 63 of the Succession Act, 1925 and Order 41 Rule 1 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 68 – देखें उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 नियम 1।	**123**	**132**
Sections 91 and 92 – Presumption – A conclusive presumption arises on the basis of written agreement between parties and their privies that their final intentions have been finalized – Any contradiction, variation, addition or subtraction from its terms is excluded by provision of Section 92.		
धाराएं 91 एवं 92 – उपधारणा – पक्षकारों एवम् उनके विश्वसनीय निजी लोगों के मध्य लिखित अनुबंध से यह निश्चयात्मक उपधारणा उत्पन्न होती है कि उनके अंतिम आशयों को अनुबंध के द्वारा अंतिम रूप दिया जा चुका है – धारा 92 के प्रावधान किसी भी विरोधाभास, रूपांतर, परिवर्धन या घटाव को अपवर्जित करते हैं।	**72**	**80**
Sections 101 and 102 – Deficiency in service – Burden of proof.		
धाराएं 101 एवं 102 – सेवा में कमी – सबूत का भार।	**24**	**29**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Sections 101 to 103 and 114 (g) – (i) Direction for DNA test – Where other evidence is available to prove or dispute the relationship, the Court should refrain from ordering DNA test.

(ii) Adverse inference – Despite an order passed by the Court, if a person refuses to submit himself to such medical examination, it is a strong case for drawing an adverse inference.

(iii) Burden of proof – The burden on a litigating party to prove his case adducing evidence in support of his plea – Court should not compel the party to prove his case in the manner suggested by the contesting party.

(iv) Personal liberty – Forcing the plaintiff to undergo DNA test when he is unwilling to do so would impinge on his personal liberty and right to privacy.

धाराएं 101 से 103 एवं 114 (छ) – (i) डीएनए परीक्षण के लिए निर्देश – जहां सम्बंध को साबित करने या विवादित करने के लिए अन्य साक्ष्य उपलब्ध है, वहाँ न्यायालय को डीएनए परीक्षण का आदेश देने से बचना चाहिए।

(ii) प्रतिकूल निष्कर्ष – न्यायालय द्वारा आदेश करने के बावजूद, कोई व्यक्ति खुद को ऐसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से इंकार करता है, तो यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए एक मजबूत मामला है।

(iii) सबूत का भार – मुकदमा करने वाले पक्ष पर यह भार होता है कि वह अपने मामले को साबित करने के लिए अपने अभिवचन के समर्थन में साक्ष्य पेश करे न्यायालय को उस पक्षकार को अपने मामले को उस तरीके से साबित करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, जैसा कि विरोधी पक्ष द्वारा सुझाया गया है।

(iv) व्यक्तिगत स्वतंत्रता – वादी को डी.एन.ए. परीक्षण के लिये तब बाध्य करना जबकि वह ऐसा न करना चाहता हो उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं निजता के अधिकार का अतिलंघन है।

73* **80**

Sections 101 and 106 – Burden of proof of facts especially within knowledge – Applicability of section 106 of the Evidence Act.

धाराएं 101 एवं 106 – विशेष रूप से ज्ञान के तथ्यों के सबूत का भार – साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता। **25** **30**

Section 105 – See sections 96, 105 and 300 Exception 2 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 105 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 96, 105 एवं 300 अपवाद 2।

303 **358**

Section 106 – Circumstantial evidence – Section 106 of the Act does not relieve the duty of the prosecution to prove the chain of circumstances.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 106 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अधिनियम की धारा 106 अभियोजन को परिस्थितियों की कड़ियों को साबित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करती।	**197**	**225**
Section 110 – See Section 32 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 110 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 32।	**322**	**386**
Section 113-B – See Sections 120-B, 304-B and 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 113–ख – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120–ख, 304–ख एवं 498–क।	**304**	**359**
Section 114 – Partition suit – When presumption in favour of wedlock can be taken u/s 114 of the Evidence Act?		
धारा 114 – बंटवारे के दावा में कब विवाह बंधन के पक्ष में उपधारणा धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है?	**228 (i)**	**258**
Section 114 (III) (g) – See Consumer Protection Act, 1986.		
धारा 114 (III) (g) – देखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986।	**283**	**332**
Section 118 – Child witness – Factors to be considered while recording evidence of child witness – Enumerated.		
धारा 118 – बाल साक्षी – बाल साक्षी की साक्ष्य का अभिलेखन करते समय विचारण योग्य तथ्य – प्रगणित किये गए।	**124**	**134**
Sections 118 and 134 – If the version of a single witness and conduct of witnesses is found reliable by the Court, can be the foundation of conviction.		
धाराएं 118 एवं 134 – यदि न्यायालय द्वारा एक मात्र साक्षी का अभिकथन और साक्षीगण का आचरण विश्वसनीय पाया जाये, दोषसिद्धी का आधार हो सकता है।	**193**	**221**
Sections 134 and 154 – (i) Hostile witness – Conviction can be based on credible evidence of hostile witness.		
(ii) Evidentiary value – Contradiction and omission – Court should examine the statement of a witness in its entirety and read with the statement of other witnesses in order to arrive at a rational conclusion.		
धाराएं 134 एवं 154 – (i) पक्षद्रोही साक्षी – पक्षद्रोही साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि आधारित हो सकती है।		
(ii) साक्ष्यिक मूल्य – विरोधाभास एवं लोप – युक्तिसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु न्यायालय को साक्षी के बयान को पूर्णता से एवं अन्य साक्षियों के कथनों के आलोक में परीक्षण करना चाहिए।	**244***	**280**
Sections 136, 148 and 165 – (i) Objections during recording of evidence – When to be decided? What course may be adopted to curtail repeated objections? Practice mandated in ***Bipin Shantilal Panchal v. State of Gujarat, (2001) 3 SCC 1*** modified.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) Criminal trial – Procedure of investigation, bail, trial, recording of evidence and judgment – Directions issued – Draft Rules of Criminal Practice, 2021 approved.		
धाराएं 136, 148 एवं 165 – (i) साक्ष्य लेख करने के दौरान की गई आपत्तियां – कब निराकृत की जानी चाहिए? – बार–बार की जाने वाली आपत्तियों को कम करने के लिए कौन से मार्ग अपनाये जा सकते हैं? – ***बिपिन शांति लाल पांचाल वि. गुजरात राज्य, (2001) 3 एससीसी 1*** में प्रतिपादित प्रथा उपांतरित की गई।		
(ii) आपराधिक विचारण – अन्वेषण, जमानत, विचारण, साक्ष्य अभिलेखन एवं निर्णय की प्रक्रिया – निर्देश जारी किए गए – ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2021 अनुमोदित किए गए।	**26**	**31**
EXCISE ACT, 1915 (M.P.)		
आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.)		
Sections 47-A and 47-D – See Section 457 of the Criminal Procedure Code, 1973		
धाराएं 47–क एवं 47–घ – देखें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457।	**70***	**78**
FAMILY COURTS ACT, 1984		
कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984		
Section 7(1) Explanation (b) – Jurisdiction – Family court is having jurisdiction to decide the gravity of the offence alleged in criminal complaint.		
धारा 7(1) स्पष्टीकरण (ख) – क्षेत्राधिकार – परिवार न्यायालय को आपराधिक परिवाद में आक्षेपित अपराध की गंभीरता के संबंध में विनिश्चय करने का क्षेत्राधिकार है।	**183**	**206**
Section 19 – See section 13(1)(i-a) of the Hindu Marriage Act, 1955.		
धारा 19 – देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a)।	**246**	**282**
Section 19 – See Order 9 Rule 13 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 19 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 9 नियम 13।	**300**	**352**
GOVANSH VADH PRATISHEDH ACT, 2004 (M.P.)		
गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (म.प्र.)		
Section 11(5) – See Rule 5 of the M.P. Govansh Vadh Pratishedh Rules, 2012.		
धारा 11(5) – देखें मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012।	**263**	**311**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
GOVANSH VADH PRATISHEDH RULES, 2012 (M.P.)		
गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 (म.प्र.)		
Rule 5 – Confiscation proceedings – Effect of acquittal.		
नियम 5 – अधिहरण की कार्यवाही – दोषमुक्ति का प्रभाव।	**263**	**311**
GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890		
संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890		
Section 9 – (i) Territorial jurisdiction – Meaning of "ordinarily resides".		
(ii) Custody of minor aged 3 years – Is expected to be in the custody of his mother.		
धारा 9 – (i) क्षेत्रीय अधिकारिता – ''साधारण निवास'' स्थान की परिभाषा।		
(ii) अभिरक्षा – तीन वर्षीय अवयस्क का उसकी मां की अभिरक्षा में होना अपेक्षित है।	**245**	**280**
HINDU LAW :		
हिन्दू विधि :		
– Partition and reunion.		
– विभाजन एवं पुनर्मिलन।	**27**	**33**
– See sections 6 and 8 of the Hindu Succession Act, 1956.		
– देखें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धाराएं 6 एवं 8।	**125**	**135**
– (i) Hindu Law – Whether occupancy right is inheritable? Held, yes.		
– (ii) First Appellate Court – Duties and powers – Summarised.		
– (i) हिन्दू विधि – क्या मौरूसी अधिकार विरासत में दिये जा सकते है? अभिनिर्धारित, हाँ।		
– (ii) प्रथम अपीलीय न्यायालय – अधिकार एवं दायित्व – संक्षेपित किए गए।	**301**	**353**
HINDU MARRIAGE ACT, 1955		
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955		
Section 5 – Valid marriage – The ritual of *Saptpadi* is mandatory.		
धारा 5 – वैध विवाह – सप्तपदी संस्कार अनिवार्य है।	**28**	**34**
Sections 5 and 11 – (i) Void marriage – If either party has a spouse living at the time of the marriage and if such marriage is solemnized after the commencement of the Act of 1955, the same is void ipso-jure – The fact that the other party had the knowledge of the existing spouse living at the time of marriage, is immaterial.		
(ii) Child marriage – Child marriage is neither void nor voidable – The only consequence of contravention of section 5 (iii) is prescribed u/s 18 where the contravention of such condition is made punishable.		

धाराएं 5 एवं 11– (i) शून्य विवाह – यदि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का कोई जीवित पति/पत्नी है और ऐसा विवाह अधिनियम 1955 के प्रारम्भ के पश्चात् सम्पन्न हुआ है तो वह वैधानिक रूप से शून्य है – यह तथ्य कि विवाह के समय दूसरे पक्ष को जीवित पति/पत्नी के होने की जानकारी थी, महत्वहीन है।

(ii) बाल विवाह – बाल विवाह न तो शून्य है और न ही शून्य करणीय – धारा 5 (iii) के उल्लंघन का एकमात्र परिणाम धारा 18 में उल्लेखित है, जहाँ ऐसी शर्त के उल्लंघन को दण्डनीय बनाया गया है। **126** **139**

Section 9 – Restitution of conjugal rights – Wife did not want to live with the husband as she was not comfortable in joint family – Husband satisfactorily proved reasonable excuse to withdraw from the company of the wife.

धारा 9 – दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन – पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे संयुक्त परिवार में सुखद महसूस नहीं होता था – पति ने पत्नी द्वारा साहचर्य से खुद को प्रत्याहृत करने का युक्तियुक्त प्रतिहेतु संतोषप्रद रूप से प्रमाणित किया है। **74*** **81**

Section 13(1)(i-a) – Divorce – Mental cruelty – Long standing dispute itself is mental cruelty.

धारा 13(1)(i-a) – विवाह विच्छेद – मानसिक क्रूरता – लंबे समय तक स्थायी विवाद अपने आप में मानसिक क्रूरता है। **246** **282**

Section 13(1)(ib) – Matrimonial relationship – Resumption of cohabitation – Merely on account of the death of the husband's mother, the wife visited her matrimonial home and stayed there for only one day, it cannot be said that there was a resumption of cohabitation.

धारा 13 (1)(ib) – वैवाहिक सम्बन्ध – सहवास का पुनर्स्थापन – केवल इस कारण से कि पति की माँ की मृत्यु होने पर पत्नी ने उसके वैवाहिक निवास का भ्रमण किया और केवल एक दिन रूकी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सहवास का पुनर्स्थापन था। **184** **207**

Section 13 (1) (i-a) (i-b) – Divorce – Irretrievable breakdown – A decree for divorce may be passed by the Court on the basis of irretrievable breakdown of marriage but even after that the husband must be held liable and responsible to maintain his minor son unless he becomes major – A child should not be left to suffer because of any dispute between the parents.

धारा 13 (1) (i–क) (i–ख) – विवाह विच्छेद – अपूर्णीय विघटन – न्यायालय द्वारा विवाह के अपूर्णीय विघटन के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित की जा सकती है परन्तु ऐसा होने के पश्चात भी पति को उसके अवयस्क पुत्र के भरण पोषण के लिये तब तक उत्तरदायी एवं जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा पुत्र वयस्क नहीं हो जाता है – माता–पिता के मध्य के किसी विवाद के कारण बालक को परेशान होने के लिये नहीं छोड़ना चाहिए। **127** **141**

Sections 13(1) (ia) and 13(1)(ib) – (i) Cruelty – Proof of – Mental cruelty is difficult to establish by direct evidence unlike physical cruelty – Inference can be drawn from the facts and circumstances of the case taken cumulatively.

(ii) Divorce – Irretrievable break down – Not a ground for divorce but can be taken into consideration.

धाराएं 13(1)(ik) एवं 13(1)(ख) – (i) क्रूरता – सबूत – शारीरिक क्रूरता के विपरीत मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष सबूत द्वारा स्थापित किया जाना कठिन है – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को संचयी रूप से विचार में लेकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

(ii) विवाह विच्छेद – अपूरणीय भग्नता – विवाह विच्छेद का आधार नहीं है किंतु विचार में लिया जा सकता है। **185 208**

Section 13-B(2) – Divorce by mutual consent – Waiving of cooling period – Provisions are directory and not mandatory – If court is satisfied that a case is made out to waive the statutory period, it can do so.

धारा 13–ख(2) – परस्पर सहमति से विवाह–विच्छेद – उपशमन अवधि का अधित्याग – प्रावधान निदेशात्मक है न कि आज्ञापक – यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि विधिक अवधि के अधित्याग का मामला बनता है तब वह ऐसा कर सकता है। **75* 82**

Sections 25 (1) and 25 (3) – Permanent alimony and maintenance – Conduct of wife is relevant only while verifying, modifying or rescinding an order and not at the time of passing of initial order.

धाराएं 25 (1) एवं 25 (3) – स्थाई गुजारा भत्ता तथा भरण पोषण – पत्नी का आचरण केवल किसी आदेश को परिवर्तित करने, बदलने या रद्द करने के दौरान विचार में लिया जा सकता है न कि आरंभिक आदेश करते समय। **128 142**

HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP ACT, 1956
हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956

Sections 6 and 13 – (i) Custody of child – Consideration of well being and welfare of the child must get precedence over individual or personal rights of the parents.

(ii) Direction by court – In custody petition, court cannot direct a parent to leave the country and go abroad with the child as it will affect the right to privacy of the parent.

धाराएं 6 एवं 13 – (i) बालक की अभिरक्षा – बालक के सुख तथा कल्याण के विचार को माता–पिता के व्यक्तिगत या निजी अधिकारों पर वरीयता मिलनी चाहिए।

(ii) न्यायालय द्वारा निर्देश – अभिरक्षा की याचिका में न्यायालय माता या पिता को देश छोड़ने तथा बालक के साथ विदेश जाने का निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि यह माता–पिता के निजता के अधिकार को प्रभावित करेगा। **186* 209**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

HINDU SUCCESSION ACT, 1956
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

Sections 6 and 8 – Self-acquired and coparcenary property – Devolution of interest – When the son as heir of Class I of the Schedule inherits the property, does he do so in his individual capacity or as karta of his undivided family? Held, the property devolved on a Hindu u/s 8 of the Act would not be the HUF property (***Commissioner of Wealth-tax, Kanpur v. Chander Sen, AIR 1986 SC 1753*** relied on) – Further held, where the property in question was self-acquired property, section 6 has no application – Share in such property would devolve according to section 8, that too among the heirs of Class I equally.

धाराएं 6 एवं 8 – स्वअर्जित एवं सहदायिकी संपत्ति – हित का न्यागमन – जब अनुसूची के वर्ग–1 के उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र ने संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की, तब क्या वह व्यक्तिगत या उसके अविभाजित परिवार के कर्ता की हैसियत में प्राप्त करता है ? अभिनिर्धारित – धारा 8 के अधीन एक हिन्दू को न्यागमत संपत्ति हिन्दू अविभाजित परिवार की नहीं होगी (***कमीशन ऑफ वेल्थ टेक्स, कानपुर विरूद्ध चंदर सेन, एआईआर 1986 सु.को. 1753*** अनुसरित) आगे अभिनिर्धारित – जहाँ वादग्रस्त संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति है वहाँ धारा 6 प्रयोज्य नहीं है – ऐसी संपत्ति में अंश धारा 8 के अनुसार यानि वर्ग–1 के उत्तराधिकारियों को बराबर न्यागमत होगा। **125 135**

Section 14 – Hindu female – Creation of restricted estate – Legally permissible if the document creates independent and new title in favour of a female and not as a recognition of pre-existing right.

धारा 14 – हिन्दू महिला – संपत्ति का सीमित उपभोग – विधितः अनुमत यदि दस्तावेज स्वतंत्र और नवीन स्वत्व महिला को प्रदान करता है न कि पूर्व अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। **187 (i) 209**

Sections 14 and 15 – (i) Right of daughter – Male Hindu dying intestate – If property is self-acquired or obtained in partition of a co-parcenery or a family property, the same would devolve by inheritance and not by survivorship – Daughter of such male Hindu entitled to inherit such property in preference to other collaterals.

(ii) Death of female Hindu – Female Hindu dying issueless and intestate – Property inherited from her father or mother would go to the heirs of her father whereas property inherited from her husband or father-in-law would go to the heirs of the husband.

(iii) Section 15(1)(a) of the Act – Operation of – Comes into operation when the female Hindu dies leaving behind her husband or any issue – Properties left behind including the properties which she inherited from her parents would devolve simultaneously upon her husband and her issues as provided in Section 15(1)(a) of the Act.

धाराएं 14 एवं 15 – (i) पुत्री का अधिकार – यदि निर्वसीयती मृत हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति है या सहदायिकी सम्पत्ति या पारिवारिक सम्पत्ति में विभाजन के द्वारा प्राप्त की गई है ऐसी सम्पत्ति उत्तराधिकार के द्वारा न्यागत होगी न कि उत्तरजीविता के द्वारा – ऐसे

हिन्दू पुरूष की पुत्री उक्त सम्पत्ति को अन्य सगोत्रीय पर वरीयता में उत्तराधिकार में प्राप्त करने की हकदार होगी।

(ii) हिन्दू महिला की मृत्यु – यदि हिन्दू महिला की मृत्यु निर्वसीयती एवं संतान विहीन होती है तब ऐसी सम्पत्ति जो उसे उत्तराधिकार में अपने पिता या माता से प्राप्त हुई है उसके पिता के वारिसों को जाएगी और जो उसे अपने पति या ससुर से प्राप्त हुई है तब वह उसके पति के वारिसों को जाएगी।

(iii) अधिनियम की धारा 15(1)(क) – प्रवर्तन – यदि हिन्दू महिला की मृत्यु अपने पीछे पति तथा संतान को छोड़कर हुई है तब अधिनियम की धारा 15(1)(क) प्रवर्तन में आयेगी और अपने माता–पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति सहित उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियां धारा 15(1)(क) में उल्लेखित अनुसार उसके पति और संतान को एक साथ न्यागत होगी।

188 211

Section 14(1) – Hindu lady – Effect of Hindu widow found in exclusive settled legal possession of HUF property in light of Section 14(1) of the Act.

धारा 14(1) – हिन्दू महिला – हिन्दू विधवा महिला के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति पर अनन्य रूप से सुस्थापित वैध कब्जे में पाए जाने पर धारा 14 (1) के आलोक में प्रभाव।

302 355

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

Sections 34, 120B and 302 – See sections 378 and 384 of the Criminal Procedure Code, 1860

धाराएं 34, 120ख एवं 302 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 378 एवं 384।

189 214

Sections 34, 149, 302 and 307 – (i) Appreciation of evidence – Difference between "related witness" and "interested witness" explained.

(ii) Number of witnesses – Quality of witnesses should be considered not quantity of witnesses.

(iii) Maxim "falsus in uno falsus in omnibus" has no application in India.

(iv) Minor omissions, contradictions, embellishment in the evidence of the prosecution witness would not make them unreliable.

(v) Evidence of Police personnel.

(vi) Framing of charge – Charge u/s 149 of the IPC has been framed and if it is found that some of the accused persons were not guilty and some of the accused had participated in the occurrence and were sharing common intention.

धाराएं 34, 149, 302, एवं 307 – (i) साक्ष्य की विवेचना – ''संबंधी साक्षी'' एवं ''हितबद्ध साक्षी'' के बीच अन्तर समझाया गया।

(ii) साक्षियों की संख्या – साक्ष्य की गुणवत्ता पर विचार किया जाना चाहिए न कि साक्षियों की संख्या पर।

(iii) सूक्ति ''एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या'' की भारत में कोई प्रयोज्यता नहीं है।

(iv) अभियोजन पक्ष के साक्षी की साक्ष्य में अल्प लोप, विरोधाभास, अलंकृति उन्हें अविश्वनीय नहीं बनाती है।

(v) पुलिसकर्मी की साक्ष्य।

(vi) आरोप का निर्धारण – भा.दं.सं. की धारा 149 के अंतर्गत आरोपित किया गया है और यदि यह पाया जाता है कि कुछ अभियुक्तगण दोषी नहीं थे और कुछ अभियुक्तगण ने घटना में भाग लिया था और समान मंतव्य साझा कर रहे थे। **29*** **35**

Sections 34, 294, 323, 498A and 506 – See sections 154 and 228 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 34, 294, 323, 498क एवं 506 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154 एवं 228। **174** **196**

Sections 34 and 300 – Murder – Determination of common intention.

धाराएं 34 एवं 300 – हत्या – सामान्य आशय का निर्धारण। **190** **216**

Sections 34 and 302 – Common intention; proof of.

धाराएं 34 एवं 302 – सामान्य आशय का साबित किया जाना। **30** **36**

Sections 34, 302 and 307 – (i) Proof beyond reasonable doubt – First Information Report was lodged within half an hour from the time of incident – Eye witness remained unshaken – Medical report of injured and post mortem report of deceased also support the statement – Proved beyond any reasonable doubt that the accused has committed the murder and attempt to murder.

(ii) Common intention – Participation of accused in the crime with co-accused with common intention and pre-arranged plan not proved.

धाराएं 34, 302 एवं 307 – (i) युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना – घटना घटित होने से आधे घंटे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रतिपरीक्षण के दौरान स्थिर बने रहे, आहत व्यक्ति का चिकित्सा प्रतिवेदन एवं मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट भी कथनों का समर्थन करती है – युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है कि अभियुक्त ने हत्या एवं हत्या का प्रयास किया।

(ii) सामान्य आशय – अभियोजन का मामला ऐसा नहीं है कि इस अभियुक्त ने किसी भी तरीके से मृतक को अथवा आहत को उपहति कारित करने में भागीदारी की – अभियुक्त का सह–अभियुक्त के साथ सामान्य आशय एवं पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर भागीदारी प्रमाणित नहीं की गई। **76 82**

Sections 34, 302, 341, 447, 504 and 506 – (i) Common intention – Is necessarily a psycological fact as it requires pre-meeting of minds – Common intention should not be confused with "intention" or *''mens-rea''*.

(ii) Criminal Act – Is different from "offence".

(iii) Act in furtherance – Criminal offence is distinctly remote and unconnected with the common intention – Section 34 would not be applicable.

धाराएं 34, 302, 341, 447, 504 एवं 506 – (i) सामान्य आशय – एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है क्योंकि इसमें मस्तिष्क का पूर्व मिलन आवश्यक है – सामान्य आशय के संबंध में ''आशय'' या ''दुराशय'' से भ्रमित नहीं होना चाहिए।

(ii) आपराधिक कृत्य – अपराध से भिन्न है।

(iii) अग्रसरण में किया गया कार्य – आपराधिक कृत्य साफ तौर पर दूरस्थ एवं असंबंधित होने की दशा में उसे धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता। **191 217**

Section 53 – (i) Life imprisonment – A sentence for imprisonment of life will run for the entire life unless the remission is granted in accordance with law.

(ii) Power of remission of sentence.

धारा 53 – (i) आजीवन कारावास – आजीवन कारावास का दण्ड सम्पूर्ण जीवन तक चलेगा जब तक कि विधि अनुसार परिहार नहीं किया जाता।

(ii) दण्ड का परिहार करने की शक्ति। **31 37**

Sections 53 and 394 – Constructive/vicarious liability – In furtherance of common intention – Co-accused named in FIR – No specific role attributed – Recovery of small amount of cash remained unidentified – Complainant refused to identify accused in Court named in FIR on the basis of disclosure statement of hostile witness.

धाराएं 53 एवं 394 – आन्वयियक दायित्व/प्रतिनिधिक दायित्व – सामान्य आशय के अग्रसरण में – सहअभियुक्त के नाम का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख – विशिष्ट कृत्य स्पष्ट नहीं – अल्प मात्रा में बरामद नगद राशि की पहचान नहीं हुई – फरियादी ने भी न्यायालय में अभियुक्त को नहीं पहचाना – प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम पक्षविरोधी साक्षीगण के प्रकटन कथनों के आधार पर लिखा गया। **129 (ii) 142**

Sections 84, 302 and 304 Part I – (i) Unsoundness of mind – A person at the time of doing the act is either incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law.

(ii) Last seen together theory – If the time gap between last seen together and the death of the deceased is of few minutes – Principle applied.

(iii) Culpable homicide not amounting to murder – Expert stated that the patients of psychosis are not in a position to understand as to what is correct or what is wrong – The accused was a complete stranger – He had no grudge against the deceased or his family members – No motive proved – Held, the act of the accused would fall u/s 304 Part I of IPC and not under Section 302 of IPC

धाराएं 84, 302 एवं 304 भाग–1– (i) मस्तिष्क की विकृतचित्तता – कृत्य कारित करते समय व्यक्ति या तो कार्य की प्रकृति अथवा यह कि वह जो कर रहा है या तो गलत है या विधि के विरूद्ध है समझने में असमर्थ हो।

(ii) अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – यदि अंतिम बार साथ देखे जाने और मृतक की मृत्यु के बीच कुछ क्षणों का समय अंतराल हो – सिद्धांत प्रयोज्य।

(iii) आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है – विषेशज्ञों के कथनानुसार साइकोसिस के रोगी इस स्थिति में नहीं होते कि वे समझ सकें कि क्या सही और क्या गलत है – अभियुक्त पूर्णतः अजनबी था – उसकी मृतक अथवा उसके पारिवारिक सदस्यों से कोई वैमनस्यता नहीं थी – हेतुक प्रमाणित नहीं किया गया – अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त का कृत्य भा.दं.सं. की धारा 304 के भाग 1 अंतर्गत होगा न कि भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत।

192 219

Sections 96, 97, 149 and 302 – Right of private defence – Onus to prove – Initial burden to discharge is on accused, the extent of evidence is that of preponderance of probabilities and thereafter onus shifts to State – Two questions alone to be answered, whether defence coming under preview of sections 96 to 102 IPC or whether the right of self defence has exceeded?

Common object – Deeming fiction – Offence committed by one member of unlawful assembly to the others having common object – Mere presence in an assembly would not constitute an offence – Courts to be more circumspect and cautious while dealing with a case u/s 149 IPC – Higher degree of onus is on the prosecution to prove the case u/s 149.

Inseparable discrepancies – Material discrepancies shaking the very credibility, leading to a conclusion in the mind of the Court that it is neither possible to separate it nor to rely upon – It is for the Court to either accept or reject it.

धाराएं 96, 97, 149 एवं 302 – प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार – प्रारंभिक प्रमाण भार अभियुक्त पर होता है जो संभावनाओं की प्रबलता की सीमा तक उन्मोचित करना होता है जिसके बाद प्रमाण भार राज्य पर आ जाता है – केवल दो प्रश्नों का उत्तर आवश्यक है, क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा धारा 96 से धारा 102 भा.दं.सं. के अंतर्गत आती है और क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया गया।

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
सामान्य उद्देश्य – उचित कल्पना – विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया गया कार्य – केवल घटना स्थल पर उपस्थित होना अपराध गठित करने के लिये पर्याप्त नहीं – न्यायालय को धारा 149 भा.दं.सं. के मामले में सतर्क और चौकन्ना रहकर कार्य करना चाहिए – धारा 149 भा.दं.सं. को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पर उच्च श्रेणी का प्रमाण भार रहता है।		
अपृथक्करणीय विसंगतियाँ – तात्विक विरोधाभास जो साक्षी के कथनों को संदेहास्पद बनाते हों एवं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, न्यायालय को स्वविवेक से तय करना है कि उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करे।	**130 (ii), (iii) & (v)**	**144**
Sections 96, 105 and 300 Exception 2 – Right of private defence – Defensive right available only when circumstances justified.		
धाराएं 96, 105 एवं 300 अपवाद 2 – निजी प्रतिरक्षा का अधिकार – बचाव का अधिकार केवल तभी उपलब्ध है जब परिस्थितियाँ न्यायोचित ठहराये।	**303**	**358**
Sections 120B, 201, 302 and 364 – See Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 120ख, 201, 302 एवं 364 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	**120***	**128**
Sections 120-B, 304-B and 498-A – Dowry death – Neither specific role nor any specific instance of cruelty of harassment by in-laws – Only husband held guilty.		
धाराएं 120–ख, 304–ख एवं 498–क – दहेज हत्या – सास–ससुर द्वारा प्रताड़ित किये जाने में ना तो कोई विनिर्दिष्ट भूमिका और ना ही विनिर्दिष्ट घटना – केवल पति की दोषसिद्धि उचित है।	**304**	**359**
Sections 120 (b), 406 and 420 – (i) Criminal breach of trust, cheating and criminal conspiracy – Distinction between 'mere breach of contract' and 'cheating' – Explained. (ii) Multiple complaints – Two complaints cannot be filed on the same cause of action at different places.		
धाराएं 120(ख), 406 एवं 420 – (i) आपराधिक न्यासभंग, छल एवं आपराधिक षडयंत्र – संविदा के भंग तथा छल के बीच का अंतर – स्पष्ट किया गया। (ii) बहुविध परिवाद – दो परिवाद एक ही वाद हेतुक के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत नहीं किये जा सकते।	**247**	**284**
Section 124-A – Sedition – Constitutional validity of section 124-A – Various directions issued.		
धारा 124–क – राजद्रोह – धारा 124–क की संवैधानिक वैधता – विभिन्न निर्देश प्रसारित।	**305**	**360**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 148, 149 and 302 – Effect of defective charge.		
धाराएं 148, 149 एवं 302 – त्रुटिपूर्ण आरोप का प्रभाव।	**248 (i)**	**288**
Sections 148 and 302 – See Section 3 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 148 एवं 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	**249**	**290**
Sections 148 and 302/149 – (i) Testimony of related witness – Ordinarily a close relation would be the last to screen the real culprit and falsely implicate an innocent person – The relationship or the partisan nature of the evidence only puts the court on its guards to scrutinize the evidence more carefully. (ii) Evidence in case of unlawful assembly – Where a crowd of several assailants who are members of unlawful assembly proceed to commit an offence of murder in furtherance of the common object of the unlawful assembly, it is often not possible for witnesses to describe accurately the part played by each one of the assailant or to remember each and every blow delivered to victim – Therefore, some omissions and contradictions are normal considering the lapse of time, their state of trauma and shock.		
धाराएं 148 एवं 302/149 – (i) हितबद्ध साक्षी की विश्वसनीयता – सामान्यतः निकट संबंधी अंतिम ही होगा जो वास्तविक अभियुक्त को बचाये और निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या अलिप्त करे। रिश्तेदारी अथवा साक्ष्य की हितबद्ध प्रकृति न्यायालय पर साक्ष्य की जांच और अधिक सतर्कता से करने का उत्तरदायित्व रखती है। (ii) विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में साक्ष्य – जहां कई आक्रामकों की भीड़ जो कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हत्या का अपराध करने के लिए अग्रसर होते हैं, तब बहुधा साक्षियों के लिए यह संभव नहीं होता है कि वे प्रत्येक आक्रामक द्वारा निभाई गई भूमिका का सटीक वर्णन करें अथवा पीड़ित को कारित प्रत्येक प्रहार को याद रखे। इस प्रकार समय के व्यतीत होने और आघात तथा सदमे को विचार में ले तो कुछ लोप और विरोधाभास सामान्य है।	**131**	**146**
Section 149 – Common object – Innocent bystanders should not be implicated for constructive liability – Only if it is proved by the prosecution that common object of the unlawful assembly was shared by any bystander or onlooker then only such bystander or onlooker should be convicted under the principle of constructive liability.		
धारा 149 – सामान्य उद्देश्य – निर्दोष तमाशाई को आन्वयिक दायित्व के लिये अपराध में संलिप्त नहीं मानना चाहिए – यदि अभियोजन द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी तमाशाई या दर्शक द्वारा भी विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को साझा किया गया था तब ही ऐसे तमाशाई या दर्शक को आन्वयिक दायित्व के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है।	**132**	**147**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 149, 302 and 452 – See sections 118 and 134 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 149, 302 एवं 452 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 118 एवं 134।	**193**	**221**
Sections 201, 302, 364, 366-A and 376 – See sections 3 and 145 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 201, 302, 364, 366–क एवं 376 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 45।	**21**	**24**
Sections 201 r/w/s 34, 302 and 498–A – (i) Dowry death – Credibility of witnesses. (ii) Ante mortem injury – Medical evidence shows that deceased was first strangulated and then an attempt was made to camouflage the death as one which arose out of burn injuries.		
धाराएं 201 सहपठित धारा 34, 302 एवं 498–क – (i) दहेज मृत्यु – साक्षियों की विश्वसनीयता। (ii) मृत्यु पूर्व चोटें – चिकित्सीय साक्ष्य दर्शित करता है कि, मृतक का पहले गला घोंटा गया फिर छलावरण से ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया कि मृत्यु दहन क्षति के कारण हुई।	**306***	**361**
Sections 201 and 304-B – (i) Death in abnormal circumstances – Deceased went missing from her matrimonial home within a few months of her marriage and immediately after demands of dowry were made on her – Death occurred under abnormal circumstances – Such death would have to be charactarized as "dowry death". (ii) Demand of dowry – Lacking of specific allegation – Effect.		
धाराएं 201 एवं 304–ख – (i) असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु – मृतिका विवाह के कुछ माह के भीतर और उससे की गई दहेज की मांग के तुरंत पश्चात् अपने वैवाहिक निवास से लापता हो गई – उसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत कारित हुई – ऐसी मृत्यु को ''दहेज–मृत्यु'' के रूप में विशेषित किया जाना चाहिए। (ii) दहेज की मांग – विनिर्दिष्ट आक्षेप का अभाव – प्रभाव।	**194**	**221**
Sections 279 and 304-A – Punishment – In the case of Section 304-A of IPC, if it is proved at the time of accident, driver was drunk or affected by any other substance because of which he was unable to drive carefully, the punishment must be strict and harsh.		
धाराएं 279 एवं 304–क – दण्ड – यदि धारा 304–क भा.दं.सं. के प्रकरण में यह साबित होता है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक मदिरा के प्रभाव में था या किसी ऐसे पदार्थ के प्रभाव में था जिसके कारण वह सावधानीपूर्वक वाहन चलाने में सक्षम नहीं था तब दण्डादेश निश्चित रूप से सख्त होना चाहिए।	**133**	**148**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 299 and 300 – (i) Difference between murder and culpable homicide explained. (ii) Relative witnesses – Testimonies of eye-witnesses cannot be discarded merely on the ground of being relative of the deceased.		
धाराएं 299 एवं 300 – (i) हत्या और आपराधिक मानववध के मध्य अंतर समझाया गया। (ii) रिश्तेदार साक्षी – चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वे मृतक के रिश्तेदार है।	**32**	**41**
Section 300 – (i) Murder – Inquest Report – Objective – Not being a substantive piece of evidence and purpose is limited to finding out the apparent cause of death of a person who died under suspicious circumstances. (ii) Plea of *alibi* – Proof – Non-production of material evidence – Not tenable.		
धारा 300 – (i) हत्या – मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट – उद्देश्य – सारभूत साक्ष्य न होते हुए इसका सीमित उद्देश्य व्यक्ति की मृत्यु के दृश्यमान कारणों की जांच करना है जो संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत हुआ है। (ii) अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् – सबूत – तात्विक साक्ष्य का प्रस्तुत नहीं किया जाना – स्वीकार योग्य नहीं।	**195**	**222**
Section 300 – See Sections 3, 15, 24 and 45 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 300 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 15, 24 एवं 45।	**250**	**292**
Sections 300 and 302 – Murder – Once the prosecution establishes the existence of necessary ingredients forming a part of "thirdly" in Section 300, intention or knowledge on the part of accused to cause death is irrelevant.		
धाराएं 300 एवं 302 – हत्या – एक बार जब अभियोजन धारा 300 के ''तीसरा'' भाग के गठन के लिए आवश्यक संघटक स्थापित कर देता है, मृत्यु कारित करने का अभियुक्त का आशय या ज्ञान असंगत है।	**134***	**149**
Sections 300, Exception 4 and 304 Part II – Murder or culpable homicide not amounting to murder.		
धाराएं 300, अपवाद 4 एवं 304 भाग–दो – हत्या अथवा आपराधिक मानव–वध जो हत्या नहीं है।	**33***	**42**
Sections 300, 376-A and 376(2)(i) – *Mens rea* where death of victim aged 8 years was caused by pressing the neck with coercion.		
धाराएं 300, 376–क एवं 376(2)(i) – दोषपूर्ण आशय जहां 8 वर्षीय मृतिका की बलपूर्वक गर्दन दबाने से मृत्यु।	**251 (iv)**	**295**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 302 – Appreciation of evidence – Distinction between "Possible and Probable" and "Impossible and Improbable" explained.		
धारा 302 – साक्ष्य का विवेचन – ''संभव व संभाव्य'' तथा ''असंभव व असंभाव्य'' का विभेद स्पष्ट किया गया।	**77**	**84**
Section 302 – Murder – Dying declaration – Before death, deceased lodged FIR – Will be treated as dying declaration, if the prosecution establishes that deceased was conscious and in a fit state of mind.		
First Investigation Report – Not an encyclopedia – Precise and concise information is normal.		
धाराएं 302 – हत्या – मृत्युकालिक कथन – मृत्यु के पूर्व मृतक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई – यदि अभियोजन यह साबित कर दे कि मृतक जागृत तथा उपयुक्त मानसिक अवस्था में था तो प्रथम सूचना रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन की तरह मानी जाएगी।		
प्रथम जाँच रिपोर्ट – विश्वकोष नहीं है –सटीक एवं संक्षिप्त जानकारी सामान्य है।	**135 (i) & (ii)**	**149**
Section 302 – Murder – Multiple blows on vital part of the body – Use of weapon with such force resulting in skull fracture – Case falls under clauses thirdly and fourthly of section 300 IPC.		
धारा 302 – हत्या – शरीर के मार्मिक हिस्सों पर कई वार – हथियार का ऐसे बल के साथ प्रयोग जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में अस्थिभंग होता है – मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के तीसरे और चौथे खण्ड के अंतर्गत आता है।	**196**	**224**
Section 302 – See section 3 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	**136**	**151**
Section 302 – See section 32 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32।	**78**	**85**
Section 302 – See section 106 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106।	**197**	**225**
Section 302 – (i) Murder trial – Effect when chain of circumstances is incomplete.		
(ii) Appeal against acquittal – When to interfere? Principles explained.		
(iii) Circumstantial evidence – Motive – Relevance of – Motive may not be so significant in a case based on eyewitnesses – However, depending upon circumstantial evidence, motive is relevant.		
धारा 302 – (i) हत्या का मुकदमा – परिस्थितियों की श्रृंखला अधूरी रहने पर प्रभाव।		
(ii) दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील – कब दोषमुक्ति में हस्तक्षेप किया जायेगा? सिद्धांतो की व्याख्या की गई।		

(iii) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – हेतुक – प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर मामले में हेतुक की प्रासंगिकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में हेतुक प्रासंगिक है। **307*** **361**

Sections 302 and 34 – See sections 4 and 25 of the Arms Act, 1959.

धाराएं 302 एवं 34 – देखें आयुध अधिनियम, 1959 की धाराएं 4 एवं 25। **137** **153**

Sections 302 and 304 Part I – Murder or culpable homicide – If the offence was committed in the heat of passion or rage.

धाराएं 302 एवं 304 भाग–एक – हत्या या आपराधिक मानववध – यदि अपराध आवेश की तीव्रता में या क्रोध में कारित किया जाता है। **34** **43**

Sections 302 and 323 – Sentencing – Review – Principle of just punishment is the bedrock of sentencing in respect of criminal offence.

धाराएं 302 और 323 – सजा पर पुनर्विचार – उचित सजा का सिद्धांत आपराधिक मामले का आधार है। **308** **362**

Section 304 – Conviction – In the absence of any pre-planned attack and intention to cause death or such bodily injury as is likely to cause death.

धारा 304 – दोषसिद्धि – किसी पूर्व नियोजित आक्रमण एवं मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, के आशय के अभाव में। **35** **43**

Section 304-A – (i) Death due to negligence – Appreciation of circumstantial evidence – Conducted by technical experts – All the witness are hearsay and circumstantial – Held, acquittal proper.

(ii) For bringing home guilt of the accused, prosecution has to prove negligence and then establish direct nexus between negligence and death.

धारा 304–क – (i) उपेक्षा द्वारा मृत्यु – परिस्थितिजन्य साक्ष्य का अभिमूल्यन – तकनीकी विशेषज्ञ की निरीक्षण या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नही – संपूर्ण साक्ष्य परिस्थितिजन्य एवं अनुश्रुत – दोषमुक्ति उचित है।

(ii) दोषसिद्धि के लिये उपेक्षा प्रमाणित करना आवश्यक है, फिर उपेक्षा एवं मृत्यु के बीच सीधा संबंध स्थापित होना चाहिये। **309** **364**

Section 304-B – See Section 32 of the Evidence Act, 1872.

धारा 304–ख – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32। **298** **350**

Section 304-B – Dowry death – In-laws should not be convicted on the basis of generalized statement unless their specific roles are proved by the prosecution on the fact of cruelty.

धारा 304–ख– दहेज मृत्यु – सास–ससुर को सामान्य कथनों के आधार पर दोषसिद्ध नहीं करना चाहिये जब तक अभियोजन द्वारा क्रूरता के तथ्य पर उनकी विशिष्ट भूमिका प्रमाणित नहीं की जाती है। **138*** **154**

Section 304-B – See section 3 of the Dowry Prohibition Act, 1961 and sections 3 and 113-B of the Evidence Act, 1872.

धारा 304–ख – देखें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 113–ख। **198** **226**

Section 306 – Abetment for suicide – No one should be convicted for offence u/s 306 of IPC until it is proved that offence was committed because of positive act of the accused by instigating or aiding in committing suicide.

धारा 306 – आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण – भा.दं.सं. की धारा 306 के अंतर्गत तब तक किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह प्रमाणित नहीं हो जाता है कि यह अपराध अभियुक्त के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या करने के लिए उत्तेजित करने अथवा सहायता देने के कारण हुआ है। **36** **44**

Section 306 – Abetment to suicide – Merely having an extramarital relationship may not be sufficient to prosecute a person for offence u/s 306 of IPC, but when mental or physical cruelty is meted out to the deceased for having an extramarital releationship, it would then certainly amount to abetting of suicide.

धारा 306 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – केवल विवाहेतर संबंध रखना किसी व्यक्ति को धारा 306 के अन्तर्गत अभियोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है किन्तु जब विवाहेतर संबंध के कारण मृतक को मानसिक या शारीरिक क्रूरता कारित हुई हो तब यह निश्चित रूप से आत्महत्या का दुष्प्रेरण माना जाएगा। **199 (i)** **228**

Section 306 – Abetment of suicide – There must be mens rea in offence of section 306 IPC because its presence is necessary ancillary for the abetment and there should be continuous irritation by the accused through words or act.

धारा 306 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – धारा 306 भा.दं.सं. के अपराध में दोषपूर्ण आशय का होना आवश्यक है क्योंकि इसकी उपस्थिति दुष्प्रेरण के लिये आवश्यक सहवर्ती है और अभियुक्त के शब्दों या कृत्यों द्वारा निरंतर संताप होना चाहिए। **139** **155**

Section 306 – (i) Suicide – A teacher should not be prosecuted for the suicide committed by any student just because he rebuked the student.

(ii) Prosecution – Only pain or suffering of any complainant cannot be a base for starting a criminal prosecution unless it translates into a legal remedy.

धारा 306 – (i) आत्महत्या – एक शिक्षक को किसी छात्र द्वारा इस आधार पर की गई आत्महत्या के लिये अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए कि उसने छात्र की अनुशासनहीनता के लिये उसकी भर्त्सना की थी।

(ii) अभियोजन – किसी परिवादी का मात्र दर्द या पीड़ा एक दाण्डिक अभियोजन प्रारम्भ होने का आधार नहीं हो सकता है जब तक कि यह किसी विधिक उपचार में परिवर्तित नहीं होता है। **37** **45**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Section 307 – Evidence and proof – To know about the intention of the accused, deadliness of the weapon, injured part of the body and nature of injuries are to be taken into consideration by the court.

धारा 307 – साक्ष्य एवं प्रमाण – अभियुक्त का आशय जानने के लिये न्यायालय द्वारा आयुध की घातकता, शरीर के चोटिल भाग और उपहतियों की प्रकृति को विचार में लिया जाना चाहिये। **79** **87**

Sections 307 and 324 – See section 360 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 307 एवं 324 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360। **252** **300**

Section 324 – Effect of minor contradictions in a case where injuries are corroborated by medical witnesses.

धारा 324 – उपहति की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होने की दशा में मामूली विरोधाभास का प्रभाव। **253 (i)** **301**

Sections 363, 366-B, 370(4) and 506 – See section 188 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 363, 366–ख, 370(4) एवं 506 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 188। **233** **266**

Sections 364 and 364-A – (i) Identification of accused – Dock Identification is a substantive piece of evidence and even in absence of Test Identification Parade, it can be relied upon.

(ii) Proof beyond reasonable doubt – The evidence of witness made it clear that he had a strong motive to falsely implicate accused on account of enmity – Held, the prosecution failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt.

धाराएं 364 एवं 364–क – (i) अभियुक्त की पहचान – कटघरे में पहचान साक्ष्य का तात्विक अंश है और यहां तक कि पहचान परेड परीक्षण के अभाव में भी इस पर विश्वास किया जा सकता है।

(ii) संदेह से परे प्रमाण – साक्षी के कथन से यह स्पष्ट है कि उसके पास अभियुक्त को रंजिश के कारण मिथ्या अलिप्त करने का प्रबल हेतुक था – अभिनिर्धारित, अभियोजन अभियुक्त की दोषिता संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। **80** **88**

Sections 366 and 376(2)(n) – See section 311 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 366 एवं 376(2)(ढ) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311। **200** **228**

Section 376 – Quantum of punishment – An accused convicted u/s 376 of IPC for the offence of rape committed prior to 21.04.2018.

धारा 376 – अभियुक्त को दिनांक 21.04.2018 से पहले कारित बलात्कार संबंधी अपराध के लिये धारा 376 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने पर दण्ड की मात्रा। **38** **45**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Section 376 – Sole testimony – No further corroboration is necessary to convict the accused if evidence rendered by the prosecutrix is totally reliable and trustworthy – In such case, conviction based on sole testimony of prosecutrix should not be interfered.

धारा 376 – एकमात्र परिसाक्ष्य – यदि पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूर्णतः दृढ़ एवं विश्वसनीय है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिये अन्य किसी संपोषक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे प्रकरण में पीड़िता की एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। **140 155**

Section 376(1) – (i) Determination of age – When the school record of the prosecutrix is available, not necessary to look into the ossification test report of the prosecutrix.

(ii) Absence of DNA examination – Effect – Ocular evidence coupled with medical evidence, it can be said that the presence of human semen and sperms in the vaginal slide further corroborates the evidence of prosecutrix.

(iii) Reduction of sentence – When the minimum sentence for offence u/s 376(1) of IPC was 10 years, the sentence cannot be reduced to the period of sentence already undergone by the appellant.

धारा 376(1) – (i) आयु का निर्धारण – जब अभियोक्त्री के स्कूल का अभिलेख उपलब्ध हो तब यह आवश्यक नहीं है कि अभियोक्त्री के अस्थि संयोजन परीक्षण प्रतिवेदन को विचार में लिया जाए।

(ii) डी.एन.ए. परीक्षण का अभाव – प्रभाव – मौखिक साक्ष्य को चिकित्सकीय साक्ष्य के साथ संबद्ध कर विचार में लेते हुए यह कहा जा सकता है कि वैजाइनल स्लाइड में वीर्य और शुक्राणु की उपस्थिति अभियोक्त्री की साक्ष्य को और संपष्ट करती है।

(iii) दण्डादेश का लघुकरण – जबकि भा.दं.सं. की धारा 376(1) के अंतर्गत अपराध के लिए न्यूनतम कारावास 10 वर्ष है, कारावास को अभियुक्त द्वारा पूर्व में भुगताई गई अवधि तक सीमित नहीं किया जा सकता है। **81 90**

Section 376(2)(g) – Gang rape – Testimony of prosecutrix – Reliability of – Evidence of prosecutrix was repleted with contradictions and omissions – Version not supported by other witnesses – Not found to be 'sterling witness'.

धारा 376(2)(छ) – सामूहिक बलात्संग –अभियोक्त्री की साक्ष्य की विश्वसनीयता – अभियोक्त्री के कथनों में तात्विक बिन्दुओं पर विरोधाभास – साक्ष्य की पुष्टि अन्य साक्षीगण से नहीं हुई – ''वास्तविक साक्षी'' की श्रेणी में नहीं आती है। **141 (i) 157**

Sections 376, 504 and 506 – See sections 184, 218, 220, 227, 300 and 461 of the Criminal Procedure Code, 1973

धाराएं 376, 504 एवं 506 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 184, 218, 220, 227, 300 एवं 461। **289 339**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 376 and 511 – (i) Preparation and attempt to commit an offence – Distinction explained. (ii) Attempt to commit rape or outraging modesty of women. **धाराएं 376 एवं 511** – (i) अपराध करने की तैयारी और प्रयत्न – भेद समझाया गया। (ii) बलात्कार अथवा स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास।	**39**	**46**
Section 379 r/w/s 34 – Benefit of probation in case of theft. **धारा 379 सहपठित धारा 34** – चोरी के प्रकरण में परिवीक्षा का लाभ।	**254**	**303**
Sections 392 and 397 – Use of firearm – Only one of the three accused had used the firearm and it was seized from his possession – No charge of having used firearm proved against other co-accused – Charge u/s 397 IPC can be fastened on the 'offender' who actually used the firearm. **धाराएं 392 एवं 397** – आग्नेयास्त्र का प्रयोग – तीन अभियुक्तगण में से केवल एक के द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया और वह उसके अधिपत्य से अभिग्रहित किया गया – अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ – धारा 397 भा.दं.स. का आरेाप उस अपराधी के विरूद्ध आरोपित किया जा सकता है जिसने वास्तविक रूप से आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया है।	**142***	**158**
Section 397 – Constructive liability – Conviction cannot be based on constructive liability u/s 397 of IPC for the offence of robbery. **धारा 397** – आन्वयिक दायित्व – भा.दं.सं. की धारा 397 के अंतर्गत लूट के अपराध के लिये आन्वयिक दायित्व के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।	**82**	**92**
Sections 406, 419 and 420 – Criminal breach of trust and cheating – Sale of excess flats, even if made, amounts to mere breach of contract – Complaint disclosing criminal offence or not, depends on the nature of allegations – Whether essential ingredients of criminal offence are present or not has to be judged? Abuse of law – Attempt to convert a case of civil nature into a criminal prosecution, merely to take advantage of a relative quick relief granted in criminal case not correct. **धाराएं 406, 419 एवं 420** – आपराधिक न्यास भंग एवं छल – अतिरिक्त फ्लेट की बिक्री प्रमाणित तब भी केवल संविदा का भंग माना गया – परिवाद में उल्लेखित अभिकथनों के आधार पर आपराधिक अपराध गठित हुआ या नहीं देखा जायेगा – यह निर्धारित किया जाना चाहिये कि अपराध के आवष्यक घटक मौजूद है या नहीं। आपराधिक प्रकरण में सापेक्ष रूप से शीघ्र उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिये सिविल प्रकृति के प्रकरण को आपराधिक अभियोजन में परिवर्तित करना उचित नहीं है।	**143**	**159**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 409, 420 and 477-A – (i) Offence of criminal breach of trust, cheating and falsification of accounts – Necessary ingredients – Enumerated. (ii) Criminal breach of trust – Proof – Accused neither gaining pecuniary profit nor any lass to the institution – Offence not proved.		
धाराएं 409, 420 एवं 477–क – (i) आपराधिक न्यासभंग, छल और लेखों के मिथ्याकरण का अपराध – आवश्यक तत्व – प्रगणित किये गये। (ii) आपराधिक न्यास भंग – सबूत – अभियुक्त को कोई आर्थिक लाभ नहीं, न ही संस्था को कोई हानि कारित हुई – अपराध साबित नहीं।	**144**	**160**
Section 420 – See section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.		
धारा 420 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138।	**50**	**55**
Section 460 – Circumstantial evidence – When the case fully rests upon circumstantial evidence.		
धारा 460 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – जब मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है।	**40***	**48**
Section 467 – See section 167(2)(a)(i) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 467 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167(2)(क)(i)।	**10***	**13**
Section 498-A – Cruelty – Jurisdiction of court – Courts at the place where the wife takes shelter after leaving or driven away from the matrimonial home on account of acts of cruelty committed by the husband or his relatives, also have jurisdiction to entertain a complaint alleging commission of offences u/s 498-A of the Code.		
धारा 498–क – क्रूरता – न्यायालय का क्षेत्राधिकार – जहां पत्नी अपने पति या उसके रिश्तेदार द्वारा की गई क्रूरता के कार्य के कारण वैवाहिक गृह को छोड़कर या उससे दूर जाकर रहती है संहिता की धारा 498–क के अन्तर्गत अपराध का आक्षेप करने वाले परिवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार उस स्थान के न्यायालय को भी है।	**201***	**230**
Section 498-A – Matrimonial disputes – Allegation of cruelty – Proceeding against distant relatives – The relatives of the husband should not be roped in on the basis of omnibus allegations unless specific instances of their involvement are made out.		
धारा 498–क – वैवाहिक विवाद – क्रूरता का आक्षेप – दूरस्थ रिश्तेदारों के विरूद्ध कार्यवाही – पति के रिश्तेदारों को बहुप्रयोजनीय आक्षेपों के आधार पर तब तक नहीं फंसाया जाना चाहिए जब तक कि विनिर्दिष्टतः उनकी संलिप्तता दर्शित न हों।	**202**	**230**
Section 498-A – See section 32(1) of the Evidence Act, 1872.		
धारा 498–क – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1)।	**242**	**278**
Section 498-A – Sentence – Offence of cruelty commited by a woman against another woman – Makes the offence more serious.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 498–क – दण्डादेश – एक महिला द्वारा दूसरी महिला के विरूद्ध कारित क्रूरता का अपराध ऐसे अपराध को और अधिक गम्भीर बनाता है।	**203**	**231**
INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947**		
Sections 25-B and 25-F – See sections 9 and 21 of the Civil Procedure Code, 1908. **धाराएं 25–ख एवं 25–च** – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराएं 9 एवं 21।	**59**	**66**
Section 33-C(2) – See Labour Law. **धारा 33–ग(2)** – देखें श्रम कानून।	**310**	**366**
INTERPRETATION OF STATUTES : **संविधियों का निर्वचनः**		
– See section 7 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. – देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7।	**53**	**60**
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000**		
Section 7A – See section 376(1) of the Indian Penal Code, 1860. **धारा 7क** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(1)।	**81**	**90**
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015**		
Sections 3, 12 and 15 – See Section 436-A of the Criminal Procedure Code, 1973. **धाराएं 3, 12 एवं 15** – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436–क।	**237***	**273**
Sections 7-A, 9, 49 and 94 – Claim of juvenility – Stage – Such claim may be raised at any stage of a criminal proceeding even after final disposal of the case. Ossification test – It is only guiding factor not conclusive evidence, which should be considered in the absence of documents mentioned u/s 94 (2). Divergent views – If two views are possible, benefit should be given to the accused. **धाराएं 7–क, 9, 49 एवं 94** – किशोरवयता का दावा – प्रक्रम – ऐसा दावा आपराधिक कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, यहां तक कि प्रकरण के अंतिम निराकरण के उपरांत भी किया जा सकता है।		

अस्थि जांच परीक्षण – यह निश्चायक साक्ष्य नहीं है केवल मार्गदर्शक कारक है जिसको धारा 94(2) में उल्लेखित दस्तावेजों के अभाव में विचार में लेना चाहिए।

एकाधिक विचार – यदि दो विचार संभव है तब इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। **145 (i), (iii) & (iv)** **162**

Sections 8(2), 12 and 102 – (i) Rule of *ejusdem generis* – Attracted where a restricted meaning is given to the general word accompanying the specific word only when intended by the legislature.

(ii) Revision is maintainable u/s 102 against order of rejection of bail application.

धाराएं 8(2), 12 एवं 102 – (i) सजाति व्याख्या का नियम – वहां आकर्षित होता है जहां विशिष्ट शब्द के साथ सामान्य शब्द को प्रतिबंधित अर्थ दिया जाता है, केवल जब विधायिका द्वारा आशयित हो।

(ii) पुनरीक्षण – जमानत आवेदन के नामंजूर किये जाने के आदेश के विरूद्ध धारा 102 के अन्तर्गत पुनरीक्षण याचिका प्रचलनशील है। **255** **303**

Section 94 – (i) Determination of age – Family register – Maintained in the ordinary course of business by a public servant in discharge of his official duty – Relevant for determining the age.

(ii) Plea of juvenility – Document produced not reliable or dubious in nature – No benefit can be granted to accused who approach Court with untruthful statement.

धारा 94 – (i) आयु का निर्धारण – परिवार पंजी – अपने कर्तव्य के सामान्य अनुक्रम में लोक सेवक द्वारा तैयार किया गया – आयु निर्धारण हेतु सुसंगत।

(ii) किशोरवयता का अभिवाक् – प्रस्तुत दस्तावेज अविश्वसनीय और संदिग्ध प्रकृति के – अभियुक्त को कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती जो असत्य कथन करते हुए न्यायालय में आया हो। **182*** **206**

Section 94 – Determination of age of juvenile – If the documents mentioned in section 94(2)(i) and (ii) of the Act are not available.

धारा 94 – किशोर की आयु का अवधारण – यदि अधिनियम की धाराएं 94(2)(i) एवं (ii) में उल्लेखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। **41*** **49**

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2007

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007

Rule 12 – See sections 7A, 9, 49 and 94 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Section 35 of the Evidence Act, 1872

नियम 12 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 7क, 9, 49 एवं 94 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35। **145** **162**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Rule 12(3) – See section 376(1) of the Indian Penal Code, 1860.		
नियम 12(3) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(1)।	**81**	**90**
KAVAAD MAFIDARAN JUJAJVE AARAJI AND NAQDI, RIYASAT GWALIOR, SAMVAT 1991		
कावड़ माफिदारन जुजाजवे आरजी और नकदी, रियासत ग्वालियर, संवत 1991		
Sections 4(4) and 12 – See section 32 of the Specific Relief Act, 1963.		
धाराएं 4(4) एवं 12 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 32।	**322**	**386**
LABOUR LAWS :		
श्रम कानून :		
– (i) Labour dispute – It was not open for the Labour Court to adjudicate upon the employer-employee relationship between the appellant and respondent.		
(ii) Industrial Disputes – Jurisdiction.		
– (i) श्रम विवाद – श्रम न्यायालय के लिये अनुमत नहीं है कि, वह अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी के मध्य नियोक्ता कर्मचारी के संबंधों का अभिनिश्चय करे।		
(iii) औद्योगिक विवाद – क्षेत्राधिकार।	**310**	**366**
– (i) Pro rata deduction in wages – When permissible ? If there is a deliberate attempt to not produce or do work by resorting to "go slow" strategy.		
(ii) Public notices – Put on the notice board – Workers were not given any opportunity to respond to these notices – Effect.		
(i) यथा अनुपातिक मजदूरी में कटौती – कब अनुमत है? जहां जानबूझकर धीमे कार्य करने की योजना के तहत कार्य अथवा उत्पादन नहीं किया जाता हो।		
(ii) लोकसूचना – नोटिस बोर्ड पर चस्पा – मजदूरों को इस सूचना के प्रति उत्तर हेतु अवसर नहीं दिया गया – प्रभाव।	**311**	**367**
LAND ACQUISITION ACT, 1894		
भू–अर्जन अधिनियम, 1894 / भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894		
Sections 4, 18 and 23 – Determination of compensation – While determining the market value/ compensation, previous instances of acquisition in proximity for location and potential for land acquisition along with cumulative increase are relevant considerations.		
धाराएं 4, 18 एवं 23 – प्रतिकर का निर्धारण – बाजार मूल्य/प्रतिकर का निर्धारण करते समय, विगत अवसर पर उस स्थान की समीपता में हुए अधिग्रहण तथा संचयी वृद्धि के साथ भूमि अधिग्रहण की क्षमता सुसंगत कारक है।	**83***	**93**

Sections 4 and 23 – (i) Determination of compensation – Generally the sale instances with respect to small plots/parcels of land are not comparable to large extent of land for the purpose of determining compensation.

(ii) Deduction – In case of acquisition of large tracts of land and the exemplars are of small portions of land, there shall be a suitable deduction towards development costs.

धाराएं 4 एवं 23 – (i) प्रतिकर का निर्धारण – सामान्य रूप से प्रतिकर के निर्धारण के उद्देश्य से छोटे भूखण्ड/भूमि के टुकड़े के विक्रय का उदाहरण भूमि के वृहद पैमाने के विक्रय के तुलनीय नहीं है।

(ii) कटौती – वृहद क्षेत्र की भूमि के अर्जन के मामले में और छोटे भूखण्ड के उदाहरण विकास शुल्क हेतु युक्तियुक्त कटौती होनी ही चाहिए। **256*** **305**

Sections 4 and 34 – Interest – Land owner must be awarded 9% per annum interest on compensation amount for the period between possession and date of notification u/s 4 of the Act, when possession has been taken by the State without paying compensation.

धाराएं 4 एवं 34 – ब्याज – जब राज्य द्वारा मुआवजा दिये बिना भूमि का आधिपत्य ले लिया गया हो तब भूमि स्वामी को मुआवजा राशि पर आधिपत्य दिनांक से धारा 4 की अधिसूचना दिनांक तक की अवधि के लिये 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी दिलाया जाना चाहिए।

84 **93**

Section 18 – (i) Rejection of reference – In absence of prosecution – Non-participation of any party could not confer jurisdiction on the Civil Court to dismiss the reference for default.

(ii) Order – No reasons assigned – Reasons are heartbeats of the order and absence of it reflects non-application of mind.

धारा 18 – (i) निर्देश का खारिज किया जाना – अभियोजन का अभाव – किसी भी पक्षकार की सहभागिता का अभाव निर्देश खारिज करने हेतु सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं देता है।

(ii) आदेश – कारण समनुदेशित नहीं किये गये – कारण आदेश की धड़कन होते हैं और कारणों का अभाव मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया जाना दर्शित करता है। **204** **232**

Sections 18 and 23 – Determination of market value – Fixation of market value in a reference u/s 18 of the Act necessarily involves some guess work which is required to be made by adopting one of the well recognized methods, such as comparison or capitalization.

धाराएं 18 एवं 23 – बाजार मूल्य का निर्धारण – अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में बाजार मूल्य नियत करने में आवश्यक रूप से कुछ अनुमान आधारित कार्य सम्मिलित है जिसको पूर्णतः तुलनात्मक या पूंजीकरण जैसी मान्यता प्राप्त पद्धति को अंगीकार कर किए जाने की आवश्यकता होती है। **146*** **165**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Sections 18 and 23 – Land acquisition – Determination of compensation – Reliance on sale deed.

धाराएं 18 एवं 23 – भूमि अधिग्रहण – प्रतिकर का निर्धारण – विक्रय विलेख पर निर्भरता। **42*** **49**

Sections 18 and 23 – Land acquisition – Determination of compensation – Large extent of agricultural land acquired – Sale exemplars of small plot cannot be relied for enhancement.

धाराएं 18 एवं 23 – भूमि अधिग्रहण – प्रतिकर का निर्धारण – बड़े क्षेत्र की कृषि भूमि अधिग्रहित – छोटे भू–खण्ड के विक्रय का उदाहरण देकर वृद्धि नहीं की जा सकती। **312** **368**

Section 23 – (i) Compensation; determination of – Assessment of market value – Where different properties in different survey numbers are acquired for same purpose.

(ii) Compensation; determination of – Assessment of market value – Reliance on sale exemplars of very property in question.

धारा 23 – (i) प्रतिकर का निर्धारण – बाजार मूल्य का आंकलन – जहां एक ही उद्देश्य के लिए अलग–अलग सर्वे नंबरों की विभिन्न भूमियों का अधिग्रहण किया जाता है।

(ii) प्रतिकर का निर्धारण – बाजार मूल्य का आंकलन – उसी संपत्ति के विक्रय दृष्टांत पर निर्भरता। **43** **50**

Section 23 – Determination of market value – To determine market value of land acquired, if a sale deed is being used by the Reference Court which was executed before the notification of the acquisition, then year to year increase should be granted and in case of more than 9 years old sale deed, the increase must not be more than 10 percent annually.

धारा 23 – बाजार मूल्य का निर्धारण – जब अधिग्रहीत भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिये रेफरेंस न्यायालय के द्वारा ऐसे विक्रय पत्र का उपयोग किया जा रहा है जिसका निष्पादन अधिग्रहण की अधिसूचना के पूर्व किया गया था तब वार्षिक वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए और 9 वर्ष पुराने विक्रय पत्र के उपयोग की दशा में ऐसी वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। **147** **166**

Section 23 – (i) Determination of compensation – Sale instances of same village are to be considered whereas sale exemplers of adjacent village or of small area of land should be discarded.

(ii) Market value – Enhancement of compensation – Cumulative increase of 10-15% per year in the market value of the land may be accepted.

धारा 23 – (i) प्रतिकर का निर्धारण – समान गांव के विक्रय उदाहरणों को विचार में लिया जाना चाहिए – आसन्न गांव या भूमि के छोटे क्षेत्र के विक्रय उदाहरण स्वीकार योग्य नहीं।

(ii) बाजार मूल्य – प्रतिकर में वृद्धि – भूमि के बाजार मूल्य में प्रतिवर्ष 10–15 प्रतिशत की संचयी वृद्धि स्वीकार की जा सकती है। **313** **369**

Section 23 – See Order 41 Rule 27 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 23 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 नियम 27। **257** **306**

LAND REVENUE CODE, 1959 (M.P.)

भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र)

Sections 31, 250 and 257 – (i) Mutation proceedings – Rules 24 and 32 do not contemplate adjudication of title by Tahsildar – It nowhere gives authority to Tahsildar to go into the question of title and decide.

(ii) Power of Civil Court – Deciding the title arising out of Will is in the domain of Civil Court only.

धाराएं 31, 250 एवं 257–(i) नामांतरण कार्यवाही – नियम 24 एवं 32 तहसीलदार द्वारा स्वत्व के न्याय निर्णयन की अपेक्षा नहीं करता है – यह कहीं भी तहसीलदार को स्वत्व के प्रश्न में जाने तथा अवधारित करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(ii) सिविल न्यायालय की शक्ति – वसीयत के आधार पर उत्पन्न स्वत्व का अवधारण केवल सिविल न्यायालय के कार्यक्षेत्र में है। **85*** **94**

Sections 111 and 116 – See Section 9 of the Civil Procedure Code, 1908.

धाराएं 111 एवं 116 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9। **148** **167**

Section 178 – Partition suit – Jurisdiction of Revenue Authorities – Partition suit cannot be decided by Revenue Authorities.

धारा 178 – विभाजन का वाद – राजस्व प्राधिकारियों की अधिकारिता – राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विभाजन के वाद का विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। **86*** **94**

Section 250 – See Sections 22, 26 and 28 of the Public Trusts Act, 1951 (M.P.).

धारा 250 – देखें लोक न्यास अधिनियम, 1951 (म.प्र.) की धाराएं 22, 26 एवं 28।

102 **108**

Sections 250 and 257 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.

धाराएं 250 एवं 257 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।

222 **252**

LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT, 1987

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

Sections 19 and 20 – Lok Adalat – Jurisdiction – Whether Lok Adalat can enter into the merits of matter and decide it on merits in absence of any compromise or settlement between the parties?

धाराएं 19 एवं 20 – लोक अदालत – क्षेत्राधिकार – क्या लोक अदालत पक्षकारों के बीच किसी समझौते या परिनिर्धारण के अभाव में मामले के गुण–दोष पर विचार कर सकती है और गुण–दोष के आधार पर निर्णय ले सकती है? 44 51

Section 21 – Where compromise decree is Challenged on the ground of fraud – Allegations of fraud will have to be proved strictly.

धारा 21 – समझौता डिक्री को कपट के आधार पर चुनौती दी जाने पर कपट के आधार को कठोरता से प्रमाणित करना होगा। **230 263**

LIMITATION ACT, 1963

परिसीमा अधिनियम, 1963

Section 5 – (i) Delay – Sufficient cause to condone – Principles reiterated.

(ii) Abatement – Delay in filing application – Effect.

धारा 5 – (i) विलंब – क्षमा हेतु पर्याप्त कारण – सिद्धांत दोहराये गये।

(ii) उपशमन – आवेदन दायर करने में विलंब – प्रभाव। **229 260**

Section 5 – Application for condonation of delay – Decided on same day without issuing any notice to respondent – Appeal was never listed for consideration of said application – Condonation of delay, erroneous.

धारा 5 – विलम्ब को क्षमा करने के लिए आवेदन – प्रत्यर्थी को कोई सूचना पत्र दिये बिना उसी दिन निराकृत किया गया – अपील कभी भी इस आवेदन पर विचार के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई – विलम्ब की माफी अनुचित है। **285* (ii) 334**

Section 5, Articles 116, 117 and 137 – See section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

धारा 5, अनुच्छेद 116, 117 एवं 137 – देखें माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37। **1 1**

Article 59 – In a suit for cancellation of sale deed and possession – Limitation period required to be calculated with respect to substantive relief claimed and not consequential relief.

अनुच्छेद 59 – विक्रय पत्र रद्द किये जाने व आधिपत्य हेतु प्रस्तुत वाद में परिसीमा काल की गणना सारवान सहायता के आधार पर की जायेगी न कि परिणामिक सहायता के आधार पर। **271 (ii) 319**

MADHYASTHAM ADHIKARAN ADHINIYAM, 1983 (M.P.)

माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (म.प्र.)

Sections 2, 3 and 7 – Work contract – Jurisdiction – All disputes relating to work contract shall be exclusively decided by the Tribunal created under the M.P. Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 and not under Arbitration and Conciliation Act, 1996.

धाराएं 2, 3 एवं 7 – कार्य संविदा – क्षेत्राधिकार – कार्य संविदा संबंधी सभी विवाद विनिर्दिष्टतः मध्य प्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित अधिकरण द्वारा ही विनिश्चित किये जायेंगे न कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन। **169 (i) 191**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 3 and 7 – See sections 11 and 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996		
धाराएं 3 एवं 7 – देखें माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 11 एवं 34।	**218**	**249**
MINERALS (PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION AND STORAGE) RULES, 2006 (M.P.)		
खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम, 2006 (म.प्र.)		
Rule 18 (6) Proviso – Interim custody – Jurisdiction – Authorised officer granted interim custody of the seized property before intimation about the offence is made to the Judicial Magistrate – On receipt of intimation, the power of grant or refusal of interim custody vests exclusively with the Judicial Magistrate.		
नियम 18 (6) परन्तुक – अंतरिम अभिरक्षा – क्षेत्राधिकार – प्राधिकृत अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध के संबंध में सूचना दिए जाने से पूर्व जप्तशुदा संपत्ति की अंतरिम अभिरक्षा प्रदत्त कर सकता है – न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना प्राप्त होने के बाद अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करना अथवा इंकार करने की शक्ति आत्यांतिक रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट में अंतर्निहित होती है।	**149**	**167**
MOTOR VEHICLES ACT, 1988		
मोटरयान अधिनियम, 1988		
Section 3 – Whether a person holding a driving licence in respect of "light motor vehicle" is entitled to drive a 'transport vehicle of light motor vehicle class' having unladen weight not exceeding 7,500 kg?.		
धारा 3 – क्या एक व्यक्ति जिसके पास ''हल्का मोटर यान'' चलाने की चालन अनुज्ञप्ति है 7500 किलोग्राम से अनधिक भार का लदानरहित ''हल्का परिवहन मोटर यान वर्ग'' का वाहन चलाने के लिए पात्र है?	**258***	**306**
Sections 39 and 192 – Non-registration of vehicle – Fundamental breach of policy – If temporary registration of vehicle has been expired and there is nothing on record to suggest that party applied for registration or that he is awaiting registration – In case of theft or accident of vehicle, non-registration of the vehicle is violation of sections 39 and 192 of the Motor Vehicles Act and fundamental breach of policy.		
धाराएं 39 एवं 192 – वाहन का पंजीयन न होना – पॉलिसी का आधारभूत उल्लंघन – यदि वाहन के अस्थाई पंजीयन की अवधि समाप्त हो चुकी है और अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि पक्षकार ने पंजीयन के लिए आवेदन किया है या यह कि वह पंजीयन का इंतजार कर रहा है – वाहन के चोरी होने अथवा दुर्घटना होने की दशा में वाहन के पंजीयन नहीं होने का प्रभाव धारा 39 तथा 192 मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है तथा पॉलिसी का आधारभूत उल्लंघन है।	**87**	**95**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.

Sections 66 (3)(c) and 149 – Permit and fitness certificate – Liability of Insurance Company.

धाराएं 66 (3)(ग) एवं 149 – अनुज्ञा पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र – बीमा कंपनी का दायित्व। **314** **370**

Section 147 – Accident by stolen vehicle – No willful breach of terms and conditions of the insurance policy by the insured – Insurance Company held liable.

धारा 147 – चुराए गए वाहन द्वारा दुर्घटना – बीमित द्वारा बीमा पालिसी की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया – बीमा कम्पनी को दायित्वधीन ठहराया गया। **205*** **235**

Section 147 – Motor Accident – Personal accident cover – In case of death of husband of insured/ owner of car while driving the car – Premium was paid for owner/ driver – The policy was categorically indemnifying the personal accident claim of the owner and driver – There was no cap on the amount of compensation payable by the insurance company in the policy – Insurance company held liable.

धारा 147 – मोटर दुर्घटना – व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा – बीमित/कार स्वामी के पति की कार चलाते समय हुई मृत्यु के मामले में स्वामी/चालक के लिए प्रीमियम अदा किया गया था – पॉलिसी विनिर्दिष्ट रूप से स्वामी और चालक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना दावा की क्षतिपूर्ति कर रही थी – बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य प्रतिकर की राशि पर कोई सीमा नहीं थी – बीमा कम्पनी को दायित्वाधीन अभिनिर्धारित किया गया। **88** **97**

Section 147 – Motor insurance – Tractor – If policy itself has a clause that one passenger is permissible to be carried on the tractor or additional premium is paid to carry passenger on the tractor, insurance company is liable.

धारा 147 – मोटर का बीमा – ट्रेक्टर – यदि पॉलिसी में स्वयं एक खण्ड है कि ट्रेक्टर पर एक यात्री को ले जाने की अनुमति है या ट्रेक्टर पर यात्री को ले जाने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम दिया गया है, तब बीमा कम्पनी दायित्वाधीन है। **89*** **98**

Section 147 r/w/s 2 (34) – Public place – Factory premises – Accident took place inside the factory premises which fall under the definition of section 2(34) of the Act as public place – Insurance company is liable.

धारा 147 सपठित धारा 2 (34) – लोक स्थान –दुर्घटना कारखाना परिसर के अंदर हुई – जो अधिनियम की धारा 2(34) के अन्तर्गत लोक स्थान की परिभाषा में आता है – बीमा कम्पनी दायित्वधीन है। **150*** **168**

Section 149 – Driving licence – Pay and recover – Driver of vehicle was holding licence to drive light motor vehicle and heavy transport vehicle, but he was driving a motor cycle at the time of accident – Insurance company absolved from liability but directed to satisfy the award and then recover the amount from the owner and driver of the vehicle.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 149 – चालन अनुज्ञप्ति – भुगतान करो और वसूलो – चालक के पास हल्का मोटरयान तथा भारी वाहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति थी लेकिन वह दुर्घटना के समय मोटर सायकल चला रहा था – बीमा कम्पनी को दायित्व से मुक्त किया गया किन्तु अवार्ड को संतुष्ट करने तथा राशि को वाहन के स्वामी और चालक से वसूल करने के निर्देश दिए गए।	**90***	**98**
Section 149 (2)(a)(ii) – Fake driving license – Owner of vehicle is expected to verify driving skills of driver before appointing him and once satisfied, not expected to verify the genuineness of his driving license.		
धारा 149 (2)(क)(ii) – फर्जी चालन अनुज्ञप्ति – वाहन मालिक से अपेक्षा है कि वह चालक की नियुक्ति से पूर्व ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करे, एक बार संतुष्ट होने के बाद चालक के चालन अनुज्ञप्ति की वास्तविकता को सत्यापित करने कि उम्मीद नहीं रहती।	**315**	**371**
Section 163-A – Fatal accident – In case of death of 7 year old child studying in class II, by taking into account the inflation, devaluation of rupees and cost of living, the Apex Court, considered notional income of deceased at Rs. 25000 per annum and applied multiplier of '15'.		
धारा 163–क – घातक दुर्घटना – कक्षा 2 में पढ़ने वाले 7 वर्ष के बालक की मृत्यु के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महगांई, रूपये में गिरावट तथा जीवन यापन की लागत को विचार में लेते हुए मृतक की काल्पनिक आय 25000 रूपये प्रतिवर्ष मानी गई तथा 15 का गुणांक लागू किया गया।	**91***	**98**
Section 166 – Assessment of compensation – Injured suffered 100 percent permanent disablement – Would require an attendant for the rest of his life – Tribunal awarded ₹ 4,81,000/- – High Court enhanced the compensation to ₹ 13,08,000/- – Apex Court further allowed enhancement and specially ₹ 6,00,000/- for attendant, transportation and special diet.		
धारा 166 – प्रतिकर का निर्धारण – आहत को 100 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता कारित हुई, उसको अपने शेष जीवन के लिए एक सहायक की आवश्यकता होगी – अधिकरण द्वारा ₹ 4,81,000/– अधिनिर्णित किए गए – उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर को बढ़ाकर ₹ 13,08,000/– किया गया – उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिकर में और वृद्धि की और विशेष रूप से सहायक, परिवहन तथा पोषण आहार के मद में ₹ 6,00,000/– दिए।	**153***	**170**
Section 166 – Assessment of income – Deceased was a bachelor of engineering – Tribunal assessed the income at ₹ 20,000/- per month and awarded ₹ 30,54,000/- – High Court reduced the amount of compensation to ₹ 15,82,000/- – Considering the qualification of the deceased, Apex Court restored the Tribunal's award.		
धारा 166 – आय का निर्धारण – मृतक अभियांत्रिकी में स्नातक था – अधिकरण ने ₹ 20,000/– प्रति माह आय का निर्धारण करते हुए ₹ 30,54,000/– अधिनिर्णित किये – उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर की राशि को घटाकर ₹ 15,82,000/– कर दिया गया – उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक की योग्यता को विचार में लेते हुए अधिकरण के अधिनिर्णय को पुर्नस्थापित किया।	**154***	**170**

Section 166 – Assessment of income – Deceased was second year Engineering student at the time of accident – Tribunal awarded a sum of ₹ 7,58,000/- which was enhanced by High Court to ₹ 10,04,937/- – Apex Court further awarded a sum of ₹ 5,00,000/- after considering the facts of education and job probability of the deceased.

धारा 166 – आय का निर्धारण –अभियांत्रिकी का छात्र – मृतक अभियांत्रिकी का द्वितीय वर्ष का छात्र था – अधिकरण ने ₹ 7,58,000/– का अवार्ड पारित किया जिसको उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर ₹ 10,04,937/– कर दिया – सर्वोच्च न्यायालय ने मृतक की शिक्षा तथा नौकरी की संभावना के तथ्य को विचार में लेते हुए अवार्ड में अतिरिक्त ₹ 5,00,000/– की वृद्धि की। **151*** **169**

Section 166 – Assessment of income of deceased – The minimum wages notification cannot be the final yardstick to arrive at the income of the deceased.

धारा 166 – मृतक की आय का निर्धारण – मृतक की आय निर्धारण के लिये न्यूनतम मजदूरी से संबंधित अधिसूचना अंतिम निर्धारक नहीं हो सकती है। **47** **53**

Section 166 – (i) Compensation – 100% disablement – Compensation may be determined as per recognized principles so that a person can lead his normal life.

(ii) Assessment of compensation – Can be assessed under which heads?

(iii) Notional income – Disablement suffered by the claimant for whole life – Multiplier be applied looking to the age of victim.

(iv) Future medical expenses – Should be based on injuries and disability – Attendant and physiotherapist charges also to be added.

धारा 166 – (i) प्रतिकर – शत् प्रतिशत विकलांगता – मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह सामान्य जीवन यापन कर सके।

(ii) प्रतिकर की गणना – किन मदों में आंकलन किया जा सकता है?

(iii) काल्पनिक आय – विकलांगता संपूर्ण जीवन के लिये मौजूद – पीड़ित की आयु के आधार पर गुणांक का चयन किया जाना आवश्यक।

(iv) भविष्य का चिकित्सीय व्यय – पीड़ित को आई हुई चोट एवं विकलांगता को दृष्टिगत रखते हुये भौतिक चिकित्सा व्यय एवं अटेंडेन्ट व्यय में राशि जोड़ी गयी। **316** **372**

Section 166 – Contributory negligence – Lorry was parked on National Highway without indicators or signals – To establish contributory negligence, some act or omission which materially contributed to the accident or damage, should be attributed to the person against whom it is alleged.

धारा 166 – योगदायी उपेक्षा – लॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना संकेतक दिए खड़ी की गई थी – योगदायी उपेक्षा प्रमाणित करने के लिए उस व्यक्ति का जिसके विरूद्ध योगदायी उपेक्षा का आक्षेप है दुर्घटना कारित होने में सारभूत योगदान होना चाहिए। **155*** **171**

Section 166 – Contributory negligence – Plea of contributory negligence – Head-on collision.

धारा 166 – अंशदायी उपेक्षा – अंशदायी उपेक्षा का अभिवचन – आमने–सामने की दुर्घटना।

45 **52**

Section 166 – (i) Dependant – Parents and married daughter of the deceased are also entitled for compensation.

(ii) Determination of dependency – Even if dependency is a relevant criteria to claim compensation for loss of dependency, it does not mean that financial dependency is the 'ark of the covenant'.

धारा 166 – (i) आश्रित – मृतक के माता–पिता तथा विवाहित पुत्री भी प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।

(ii) आश्रितता का निर्धारण – यद्यपि आश्रितता की हानि के लिए प्रतिकर का दावा करने के लिए आश्रितता एक सुसंगत कसौटी है किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आर्थिक आश्रितता 'वाचा का संदूक' है। **206*** **235**

Section 166 – Determination of compensation – Applying appropriate multiplier – The relevant multiplier which should be applied is the age of the deceased at the time of accident and not the age of his or her parents.

धारा 166 – प्रतिकर का निर्धारण – उचित गुणांक का प्रयोग – दुर्घटना के समय मृतक की आयु के आधार पर सुसंगत गुणांक का प्रयोग किया जाना चाहिए न कि उसके माता–पिता की आयु के आधार पर। **46*** **53**

Sections 166 and 168 – Just compensation – It is the duty of the Tribunal to assess the effect of permanent disability on the earning capacity of injured and after such assessment, loss of earning capacity should be quantified in terms of money to decide future loss of earning.

धाराएं 166 एवं 168 – उचित प्रतिकर – आहत की अर्जन क्षमता पर स्थायी निःशक्तता के प्रभाव का आंकलन करना अधिकरण का कर्तव्य है और ऐसे आंकलन के पश्चात् भविष्यवर्ती अर्जन हानि के निर्धारण हेतु अर्जन क्षमता की हानि को धन के रूप में परिमाणित करना चाहिए।

95 **101**

Section 166 – Legal representative – Mother-in-law who was dependent on the deceased for shelter and maintenance, is a legal representative u/s 166 of the Act.

धारा 166 – विधिक प्रतिनिधि – स्वयं के आवास एवं भरण–पोषण के लिये मृतक पर आश्रित सास भी अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि होती है। **92** **99**

Section 166 – Motor accident – Injury – Claimant suffered serious and grievous injuries including five fractures – No permanent disability was proved – Claimant was not found entitled for compensation for loss of future earnings.

धारा 166 – मोटर दुर्घटना– क्षति – आवेदक को गंभीर क्षति कारित हुई थी जिसमें पांच अस्थिभंग भी थे – स्थाई निर्योग्यता को प्रमाणित नहीं किया गया – आवेदक भविष्य की हानि के मद में प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया गया। **152*** **169**

Section 166 – Negligence – Appreciation of – If information related to negligence disclosed in the first information report is contrary to the evidence taken by the Tribunal on same point, in such a situation evidence taken by Tribunal should be believed and not the information disclosed in FIR.

धारा 166 – उपेक्षा का मूल्यांकन – यदि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेखित उपेक्षा संबंधी तथ्य समान बिंदु पर अधिकरण द्वारा ली गई साक्ष्य से विपरीत हो तब ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा ली गई साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए न कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेखित सूचना पर। **48** **54**

Section 166 – Permanent disability – In case of accident of a woman working as coolie, Apex Court fixed functional disability at 90 percent and restored Tribunal's award.

धारा 166 – स्थाई निर्योग्यता – महिला जो कुली का काम करती थी के दुर्घटना के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी कार्यकारी निर्योग्यता 90 प्रतिशत निर्धारित करते हुये अधिकरण का अधिनिर्णय पुनर्स्थापित किया। **93*** **100**

Section 166 – Policy condition – The terms of insurance policy have to be strictly construed and it is not permissible to re-write the contract while interpreting the terms of policy.

धारा 166 – पॉलिसी की शर्त – बीमा पॉलिसी की शर्तों का कठोर अर्थान्वयन अपेक्षित है और पॉलिसी की शर्तों की विवेचना करते समय अनुबंध को पुनः लिखने की अनुमति नहीं है। **94*** **100**

Section 166 – (i) Procedure – Application u/s 166 of Motor Vehicles Act, 1988 is summary in nature – How to be decided?

(ii) Conventional head – Compensation awarded for loss of love & affection, as separate head is not justified.

धारा 166 – (i) प्रक्रिया – धारा 166 मोटरयान अधिनियम के आवेदन का विचारण संक्षिप्त प्रकृति का है – आवेदन का निराकरण किस प्रकार किया जाना चाहिये?

(ii) पारंपरिक मद – प्रेम एवं स्नेह के मद में कोई पृथक से क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा सकती। **317** **375**

Section 166 – Split multiplier – Cannot be applied – Retirement in near future is not a just reason for applying split multiplier.

धारा 166 – पृथक–पृथक गुणांक – निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति पृथक–पृथक गुणांक लागू करने हेतु उचित कारण नहीं है। **207** **236**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 168 – Effect when at the time of accident, thresher is attached with the tractor and thresher is not insured.		
धारा 168 – प्रभाव–जब दुर्घटना के समय थ्रेसर ट्रेक्टर के साथ जुड़ा था एवं थ्रेसर का बीमा नहीं था।	**259**	**307**
Section 168 (1) – (i) Determination of income – At the time of accident the deceased was studying in the 3rd/4th semester of civil engineering, Cannot be considered worse than the labourers/skilled labourers.		
(ii) Future prospects – In case of a deceased who was not serving at the time of death and, income determined on guesswork, their legal heirs shall also be entitled to future prospects.		
धारा 168 (1) – (i) आय का निर्धारण – मृतक सिविल अभियांत्रिकी के तीसरे/चौथे सेमेस्टर में अध्ययन कर रहा था, उसकी आय को श्रमिक अथवा कुशल श्रमिक से और खराब स्थिति में नहीं माना जा सकता।		
(ii) भविष्यवर्ती लाभ – उस परिस्थिति में जहां मृत्यु के समय मृतक कार्य नहीं कर रहा था और आय अनुमान के आधार पर निर्धारित की गई है, उसके विधिक वारिस भी भविष्यवर्ती लाभ के अधिकारी होने चाहिए।	**156**	**171**
MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (M.P.)		
नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (म.प्र.)		
Section 307(2) and (5) – Notice for removal of encroachment by Corporation – Owner cannot claim remedy under sub-section (5) of section 307 of the Act as house-owner is not covered under the expression "any other person".		
धाराएं 307 (2) एवं (5) – अतिक्रमण हटाने के लिये नगरनिगम द्वारा सूचना पत्र – मकान मालिक धारा 307(5) अधिनियम 1956 के अंतर्गत उपचार प्राप्त नही कर सकता क्योंकि वह ''किसी अन्य व्यक्ति'' की श्रेणी में नहीं आता।	**318**	**377**
N.D.P.S. ACT, 1985		
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985		
Sections 35 and 54 – Presumption – Reverse burden – Standard of proof – An initial burden exists upon the prosecution and when it stands satisfied then legal burden would shift over accused to lead evidence or establish his case for innocence as per the standard of proof required, that is preponderance of probability.		
धाराएं 35 एवं 54 – उपधारणा – सबूत का विपरीत भार – सबूत का मानक – आरंभिक भार अभियोजन पर विद्यमान होता है और जब यह संतुष्ट हो जाता है तब अपेक्षित सबूत के मानक अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा अपनी निर्दोषिता के लिए प्रकरण स्थापित करने का भार अभियुक्त पर चला जाता है जो कि संभावनाओं की बाहुल्यता के अनुरूप है।	**96***	**101**

Sections 43 and 50 – (i) Public place – Chance recovery – Where the search and seizure was made from the vehicle used by way of chance recovery from public road, provisions of section 43 would apply.

(ii) Personal search – In the search of motor cycle at public place, compliance of section 50 does not attract.

(iii) Ownership – The seizure of vehicle from possession of the accused is proved beyond reasonable doubt, therefore, the question of ownership of vehicle is not relevant.

(iv) Independent witness – Merely because independent witnesses were not examined, the conclusion cannot be drawn that accused was falsely implicated.

धाराएं 43 एवं 50 – (i) लोक स्थान – संयोगवश बरामदगी – जहां लोकमार्ग पर संयोगवश बरामदगी के रूप में वाहन से तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाही की गई है वहां धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) व्यक्तिगत तलाशी – लोक स्थान पर मोटर साइकिल की तलाशी धारा 50 के पालन को आकर्षित नहीं करती है।

(iii) स्वामित्व – अभियुक्त के अधिपत्य से वाहन के अभिग्रहण को युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया, अतः वाहन के स्वामित्व का प्रश्न सुसंगत नहीं है।

(iv) स्वतंत्र साक्षी – केवल इस कारण कि स्वतंत्र साक्षीगण परीक्षित नहीं कराए गए हैं यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया था। **157** **173**

NATIONAL INVESTIGATION AGENCY ACT, 2008
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008

Sections 6 (4), (5), 10 and 22 – Investigation of scheduled offences – The remand and committal power of Chief Judicial Magistrate remains intact unless a special Court is designated by the Government u/s 22 of the Act.

धाराएं 6 (4), (5), 10 एवं 22 – अधिसूचित अपराधों का अन्वेषण – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड एवं उपार्पण की शक्तियां तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक कि शासन द्वारा अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय नामित नहीं कर दिया गया हो।

97 **102**

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

Sections 118, 138 and 139 – (i) Presumption – As provided under sections 118 and 139 of the Act arises when the signature on the dishonored cheque is admitted.

(ii) Sentence – Nature of transaction and status of parties should also be considered while passing the sentence u/s 138 of the Act and this offence should not be compared with any other criminal offences for the purpose of sentence.

धाराएं 118, 138 एवं 139 – (i) उपधारणायें – जब अनादरित चेक पर हस्ताक्षर स्वीकृत हों वहीं अधिनियम की धाराएं 118 एवं 139 के अंतर्गत उपलब्ध उपधारणायें उद्‌भूत होती हैं।

(ii) दण्डादेश – अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दण्डादेश पारित करते समय संव्यवहार की प्रकृति एवं पक्षकारों की प्रास्थिति पर भी विचार करना चाहिए और दण्ड के आषय हेतु इस अपराध की तुलना किसी अन्य दाण्डिक अपराध से नहीं करना चाहिए। **49** **54**

Section 138 – Complaint by company – Authorized employee of the company is de facto complainant – Such de facto complainant can change from time to time – Court can take cognizance on statement of such employee.

धारा 138 – कंपनी द्वारा परिवाद – कंपनी का अधिकृत कर्मचारी वस्तुतः परिवादी है – इस तरह का परिवादी समय समय पर बदल सकता है – न्यायालय इस तरह के कर्मचारी के कथनों पर संज्ञान ले सकता है। **208** **238**

Section 138 – (i) Dishonour of cheque and cheating – Mere dishonour of cheque cannot be construed as an act with a deliberate intention to cheat.

(ii) Cheque issued as security; dishonour of – When constitutes offence u/s 138 of the NI Act ?

धारा 138 – (i) चेक का अनादरण एवं छल – मात्र चेक के अनादरण को छल कारित करने के आशय से किए गए कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(ii) सुरक्षार्थ जारी चेक का अनादरण – कब परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध गठित करता है? **50** **55**

Section 138 – (i) Dishonour of cheque – Presumption – Initial burden is placed on the complainant to discharge that cheque is drawn towards the consideration of legally recoverable amount – Such presumption would remain until the contrary is proved.

(ii) Dishonour of cheque – Rebuttal of presumption – The onus is on the accused to raise a probable defence on preponderance of probabilities.

धारा 138 – (i) चेक का अनादरण– उपधारणा – यह साबित करने का प्रारंभिक सबूत का भार परिवादी पर है कि चेक विधिक रूप से वसूली योग्य राशि की अदायगी हेतु दिया गया है – जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए ऐसी उपधारणा अस्तित्व में रहेगी।

(ii) चेक का अनादरण– उपधारणा का खण्डन – संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर अधिसंभाव्य बचाव प्रस्तुत करने का प्रमाण भार अभियुक्त पर है। **158*** **176**

Sections 138 and 141 – Complaint against company – Complaint was filed only against corporate entity and none of the natural persons who were stated to be in charge of and responsible for affairs of corporate entity were arrayed as accused – In such facts and circumstances, corporate debtor cannot be proceeded against u/s 138.

धाराएं 138 एवं 141 – निगम के विरूद्ध परिवाद – परिवाद केवल निगमित संस्था के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था और निगमित संस्था के कार्यों के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में संयोजित नहीं किया गया था – ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, निगमित देनदार के विरूद्ध धारा 138 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। **98*** **103**

Sections 138 and 141 – (i) Debt or liability – Advance payment – If there is a breach in the condition of advance payment, it would not incur criminal liability u/s 138 since there was no legally enforceable debt or liability at the time when the cheque was drawn.

(ii) Gift – A cheque given as a gift and not for the satisfaction of a debt or liability would not attract the provision of section 138.

(iii) Post dated cheque – The term 'debt' also includes a sum of money promised to be paid on a future date by reason of a present obligation – A post-dated cheque issued after debt has been incurred would be covered by the definition of debt.

(iv) Offence by company – Incharge Officer – Whether the individual was incharge or responsible for the affairs of the company during the commission of the offence is the test to determine the liability of Director or Managing Director.

(v) Security cheque – Cheque furnished as security is covered under provision of section 138.

धाराएं 138 एवं 141 – (i) ऋण या दायित्व – अग्रिम भुगतान – यदि अग्रिम भुगतान की शर्त का भंग हुआ है तब यह धारा 138 के अन्तर्गत आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि जब चेक जारी किया गया था तब कोई ऋण या दायित्व नहीं था।

(ii) उपहार – चेक का उपहार स्वरूप न कि किसी ऋण या दायित्व की संतुष्टि हेतु दिया जाना, धारा 138 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है।

(iii) उत्तर दिनांकित चेक – शब्द 'ऋण' के अन्तर्गत ऐसी राशि भी सम्मिलित है जिसको वर्तमान दायित्व के कारण भविष्य के किसी दिनांक को भुगतान करने का वचन दिया गया हो – दायित्व उत्पन्न होने के उपरांत जारी किया गया उत्तर दिनांकित चेक ऋण की परिभाषा द्वारा आच्छादित है।

(iv) कम्पनी द्वारा अपराध – भारसाधक अधिकारी – निदेशक या प्रबंध निदेशक के दायित्व का निर्धारण करने के लिए परीक्षा यह है कि क्या वह व्यक्ति अपराध के घटित किए जाते समय कम्पनी के संव्यवहार का भारसाधक एवं जिम्मेदार रहा है।

(v) सुरक्षा चेक – सुरक्षा बतौर जारी किया गया चेक धारा 138 के प्रावधान द्वारा आच्छादित है।

159 **177**

Sections 138 and 141 – (i) Offence against company – Vicarious liability.

(ii) Necessary party – Unless the company or firm is arrayed as a party, Officers associated to the company would not be convicted as vicariously liable.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 138 एवं 141 – (i) कंपनी के विरूद्ध अपराध – प्रतिनिधिक दायित्व। (ii) आवश्यक पक्षकार – जब तक कंपनी या फर्म को पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा जाता, कंपनी से जुड़े अधिकारी को प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।	**260**	**308**
Sections 138, 141 and 142 – Complaint – Averment – Against those Directors of the company who neither signed the cheque nor posted as Managing Director or Joint Managing Director at the time of offence.		
धाराएं 138, 141 एवं 142 – परिवाद – प्रकथन – कंपनी के ऐसे निदेशकों के संबंध में जो न तो चेक के हस्ताक्षरकर्ता हैं, और न ही अपराध के समय प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर थे।	**51**	**58**
Sections 138, 141 and 142 – (i) Offence against company – Form of complaint. (ii) Offence against company – Complaint by authorized person – Whether it is always necessary to elaborate upon the authorization of person in body of complaint?		
धाराएं 138, 141 एवं 142 – (i) कंपनी के विरुद्ध अपराध – परिवाद का प्रारूप। (ii) कंपनी के विरुद्ध अपराध – अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवाद – क्या परिवाद के मुख्य भाग में व्यक्ति के प्राधिकार के बारे में विस्तार से बताया जाना सदैव आवश्यक है?	**52**	**59**
Sections 138 and 143 – (i) Jurisdiction – In case of any conviction in summary trial and summons trial explained – Ceiling u/s 29 (2) CrPC not applicable. (ii) Compensation – Compensation can be granted only u/s 357 (1) (b) of CrPC and not u/s 357 (3) of CrPC.		
धाराएं 138 एवं 143 – (i) क्षेत्राधिकार – संक्षिप्त विचारण एवं समन विचारण में मजिस्ट्रेट के दोषसिद्धि के प्रकरण में दी गई सजा की व्याख्या की गई है – धारा 29 (2) दं.प्र.सं. की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। (ii) प्रतिकर – प्रतिकर धारा 357 (3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता केवल धारा 357 (1) (ब) दं.प्र.सं. के अधीन दिया जा सकता है।	**319**	**378**
Sections 138 and 145 – Complaint u/s 138 – Defence evidence – Accused filed affidavit-of-evidence in lieu of Examination-in-Chief – Not admissible.		
धाराएं 138 एवं 145 – धारा 138 के अंतर्गत परिवाद – प्रतिरक्षा साक्ष्य – अभियुक्त ने मुख्य परीक्षण के स्थान पर साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया – ग्राह्य नहीं।	**261**	**310**
Section 141 – Offence against company – Specific averments in complaint about the Director, responsible for conduct of business and was In-charge, is essential for fulfilling requirement of section 141 of the N.I. Act.		
धारा 141 – कंपनी के विरूद्ध अपराध – परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु निदेशक का व्यापार संचालक एवं प्रभारी होने का शिकायत में विशिष्ट कथन आवश्यक है।	**320**	**382**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
POWERS OF ATTORNEY ACT, 1882		
मुख्तारनामा अधिनियम, 1882		
Sections 1A and 2 – (i) Sale by Power of Attorney holder – The possession of an agent under a deed of Power of Attorney is also the possession of the principal and that any unauthorized sale made by the agent will not tantamount to the principal parting with possession. (ii) Suit for partition – Is not always necessary for a plaintiff in a suit for partition to seek cancellation of alienations.		
धाराएं 1क एवं 2 – (i) मुख्तारनाम द्वारा विक्रय – मुख्तारनामा के अन्तर्गत अभिकर्ता का आधिपत्य प्रधान का आधिपत्य माना जाता है और अभिकर्ता के द्वारा किया गया कोई अनाधिकृत विक्रय प्रधान के आधिपत्य से अलग होने के समान नहीं होगा। (ii) विभाजन का वाद – विभाजन के वाद में वादी के लिए यह हमेशा आवश्यक नहीं होता कि वह व्ययनों का निरस्तीकरण मांगे।	**272 (i) & (iii)**	**320**
PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988		
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988		
Section 7 – Extra-judicial confession – Evidentiary value.		
धारा 7 – न्यायिकेत्तर संस्वीकृति – साक्ष्यिक मूल्य।	**262**	**310**
Sections 7 and 13 (1)(d) – Illegal gratification – Mere recovery of the amount from the person would not be sufficient to convict him.		
धाराएं 7 एवं 13 (1)(घ) – अवैध परितोषण – किसी व्यक्ति से केवल धन की बरामदगी मात्र उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है।	**209**	**239**
Section 19 – Sanction for prosecution – Proper stage of examining the validity of sanction is during trial – Issue relating to non-application of mind by sanctioning authority should firstly be raised during trial.		
धारा 19 – अभियोजन की अुनमति – अनुमति की वैधता के परीक्षण का उपयुक्त स्तर विचारण के दौरान है, अतः अनुमति देने के सम्बंध में प्राधिकारी द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करने सम्बंधी मुद्दा प्रथमतः विचारण के दौरान उठाया जाना चाहिए।	**99***	**103**
Section 19 – See Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 19 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190।	**290**	**341**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960 **पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960**		
Sections 4 and 9 r/w/s 11(d) – See Rule 5 of the Govansh Vadh Pratishedh Rules, 2012 (M.P.). **धाराएं 4 एवं 9 सहपठित धारा 11(घ)** – देखें मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 का नियम 5।	**263**	**311**
PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954 **खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954**		
Sections 7, 13 and 16 – Effect of not applying for examination of second sample by the Central Food Laboratory u/s 13(2) by the accused. **धाराएं 7, 13 एवं 16** – अभियुक्त द्वारा दूसरे नमूने को धारा 13(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से परीक्षित कराने के संबंध में आवेदन नहीं देने का प्रभाव	**264***	**313**
Section 13 – Right to challenge the report – If a copy of the report of the Public Analyst is not delivered to the accused, his right under sub-section (2) of Section 13 of praying for sending the sample to the Central Food Laboratory will be defeated. **धारा 13** – रिपोर्ट को चुनौती देने का अधिकार – यदि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति अभियुक्त को नहीं दी जाती है तो धारा 13 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में नमूना भेजने के लिए प्रार्थना करने का उसका अधिकार निष्फल हो जाएगा।	**100**	**104**
PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012 **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012**		
Section 4 – See section 376(1) of the Indian Penal Code, 1860. **धारा 4** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376(1)।	**81**	**90**
Section 5 – See sections 300, 376-A and 376(2)(i) of the Indian Penal Code, 1860, Section 53-A of the Criminal Procedure Code, 1973 and Sections 15, 27 and 45 of the Evidence Act, 1872. **धारा 5** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300, 376–क एवं 376(2)(i), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53–क एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 15, 27 एवं 45।	**251**	**295**
Section 7 – (i) Sexual assault – Interpretation of the words "touch", "physical contact" and "sexual intent" – Whether "skin to skin" contact is necessary for constituting offence u/s 7 of the POCSO Act? (ii) Certified copy of documents – How to be prepared?		

धारा 7 – (i) लैंगिक हमला – "स्पर्श", "शारीरिक संपर्क" और "लैंगिक आशय" शब्दों का निर्वचन – क्या पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के गठन के लिए "त्वचा से त्वचा" संपर्क आवश्यक है?

(ii) दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि – कैसे तैयार की जानी चाहिए? **53** **60**

Section 8 – See Section 188 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 8 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 188। **233** **266**

PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

Sections 2(f), 12 and 17 – (i) Magistrate can pass any order without considering Domestic Incident Report.

(ii) Shared household – Lived at any point of time and has been subjected to domestic violence, can file the application.

(iii) Right to reside cannot be restricted to actual residence.

धाराएं 2(च), 12 एवं 17 – (i) मजिस्ट्रेट घरेलू घटना रिपोर्ट को विचार में लिये बिना भी कोई आदेश पारित कर सकता है।

(ii) साझा गृहस्थी – किसी समय साथ रहे हो तथा घरेलू हिंसा कारित की हो तो भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) निवास का अधिकार वास्तविक निवास तक सीमित नहीं किया जा सकता।

265* **313**

Sections 2(q), 17 and 43 – Eviction from shared household – Protection against eviction or dispossession of a woman u/s 17 of the Act is not absolute or unqualified – Can be evicted from the shared household in accordance with the procedure established by law – Embargo contained in section 17(2) of the Act operates only against a person who is a respondent within the meaning of section 2(q) of the Act.

धाराएं 2 (थ), 17 एवं 43 – साझी गृहस्थी से निष्कासन – अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत महिला को निष्कासन अथवा बेदखल किए जाने से संरक्षण पूर्ण एवं आत्यंतिक नहीं है – विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में साझी गृहस्थी से निष्कासित की जा सकती है – अधिनियम की धारा 17(2) का प्रतिरोध केवल उस व्यक्ति के विरूद्ध लागू होता है जो अधिनियम की धारा 2 (थ) के अर्थ में प्रत्यर्थी है। **210*** **240**

Sections 2(s) and 19 (1)(f) – Alternate accommodation – Alternate equivalent accommodation as per section 19 (1) (f) of D.V. Act, does not mean that the alternate accommodation must be totally identical to previously shared house hold although, there should be similar luxury and comfort in the alternate accommodation also.

धाराएं 2(ध) एवं 19 (1)(च) – वैकल्पिक आवास – घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 (1) (च) में उल्लिखित समान स्तर के वैकल्पिक आवास का अर्थ यह नहीं है कि वैकल्पिक आवास पूर्व की साझी गृहस्थी वाले आवास से पूर्णतः समरूप होना चाहिए हालांकि वैकल्पिक आवास में भी विलासिता एवं आराम समान होना चाहिए। **160 180**

Sections 12 and 31 – See Sections 468 and 482 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 12 एवं 31 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 468 एवं 482। **266 314**

PUBLIC TRUSTS ACT, 1951 (M.P.)
लोक न्यास अधिनियम, 1951 (म.प्र.)

Sections 8, 12, 26 and 27 – Difference between the terms 'Court' and 'a Civil Court' – Term "Court" used in sections 26 and 27 and term "a Civil Court" used in sections 8 and 12 of the Trusts Act has different meaning as per the definition of 'Court' under Public Trusts Act.

धाराएं 8, 12, 26 एवं 27 – शब्द 'न्यायालय' तथा 'सिविल न्यायालय' में अन्तर – न्यास अधिनियम की धारा 26 तथा 27 में शब्द ''न्यायालय'' का प्रयोग किया गया है एवं धारा 8 तथा 12 में शब्द ''सिविल न्यायालय'' का प्रयोग किया गया है जिनके अलग अर्थ है। **101 105**

Sections 22, 25 and 26 – (i) Vacancies occurred in the Board – Can be filled through the procedure as provided u/s 25 of the Act.

(ii) Removal of the trustees – No such discretion is available to the Registrar.

(iii) Public Trust – Dispute relating to administration – The directions ought to have been sought from the District Judge as provided u/s 26 of the Act – Cannot be countenanced in the eyes of law.

धाराएं 22, 25 एवं 26 – (i) बोर्ड में स्थानों की रिक्तता – अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उपबंधित प्रक्रिया के द्वारा ही पूर्ण की जा सकती है।

(ii) न्यासियों का हटाया जाना – पंजीयक के पास ऐसा कोई विवेकाधिकार उपलब्ध नहीं है।

(iii) लोक न्यास – प्रशासन से संबंधित विवाद – अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत उपबंधों के तहत जिला न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने होंगे – विधि की दृष्टि से समर्थित नहीं माना जा सकता है। **267 316**

Sections 22, 26 and 28 – (i) Court – The powers of Court which are flowing from Civil Procedure Code are given to Registrar for limited purpose – Registrar under the Act is not a 'Court'.

(ii) Removal of encroachment – The relevant provision of Trusts Act provides for certain powers to Registrar but not give him any kind of power of adjudication or issuance of order to Tahsildar to remove encroachment.

धाराएं 22, 26 एवं 28 – (i) न्यायालय – सिविल प्रक्रिया संहिता से व्युत्पन्न न्यायालय की शक्तियां पंजीयक को जांच करने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है – अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक एक न्यायालय नहीं है।

(ii) अतिक्रमण का हटाया जाना – न्यास अधिनियम के सुसंगत प्रावधान जो पंजीयक को कतिपय शक्तियां प्रदान करते हैं वे न्यायर्णियन की या अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को आदेश जारी करने जैसे कोई शक्ति नहीं देते है। **102 108**

REGISTRATION ACT, 1908
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908

Section 17 – Registration – Need of – Document which neither creates right in specific property nor assets of the family in favour of a specific person – Registration of such document not required.

धारा 17 – पंजीकरण – आवश्यकता – दस्तावेज जो किसी विशिष्ट संपत्ति में कोई अधिकार सृजित नहीं करता और न ही विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में परिवार की संपदा को दिये जाने का उपबंध करता है – ऐसे दस्तावेज के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। **211 (i) 240**

Sections 17 and 49 – (i) Unregistered document – Relinquishment deed is compulsorily registrable u/s 17 of the Registration Act,

(ii) Collateral purpose – It must be "independent of" or "divisible from" the very object and purpose of such document for which it is executed.

(iii) Admissibility of unregistered document – Different propositions explained.

धाराएं 17 एवं 49 – (i) अपंजीकृत दस्तावेज – हक त्याग विलेख धारा 17 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्यतः पंजीयन योग्य दस्तावेज है।

(ii) संपार्विक उद्देश्य – यह उस दस्तावेज के उद्देश्य से ''स्वतंत्र'' तथा ''विभाज्य'' होना चाहिए जिसके लिए इसे निष्पादित किया गया है।

(iii) अपंजीकृत दस्तावेज की साक्ष्य में ग्राह्यता – विभिन्न प्रस्थापनाएं समझाई गई।

103 110

RULES REGARDING RECORD OF RIGHTS:
अधिकारों के अभिलेख संबंधी नियमः

Rules 24 and 32 – See sections 31, 250 and 257 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).

नियम 24 एवं 32 – देखें भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धाराएं 31, 250 एवं 257।

85 94

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989		
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989		
Section 3(2)(v) – See section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 3(2)(अ) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	**120***	**128**
SERVICE LAW :		
सेवा विधि :		
– Appointments – When illegal or invalid or wrong, explained – Appointment not consistent with statutory provisions are void ab initio.		
– नियुक्यिाँ – कब अवैध या अमान्य या गलत, समझाया गया – नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं, तो प्रारंभतः शून्य।	**321**	**383**
– Burden of proof – Delinquent may examine himself to rebut the allegations of misconduct.		
– सबूत का भार – अपचारी कदाचार के आरोपों के खण्डन के लिए स्वयं की परीक्षा करवा सकता है।	**54***	**63**
SPECIFIC RELIEF ACT, 1963		
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963		
Sections 10 and 16(c) – See section 96 and Order 41 Rule 31 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धाराएं 10 एवं 16(ग) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 31।	**4**	**5**
Sections 16 and 20 – Suit for specific performance of contract – Agreement to sell was executed between plaintiff and defendant for the suit property – Bharat Petroleum Corporation was having lease over the property and constructed petrol pump over that – Bharat petroleum had objected and claimed first right to purchase – Execution of agreement to sell and readiness and willingness were proved by the plaintiff – Trial Court dismissed the suit after considering the objection of the Corporation – High Court held that plaintiff is the master of the suit – Not bound to sue against every possible adverse claim in the suit – Suit was decreed.		
धाराएं 16 एवं 20 – संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद – वादी तथा प्रतिवादी के मध्य दावाकृत सम्पत्ति के विक्रय का करार निष्पादित किया गया। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के पास उक्त सम्पत्ति का पट्टा था और उस पर पेट्रोल पम्प का निर्माण किया गया था भारत पेट्रोलियम ने आपत्ति प्रस्तुत की तथा अग्रक्रयाधिकार का दावा किया – विक्रय के करार का निष्पादन तथा तैयारी एवं रजामंदी वादी के द्वारा प्रमाणित की गई – विचारण न्यायालय द्वारा कार्पोरेशन की		

आपत्ति को विचार में लेते हुए वाद खारिज किया गया – उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि वादी अपने वाद का स्वामी है – वाद में प्रत्येक संभावित विरोधी दावे के सम्बंध में वाद करने के लिए बाध्य नहीं है – वाद डिक्री किया गया। **161*** **181**

Sections 16(c) and 20 – (i) Nature of document where in the document the purpose of sale of the property was stated to be for the marriage expenses.

(ii) Readiness and willingness.

धाराएं 16(ग) एवं 20 – (i) दस्तावेज की प्रकृति जहाँ दस्तावेज में सम्पत्ति को विक्रय किये जाने का उद्देश्य विवाह खर्च उल्लेखित किया गया है।

(ii) इच्छुक और तत्परता। **268** **317**

Sections 16 (c) and 20 – Relief of specific performance – Discretion u/s 20 of the Act should be exercised judiciously on sound reason – Section 10(a) is not retrospective but this provision is a guide on the discretionary relief.

धाराएं 16 (ग) एवं 20 – विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष – अधिनियम की धारा 20 के विशेषाधिकार का उपयोग दृढ़ कारणों के आधार पर न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए –धारा 10 (क) का प्रावधान भूतलक्षी नहीं है किंतु यह विवेकाधीन अनुतोष प्रदान करने के लिये मार्गदर्शक है। **104** **112**

Section 19 (b) – Specific performance – Bonafide purchaser – Decree of specific performance in favour of the plaintiff who knew that the suit property was already purchased by a bonafide purchaser through registered deed before the institution of the suit – Should not be passed.

धारा 19 (ख) – विनिर्दिष्ट पालन – सद्भावी क्रेता – ऐसे वादी के पक्ष में विशिष्ट अनुपालन की आज्ञप्ति पारित नहीं किया जाना चाहिए जो यह जानता था कि वाद प्रस्तुति के पूर्व ही वाद–संपत्ति को सद्भावी क्रेता द्वारा पंजीकृत विलेख द्वारा खरीदा जा चुका था।

212 **241**

Section 20 – Agreement to sell joint Hindu family property – Right of karta to execute agreement to sell or sale deed of a joint Hindu family property is settled and is beyond cavil.

धारा 20 – संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के विक्रय का करार – संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति को विक्रय करने का करार निष्पादित करने या विक्रय करने का कर्ता का अधिकार स्थापित है और छिद्रान्वेषण से परे है। **162 (i)** **181**

Section 20 – Effect of admission when the vendor had specifically admitted the execution of the agreement to sale and receipt of the advance sale consideration.

धारा 20 – विक्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से विक्रय की संविदा का निष्पादन तथा अग्रिम विक्रय प्रतिफल की प्राप्ति स्वीकार करने का प्रभाव। **269*** **318**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 20 – Specific performance of contract – Test of readiness and willingness explained.		
धारा 20 – संविदा का विनिर्दिष्ट पालन – इच्छुक एवं तत्पर होने का परीक्षण समझाया गया।	**213**	**242**
Section 21(5) – Suit for specific performance of agreement – Neither specifically pleaded nor any step in this regard taken by the plaintiff – Relief cannot be granted.		
धारा 21(5) – अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद – वादी द्वारा न तो विनिर्दिष्ट रूप से अभिवचन किये गये और न ही इस संबंध में कोई कदम उठाये – अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जा सकता।	**214**	**243**
Section 32 – (i) Interference of State Government in private temple – Extent of power. (ii) Possession affords prima facie presumption of ownership – Scope. (iii) Cash grant – Act makes a mechanism for cash grant (nemnuk) to religious places irrespective of their status as Private/Public or State owned temple. (iv) Shebaitship is like immovable property – Not a mere office, it is property also – It is hereditary and having no right to sale; mortgage or Lease the property.		
धारा 32 – (i) निजी मंदिर में सरकार के हस्तक्षेप – शक्ति का क्षेत्र। (ii) कब्जा स्वामित्व का प्रथमदृष्ट्या अनुमान लगाना है – विस्तार। (iii) नगद अनुदान – अधिनियम धार्मिक स्थलों को नगद अनुदान (नेमनुक) के लिये एक तंत्र बनाता है, चाहे वह निजी या सार्वजनिक या राज्य के स्वामित्व वाले मंदिर के रूप में हो। (iv) शाबितशिप अचल संपत्ति के समान है – केवल ऑफिस नहीं है, यह संपत्ति भी है – वंशागत पद की तरह है जिसे विक्रय, बंधक या पट्टे पर प्रदान नहीं किया जा सकता।	**322**	**386**
Section 34 – Determination of possession – Facts to be considered.		
धारा 34 – आधिपत्य का निर्धारण – सुविचारित किये जाने योग्य तथ्य।	**323**	**388**
Section 34 – Plea of gift deed – Not to be decided on general presumption and assertion.		
धारा 34 – दान विलेख का अभिवाक् – सामान्य उपधारणा और अभिकथन के आधार पर विनिश्चय नहीं होगा।	**215**	**244**
Section 34 – See section 9 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 34 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9।	**109***	**119**
Section 34 – See section 10 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.		
धारा 34 – देखें शहरी भूमि (सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 10।	**164**	**184**

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 34 – See section 54 of the Transfer of Property Act, 1882		
धारा 34 – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54।	**163***	**183**
Sections 34 and 36 – Cancellation of registered sale deed – Procedure – If a registered sale deed is cancelled by registered deed, such cancellation deed is always subject to adjudication of rights of parties by competent Civil Court.		
धाराएं 34 एवं 36 – पंजीकृत विक्रय विलेख का रद्दकरण – प्रक्रिया – यदि पंजीकृत विक्रय विलेख पंजीकृत विलेख द्वारा रद्द किया जाता है, ऐसा रद्दकरण विलेख सदैव सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिकारों के न्यायनिर्णयन के अध्यधीन है।	**216**	**245**
STAMP ACT, 1899		
स्टाम्प अधिनियम, 1899		
Section 35 – See sections 17 and 49 of the Registration Act, 1908.		
धारा 35 – देखें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धाराएं 17 एवं 49।	**103**	**110**
SUCCESSION ACT, 1925		
उत्तराधिकार अधिनियम, 1925		
Section 63 – Proof of Will – The requirement of section 63 of the Act cannot be said to have been fulfilled by mechanical compliance of the stipulations therein – Evidence of meeting the requirement of the said provision must be reliable.		
धारा 63 – वसीयत का साबित किया जाना – अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकताओं की शर्तों को यांत्रिकीय तरीके से पालन कर पूरा नहीं किया जा सकता है – उक्त प्रावधान की आवश्यकता को पूरा करने की साक्ष्य विश्वसनीय होना चाहिए।	**105***	**113**
Section 63 – See sections 3, 8, 17 and 68 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 63 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8, 17 एवं 68।	**20**	**22**
Section 63 – Will – Suspicious circumstances – Redefined – Evidence produced to establish that testator had suffered paralytic stroke affecting his speech, mobility of right arm and right leg – Treating doctor and scriber not examined – No evidence to show as to whom the testator gave instruction to write the Will – No cordial relationship established – Held, Will notproved according to law.		
धारा 63 – वसीयत– संदेहास्पद परिस्थितियां – पुनर्परिभाषित – यह स्थापित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत की गई कि वसीयतकर्ता लकवाग्रस्त था जिससे उसका बोलना, दाहिनी भुजा और दाहिने पैर की गतिशीलता प्रभावित थी – उपचार करने वाले चिकित्सक एवं लेखक का परीक्षण नहीं किया गया – यह दर्शाने हेतु कि वसीयतकर्ता ने वसीयत लिखने हेतु किसे निर्देश दिये, कोई साक्ष्य नहीं – कोई सौहाद्रपूर्ण संबंध स्थापित नहीं – अभिनिर्धारित, वसीयत विधि अुनसार प्रमाणित नहीं।	**123 (i)**	**132**

Section 63 – (i) When the signature of the testator is disputed or the mental capacity of the testator is questioned, it amounts to suspicious circumstances.

(ii) Court does not apply Article 14 to dispositions under a Will.

धारा 63 – (i) जहाँ वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर विवादित है या वसीयतकर्ता की मानसिक अवस्था को प्रश्नगत किया गया है, ये संदेहास्पद परिस्थितियां है।

(ii) वसीयत के अन्तर्गत किए गए प्रबंध पर न्यायालय अनुच्छेद 14 लागू नहीं करती है।

270* **318**

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

Section 41 – Effect of sale by ostensible owner where Power of Attorney did not contain authorization to sell.

धारा 41 – दृश्यमान स्वामी द्वारा विक्रय का प्रभाव जहां मुख्तारनामा के अन्तर्गत विक्रय करने हेतु अधिकृत होने का उल्लेख नहीं था। **272 (ii)** **320**

Section 41 – Right of bonafide purchasers.

धारा 41 – सद्भावी क्रेता के अधिकार। **271 (i)** **319**

Section 53-A – See Order 7 Rule 11(d) of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 53–क – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 14।

224 **254**

Section 54 – Sale of immovable property – Payment of consideration – Sale of an immovable property has to be for a price which may be payable in future – It may be partly paid and the remaining part in future – Payment of price is an essential part of sale covered by section 54 of the TP Act – Sale deed in respect of an immovable property executed without payment of price and does not provide for payment of price at a future date – Is not a sale at all in the eyes of law and has no legal effect – Such a sale will be void and will not effect the transfer of immovable property.

धारा 54 – स्थावर सम्पत्ति का विक्रय – प्रतिफल का भुगतान – स्थावर सम्पत्ति का विक्रय उस कीमत पर होनी चाहिए जो कीमत भविष्य में भुगतान योग्य हो सकती है – यह आंशिक रूप से भुगतान की जा सकती है और अवशेष को भविष्य में भुगतान योग्य बनाया जा सकता है – कीमत का भुगतान धारा 54 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय का अनिवार्य भाग है – स्थावर सम्पत्ति के सम्बंध में विक्रय पत्र कीमत का भुगतान किए बिना निष्पादित किया गया और भविष्यवर्ती दिनांक पर कीमत के भुगतान का प्रावधान नहीं है – ऐसा विक्रय विधि की दृष्टि में कोई विक्रय नहीं है एवं इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है – ऐसा विक्रय स्थावर सम्पत्ति के अंतरण को प्रभावित नहीं करेगा। **163*** **183**

Sections 59-A, 60 and 91 – (i) Right of redemption – Once the plaintiff has purchased property, the equity of redemption is part of the title and as an owner, he could seek redemption of the suit land.

(ii) Necessary party – Necessary party in a suit for foreclosure filed by the mortgagee after the purchase of part of the mortgaged land.

(iii) *Res Judicata* – The declining of stay of execution will not operate as *res judicata* only because section 11 Explanation (vii) of the Code is applicable to execution as well.

धाराएं 59–क, 60 एवं 91 – (i) मोचन का अधिकार – जैसे ही वादी द्वारा संपत्ति क्रय की जाती है, मोचन की साम्या स्वत्व का भाग होने से और स्वामी होने के नाते वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में मोचन की प्रार्थना कर सकता है।

(ii) आवश्यक पक्षकार – बंधक संपत्ति के भाग को क्रय करने के पश्चात् पुरोबंध के लिए प्रस्तुत वाद में उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था।

(iii) *पूर्व न्याय* – संहिता की धारा 11 का स्पष्टीकरण vii निष्पादन पर भी लागू होता है केवल इसीलिए निष्पादन को स्थगित किए जाने से इंकार *पूर्व न्याय* के रूप में क्रियाशील नहीं होगा।

106 113

Sections 106, 111, 112 and 113 – (i) Lease; determination of – Breach of terms of lease – Clause 14 of lease deed stipulateds termination on sub-letting without previous permission in writing of lessor – Name of Managing Partner or the company was mentioned in previous records and documents – Held, there is no breach of the terms of lease.

(ii) 'Default' and 'Breach' – Meaning explained – Clause 12 of lease deed provides that lease can be terminated after notice and hearing lessee – Clause 14 is independent of clause 12 and no notice is required when breach is committed by sub-letting the leasehold property.

(iii) Lease; determination of – Breach of terms of lease – Lessee transferred part of his interest in lease land by registered sale deed – Sale was for consideration, without permission of lessor – Held, this is clear breach of clause 14 of lease deed and thus, termination of lease is proper.

(iv) Lease; determination of – Whether entire lease can be terminated when breach is committed in respect of part of lease land? Held, yes.

धाराएं 106, 111, 112 एवं 113 – (i) पट्टे का पर्यवसान – पट्टे की शर्तों का उल्लंघन – पट्टा विलेख का खंड 14 पट्टाकर्ता की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना उप – किराएदारी पर पट्टे के पर्यवसान का उपबंध करता था – पूर्व के दस्तावेजों एवं अभिलेख में प्रबंध भागीदार अथवा कंपनी का नाम उपयोग में लाया जाता रहा था – अभिनिर्धारित, पट्टे की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

(ii) 'व्यतिक्रम' एवं 'उल्लंघन' – अवधारित, खंड 14 खंड 12 से स्वतंत्र है तथा पट्टाकृत संपत्ति को उप–किराए पर देने का उल्लंघन होने पर किसी भी सूचना की आवश्यकता नहीं होती है।

(iii) पट्टे का पर्यवसान – पट्टे की शर्तों का उल्लंघन – पट्टेदार द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा पट्टे की भूमि में अपना हित हस्तांतरित – विक्रय प्रतिफल सहित था, पट्टाकर्ता की अनुमति नहीं ली गई थी – अवधारित, यह पट्टा विलेख के खंड 14 का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः पट्टे का पर्यवसान उचित है।

(iv) पट्टे का पर्यवसान – क्या पट्टाकृत भूमि के अंशभाग के संबंध में उल्लंघन किए जाने पर संपूर्ण पट्टे का पर्यवसान किया जा सकता है? अवधारित, हाँ। **107** **115**

Section 122 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963.

धारा 122 – देखें विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34। **215** **244**

URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) ACT, 1976
शहरी भूमि (सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976

Section 10 – Declaration of surplus land – Jurisdiction of Civil Court – After conducting inquiry, competent authority passed final order declaring land as surplus land – Possession of land was taken over and the same was allotted to development authority to construct houses for needy slum dwellers – Civil Court cannot declare the order passed by the competent authority as illegal or non est.

धारा 10 – अतिशेष भूमि की घोषणा – सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार – सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत भूमि को अतिशेष भूमि घोषित करने का आदेश पारित किया गया – भूमि का आधिपत्य लेकर उसे विकास प्राधिकरण को जरूरत मंद झुग्गी वासियों के मकान बनाने के लिए आवंटित कर दिया गया – सिविल न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक या अस्तित्वहीन घोषित नहीं कर सकता है। **164** **184**

WAKF ACT, 1995
वक्फ अधिनियम, 1995

Sections 6, 7, 83 and 85 – Jurisdiction of Wakf Tribunal – If tenant pleads that disputed property is not wakf property.

धाराएं 6, 7, 83 एवं 85 – वक्फ अधिकरण का क्षेत्राधिकार – यदि किराएदार विवादित संपत्ति वक्फ सम्पत्ति नहीं होने का अभिवचन करता है। **55** **63**

Sections 83 and 85 – (i) Wakf property – Bar of jurisdiction of Civil Court – Only tribunal constituted under the Act has power to determine any dispute regarding wakf, wakf property, injunction, eviction of tenant and determination of right and obligation of the lessor and lessee of the property.

(ii) Wakf Act – Jurisdiction – Bar of Civil Court contained in sections 6(5) and 7(2) is confined to Chapter II but the bar of jurisdiction u/s 85 is all pervasive.

(iii) Dispute regarding status of wakf property – Only wakf tribunal is proper forum to decide whether subject property is disputed to be wakf property or not.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 83 एवं 85 – (i) वक्फ संपत्ति – सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का वर्जन – केवल अधिनियम के तहत गठित अधिकरण को वक्फ, वक्फ संपत्ति, निषेधाज्ञा, किरायेदार की बेदखली और संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व के निर्धारण के बारे में किसी भी विवाद को निर्धारित करने की शक्ति है। (ii) वक्फ अधिनियम – क्षेत्राधिकारिता – धारा 6(5) और 7(2) में निहित सिविल न्यायालय का वर्जन अध्याय 2 तक ही सीमित है लेकिन धारा 85 के तहत क्षेत्राधिकारिता सर्व व्यापक है। (iii) वक्फ संपत्ति की स्थिति के सम्बन्ध में विवाद – केवल वक्फ अधिकरण यह तय करने के लिए उचित मंच है कि वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।	**165**	**186**

PART – II A
(GUIDELINES)

1.	Guidelines for the Investigating Agencies and Criminal Courts regarding arrest and deciding of bail Applications.	247
2.	Guidelines issued by Hon'ble Supreme Court while exercising powers u/s 319 CrPC.	389

PART – III
(CIRCULARS/NOTIFICATIONS)

1.	Notification dated 25.02.2022 of the Ministry of Road and Highway sregarding date of enforcement of certain provisions of the Motor Vehicles (Amendment)Act, 2019	1
2.	Notification of Ministry of Women & Child Development dated 31.08.2022 regarding date of enforcement of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Act, 2021	5
3.	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में संशोधन विषयक अधिसूचना	3
4.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के संशोधन की अधिसूचना, दिनांक 01 सितम्बर, 2022	6
5.	मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना दिनांक 18.01.2022 विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति विषयक	4
6.	Circular dated 15.12.2022 of the High Court of Madhya Pradesh regarding referral of District judiciary and Trial Courts.	7

PART – IV
(IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS)

1.	The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2021	15
2.	The Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2021	1
3.	The Subordinate Courts of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2020	3
4.	The Code of Civil Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2020	15
5.	मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में संशोधन	17
6.	मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियम, 2022	37

7.	मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में संशोधन	29
8.	दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2019	32
9.	Amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal)	39
10.	Amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961	41
11.	Amendment in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994.	42

NOMINAL INDEX OF CASES INCLUDED IN PART II

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
A.T. Mydeen and anr. v. Assistant Commissioner, Customs Department	2022 CriLJ 1041 (SC) (Three Judge Bench)	176*	199
Abdul Vahab v. State of Madhya Pradesh	2022 (1) Crimes 330 (SC)	263	311
Abhimanyu Partap Singh v. Namita Sekhon and anr.	2022 ACJ 1995	316	372
Achin Phulre and ors. v. State of M.P. and anr.	2022 CriLJ 1719	201*	230
Ajanta LLP v. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha D/B/A Cacio Computer Company Limited and anr.	(2022) 5 SCC 449	275	324
Ajay Khateek v. State of M.P.	ILR (2021) MP 1986	70*	78
Akhilesh and anr. v. Kavita	2022 (2) MPLJ 338	245	280
Akhilesh Singh and anr. v. Krishan Bahadur Singh and ors.	2022 (3) MPLJ 419	279	329
Akhlesh v. Municipal Corporation, Jabalpur and anr.	2022 (3) MPLJ 302	318	377
Amazon.com NV Investment Holdings LIC v. Future Retail Ltd. and ors.	(2022) 1 SCC 209	114	123
Amudhavali and ors. v. P. Rukumani and ors.	2022 (2) MPLJ 264 (SC)	216	245
Anil Kumar Soti and ors. v. State of Uttar Pradesh through Collector Bijnore (Uttar Pradesh)	(2022) 2 SCC 268	83*	93
Ankita Argal and ors.v. State of M.P. and ors.	2021 (4) MPLJ 451	28	34
Anuj Singh alias Ramanuj Singh alias Seth Singh v. State of Bihar	AIR 2022 SC 2817 (Three Judge Bench)	253	301
Anushri Jain v. Anamika Jain and ors.	2022 (2) MPLJ 523	223	254
Arjun S/o Ramanna alias Ramu v. Iffco-Tokio General Ins. Co. Ltd. and anr.	(2022) 5 SCC 706	294	346
Arunachala Gounder (Dead) by LRs. v. Ponnusamy and ors.	AIR 2022 SC 605	188	211
Arvind Kumar alias Nemichand and ors.v. State of Rajasthan	2022 CriLJ 374	130	144
Asha Devi and ors. v. Assistant Director, State Insurance and Provident Fund Department and ors.	2021 ACJ 2679 (SC)	89*	98
Ashok Kumar v. Raj Gupta and ors.	(2022) 1 SCC 20	73*	80
Ashutosh Ashok Parasrampuriya and anr. v. M/s. Gharrkul Industries Pvt. Ltd. and ors.	2021 (4) Crimes 132 (SC)	51	58

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Asian Hotels (North) Ltd. v. Alok Kumar Lodha and ors.	(2022) 8 SCC 145	276*	325
Attorney General for India v. Satish and anr.	2021 (4) Crimes 370 (SC) (Three Judge Bench)	53	60
B.P. @ Amrat Singh Gurjar v. State of M.P.	2022 (2) Crimes 496 (MP)	293	345
Badri Prasad Tiwari v. State of M.P. and ors.	2022 (1) MPLJ 420 (DB)	102	108
Bajaj Allianz General Ins. Co. Ltd. v. Rambha Devi and ors.	2022 ACJ 953 (SC) (Three Judge Bench)	258*	306
Balkrishna Devda and ors. v. State of M.P. and anr.	2022 CriLJ 1538	174	196
Balwan Singh (Dead) By LRs. etc. etc. v. State of Haryana and ors.	AIR 2022 SC 2996	312	368
Bangalore Development Authority v. N. Nanjappa and anr.	AIR 2022 SC 81	113	122
Basanti Devi and anr. v. Divisional Manager, New India Assurance Co. Ltd. and ors.	2022 ACJ 823 (SC)	154*	170
Bata India Limited v. Workmen of Bata India Limited and anr.	(2022) 6 SCC 95	311	367
Beereddy Dasratharami Reddy v. V. Manjunath and anr.	AIR 2022 SC 65	162	181
Bhagchandra v. State of Madhya pradesh	AIR 2022 SC 410 (Three Judge Bench)	136	151
Bhagwan Narayan Gaikwad v. The State of Maharashtra and ors.	2021 (4) Crimes 42 (SC)	14	16
Bhagwan Sharan and anr. v. Krishnakant Bhargava and anr.	AIR 2022 MP 8	161*	181
Bhagwat Narayan Dubey v. Kalicharan and ors.	2022 (3) MPLJ 384	280	330
Bharat Bhushan Gupta v. Pratap Narain Verma and anr.	AIR 2022 SC 2867	232	265
Bharati Bhattacharjee v. Quazi Md. Maksuduzzaman and ors.	(2022) 6 SCC 146	283	332
Bhom Singh and anr. v. Reliance General Ins. Co. Ltd. and anr.	2022 ACJ 716 (Three Judge Bench)	151*	169
Bhupesh Rathod v. Dayashankar Prasad Chaurasia and anr.	2021 (4) Crimes 282 (SC)	52	59
Bijender @ Mandar v. State of Haryana	2021 (4) Crimes 215 (SC) (Three Judge Bench)	22	26
Biswanath Banik and anr. v. Sulanga Bose and ors.	AIR 2022 SC 1519	224	254

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Bombay Chemical Industries v. Deputy Labour Commissioner and anr.	(2022) 5 SCC 629	310	366
Branch Manager, Universal Sompo General Ins. Co. Ltd. v. Devkaran and ors.	2022 ACJ 702	150*	168
Canara Bank v. Bank of India and ors.	2022 (1) MPLJ 466	58*	66
Central Bureau of Investigation (CBI) and anr. v. Thommandru Hannah Vijayalakshmi @ T.H. Vijayalakshmi and anr.	2021 (4) Crimes 141 (SC)	9	12
Chandra @ Chanda @ Chandraram and anr. v. Mukesh Kumar Yadav and ors.	2021 ACJ 2554	47	53
Chandra and ors. v. Branch Manager, Oriental Insurance Co.Ltd. and anr.	2021 ACJ 2550 (SC)	46*	53
Chandrapal v. State of Chhattisgarh (earlier M.P.)	AIR 2022 SC 2542	250	292
Chetna Dholakhandi (Smt.) & ors. v. State of M.P. & ors.	ILR (2021) MP 1896	86*	94
Chhuna @ Chhatra Pal Singh & anr. v. State of M.P.	ILR (2022) MP 168 (DB)	135	149
Child in Conflict with Law v. State of M.P. and anr.	2022 CriLJ 2358	255	303
Criminal Trails Guidelines regarding Inadequacies and Deficiencies, In Re v. State of Andhra Pradesh and ors.	(2021) 10 SCC 598 (Three Judge Bench)	26	31
Debananda Tamuli v. Smti Kakumoni Kataky	AIR 2022 SC 1099	184	207
Deepak Yadav v. State of U.P. and anr.	AIR 2022 SC 2514 (Three Judge Bench)	240	275
Devender Singh and ors. v. State of Uttarakhand	AIR 2022 SC 2965 (Three Judge Bench)	304	359
Devendra Ku. Agrawal v. State of M.P. and anr.	2022 CriLJ 2048	264*	313
Dharamender v. United India Insurance Co. Ltd. and ors.	2022 ACJ 158 (SC)	66*	73
Dilip Hariramani v. Bank of Baroda	AIR 2022 SC 2258	260	308
Dipali Biswas and ors. v. Nirmalendu Mukherjee and ors.	AIR 2021 SC 4756	2	2
Dr. Harish Kumar Khurana v. Joginder Singh and ors.	(2021) 10 SCC 291	23*	28
Durgesh Singh Bhadauria v. State of M.P.	ILR (2022) MP 138 (DB)	121	129
Dyna Chem (M/s) v. Jaipaldas S/o Ghuriyomal Punjabi	2021 (4) MPLJ 406	5*	8

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Estate Officer v. Colonel H.V. Mankotia (Retired)	AIR 2021 SC 4894	44	51
Ex. Ct. Mahadev v. Director General Border Security Force and ors.	AIR 2022 SC 2986	303	358
Farooqi Begum (D) by LRs. v. State of Uttar Pradesh	AIR 2022 SC 3295	323	388
Ganesan v. State Rep. by Station House Officer	AIR 2021 SC 5643	82	92
Gangashankar Dubey v. Sindhu Bai and ors.	2022 (1) MPLJ 315	103	110
Gayatri Parashar v. Tulsiram Kori	2022 (2) MPLJ 327	168	191
Gayatri Project Ltd. v. Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd.	2022 (2) MPLJ 425	169	191
Geo Varghese v. State of Rajasthan & anr.	2021 (4) Crimes 71 (SC)	37	45
Ghulam Hassan Beigh v. Mohammad Maqbool Megrey & ors.	2022 (3) Crimes 160 (SC) (Three Judge Bench)	291	342
Gopal Krishna Gautam @ Pandit v. State of M.P. & anr.	ILR (2021) MP 1975	96*	101
Government of Maharashtra (Water Resources Department) v. Borse Brothers Engineers and Contractors Pvt. Ltd.	2021 (4) MPLJ 274 (Three Judge Bench)	1	1
Govind Singh Yadav (Dead) thr. LRs. Rammurti Yadav & ors. v. Dilip Singh Yadav & ors.	ILR (2022) MP 125	125	135
Gurwinder Singh v. Pirthi Singh and ors.	2022 ACJ 747 (SC)	153*	170
H.B. Products v. H.T. Products	2022 (3) MPLJ 404	278	328
Hameer Singh and ors. v. State of Madhya Pradesh	2021 CriLJ 4676 (DB)	32	41
Haneef Khan v. State of M.P.	ILR (2022) MP 205	119	128
Hariprasad Bairagi v. Radheshyam and ors.	2022 (1) MPLJ 414 (DB)	85*	94
Haseen Khan v. State of M.P. and ors.	2021 CriLJ 4739	31	37
Heera Traders v. Kamla Jain	AIR 2022 SC 1377	166	189
Himalaya Vintrade Pvt. Ltd. v. Md. Zahid and anr.	AIR 2021 SC 5749	60	67
Indira Chaurasia (deceased) through LRs. Bipin Bihari Chaurasia and ors. v. Director, Krishi Upaj Mandi Board and ors.	2022 (1) MPLJ 625	112*	121
Indrapal Singh and ors. v. State of U.P.	AIR 2021 SC 4514 (Three Judge Bench)	30	36
Indresh Patel and anr. v. Narad Choudhari and ors.	AIR 2022 (NOC) 564 (CHH.)	281*	331

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Indu @ Indrapal Singh & anr. v. State of M.P.	ILR (2021) MP 1602 (DB)	76	82
I-Pay Clearing Services Private Limited v. ICICI Bank Limited	(2022) 3 SCC 121	170	193
Irappa Siddappa Murgannavar v. State of Karnataka	2021 (4) Crimes 221 (SC) (Three Judge Bench)	21	24
Jacob Punnen and anr. v. United India Insurance Co. Ltd.	2022 ACJ 450	115	124
Jafarudheen v. State of Kerala	(2022) 8 SCC 440	296	347
Jagdish Singh and anr. v. State of M.P.	2022 CriLJ 826	200	228
Jagjeet Singh and ors. v. Ashish Mishra alias Monu and anr.	AIR 2022 SC 1918 (Three Judge Bench)	239*	275
Jaidev Rajnikant Shroff v. Poonam Jaidev Shroff	(2022) 1 SCC 683	160	180
Jamia Masjid v. K.V. Rudrappa (Since Dead) By LRs. and ors.	AIR 2021 SC 4523 (Three Judge Bench)	3	3
Janabai and ors. v. ICICI Lombard General Ins. Co. Ltd.	2022 ACJ 2003	317	375
Jangli v. State of Madhya Pradesh	2021 CriLJ 5017 (DB)	33*	42
Jaswinder Singh (dead) Through LRs. v. Navjot Singh Sidhu and ors.	AIR 2022 SC 2441	308	362
Jithendran v. New India Assurance Co. Ltd. and anr.	AIR 2021 SC 5382	95	101
Jogi Ram v. Suresh Kumar and ors.	(2022) 4 SCC 274	187	209
K. Anusha and ors. v. Regional Manager, Shriram General Ins. Co. Ltd.	2022 ACJ 721 (SC)	155*	171
K. Arumuga Velaiah v. P.R. Ramasamy and anr.	(2022) 3 SCC 757 (Three Judge Bench)	211	240
K. Karuppuraj v. M. Ganesan	AIR 2021 SC 4652	4	5
K. Muruganandam & ors. v. State Rep. by the Deputy Superintendent of Police & anr.	2022 (2) Crimes 122 (SC)	177*	199
K. Shanthamma v. The State of Telangana	2022 (1) Crimes 425 (SC)	209	239
K. Srinivasappa and ors. v. M. Mallamma and ors.	AIR 2022 SC 2381	230	263
K.S. Ranganatha v. Vittal Shetty	2022 (1) Crimes 454 (SC) (Three Judge Bench)	158*	176
Kahkashan Kausar @ Sonam and ors. v. State of Bihar and ors.	2022 (1) Crmes 376 (SC)	202	230
Kala Singh @ Gurnam Singh v. State of Punjab	2021 (4) Crimes 119 (SC)	35	43

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Kallu Khan v. State of Rajashtan	AIR 2022 SC 50	157	173
Kamatchi v. Lakshmi Narayanan	AIR 2022 SC 2932	266	314
Kamla Devi v. State of Rajasthan & anr.	2022 (2) Crimes 29 (SC)	238	277
Kanchan Sharma v. State of Uttar Pradesh and anr.	2021 (4) Crimes 48 (SC)	36	44
Karan Singh v. The State of Uttar Pradesh and ors.	2022 (1) Crimes 336 (SC)	244*	280
Kattukandi Edathil Krishnan and anr. v. Kattukandi Edathil Valsan and ors.	AIR 2022 SC 2841	228	258
Keshav and ors. v. Gian Chand and anr.	AIR 2022 SC 678	215	244
Kewal Krishan v. Rajesh Kumar and ors.	2022 (1) MPLJ 494 (SC)	163*	183
Kirpal Kaur and anr. v. Ritesh and ors.	AIR 2022 SC 1555	268	317
Krishi Upaj Mandi Samiti, Dhar v. M/s. Khemchand Jain, Dhar	2022 (2) MPLJ 419	171	194
Krishna Bhadoria v. Geeta Bhadoria and anr.	2022 (1) MPLJ 677	210*	240
Krishnamurthy @ Gunodu and ors. v. State of Karnataka	2022 (2) Crimes 101 (SC)	191	217
Kuljit Singh and anr. v. State of Punjab	(2022) 1 SCC 385 (Three Judge Bench)	138*	154
Kurvan Ansari and anr. v. Shyam Kishore Murmu and anr.	2022 ACJ 166	91*	98
L.I.C. of India and anr. v. Sunita	2021 ACJ 2731	94*	100
Lala Alias Anurag Prakash Aasre v. State of Maharashtra	AIR 2021 SC 5199	71*	79
Lalu Sindhi @ Dayaldas v. State of M.P.	ILR (2021) MP 1932 (DB)	77	84
Leena v. Manish Purushottam Upadhayay	AIR 2022 MP 84 (DB)	300	352
M. Nageswara Reddy v. State of Andhra Pradesh and ors.	2022 CriLJ 2254 (SC)	241*	278
M.P. Housing and Infrastructure Development Board and anr. v. K.P. Dwivedi	2022 (2) MPLJ 637 (SC)	218	249
M.P. Power Management Company Ltd., Jabalpur v. Sky Power South East Solar India Ptd. Ltd. & ors.	2022 (1) MPLJ 68 (DB)	64	70
M.S.P. v. State of Madhya Pradesh & anr.	2022 (2) Crimes 293 (SC) (Three Judge Bench)	292	344
M/s. Knit Pro International v. The State of NCT of Delhi and anr.	2022 (2) Crimes 381 (SC)	284	333
M/s. Sree Surya Developers and Promoters v. N. Sailesh Prasad and ors.	AIR 2022 SC 1031	172	194

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
M/s. TRL Krosaki Refractories Ltd. v. M/s. SMS Asia Private Limited & anr.	2022 (1) Crimes 415 (SC)	208	238
Mahadev Meena v. Praveen Rathore and anr.	2022 CriLJ 671	120	128
Mahendra K.C. v. State of Karnataka and anr.	(2022) 2 SCC 129	139	155
Mahendra Kumar Dubey v. Economic Offence Wing, Unit: Gwalior thr. its Superintendent of Police, E.O.W. Gwalior (M.P.)	2022 CriLJ 962	290	341
Mahendra Singh and ors. v. State of M.P.	AIR 2022 SC 2631	249	290
Makhan Singh v. State of Haryana	2022 (3) Crimes 269 (SC)	298	350
Managing Director (Shri Grish Batra) Padmini Infrastructure Developers (I) Ltd. v. General Secretary (Shri Amol Mahapatra) Royal Garden Residents Welfare Association	AIR 2021 SC 4627	8	11
Manglesh v. Jayakishan (since dead) through LRs. and anr.	2022 (2) MPLJ 550	259	307
Manjula and ors. v. Shyamsundar and ors.	(2022) 3 SCC 90	111	120
Manmohan Lal Gupta (Dead) through LRs. v. Market Committee Bhikhi and ors.	(2021) 10 SCC 395	43	50
Manmohan Nanda v. United India Insurance Co. Ltd. and anr.	2022 ACJ 496	116	125
Manoj @ Monu @ Vishal Chaudhary v. State of Haryana & anr.	2022 (1) Crimes 479 (SC) (Three Judge Bench)	182*	206
Manoj Kumar Khokhar v. State of Rajasthan and anr.	2022 (1) Crimes 440 (SC)	179	203
Manoj Mishra @ Chhotkau v. State of Uttar Pradesh	2021 (4) Crimes 104 (SC)	38	45
Meena Pawaia and other v. Ashraf Ali and ors.	2022 ACJ 528 (SC)	156	171
Meera v. State by the Inspector of Police thiruvotriyur Police Station Chennai	(2022) 3 SCC 93	203	231
Methu and ors. v. Late Leemchand and ors.	AIR 2022 MP 100	226*	256
Milkhi Ram v. Himachal Pradesh State of Electricity Board.	AIR 2021 SC 5025	59	66
Mitesh Kumar J. Sha v. State of Karnataka and ors.	2022 CriLJ 231	143	159
Mohan @ Srinivas @ Seena @ Tailor Seena v. State of Karnataka	2022 (2) Crimes 114 (SC)	189	214
Mohd. Firoz v. State of Madhya Pradesh	AIR 2022 SC 1967 (Three Judge Bench)	235	271

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Mohd. Rafiq @ Kallu v. the State of Madhya Pradesh	2021 (4) Crimes 53 (SC)	34	43
Mohd. Sakhawat Noor v. State of M.P. and ors.	2022 (2) MPLJ 342	204	232
Mrs. Umadevi Nambiar v. Thamarasseri Roman Catholic Diocese Rep. by its Procurator Devssia's Son Rev. Father Joseph Kappil	AIR 2022 SC 1640	272	320
Ms. P XXX v. State of Uttarakhand and anr.	AIR 2022 SC 2885	289	339
Mukesh v. State of Madhya Pradesh	2022 CriLJ 915 (SC)	190	216
Munnalal alias Bicholi and Jagdish v. State of M.P.	2022 CriLJ 697 (DB)	141	157
Munni Devi alias Nathi Devi (Dead) thr. LRs. and ors. v. Rajendra alias Lallu Lal (Dead) thr. LRs. and ors.	AIR 2022 SC 2596	302	355
Munusamy v. Land Acquisition Officer	AIR 2021 SC 4715	42*	49
Murthy and ors. v. C. Saradambal and ors.	(2022) 3 SCC 209	123	132
Musstt Rehana Begum v. State of Assam and anr.	2022 (2) Crimes 79 (SC)	183	206
N. Jayasree and ors. v. Cholamandalam Ms. General Insurance Company Ltd.	AIR 2021 SC 5218	92	99
N. Raghavender v. State of Andhra Pradesh, CBI	AIR 2022 SC 826	144	160
Nag Leather Private Limited v. Dynamic Marketing Partnership represented by its partners and anr.	(2022) 2 SCC 271	98*	103
Nagendra Sah v. State of Bihar	2021 (4) Crimes 334 (SC)	25	30
Nahar Singh v. State of Uttar Pradesh and anr.	2022 (2) Crimes 51 (SC)	234	267
Nandu Galtha Pardi v. State of Madhya Pradesh through Police Station Kotwali District Guna (M.P.)	2021 CriLJ 4867 (DB)	40*	48
Nanjundappa and anr. v. State of Karnataka	AIR 2022 SC 2374 (Three Judge Bench)	309	364
Narayan Deorao Javle (deceased) through LRs. v. Krishna and ors.	AIR 2021 SC 3920	106	113
Narayana Prasad Sahu v. State of Madhya Prasad	(2022) 1 SCC 87	100	104
Narbad Ahirwar & anr. v. State of M.P.	ILR (2021) MP 2339 (DB)	131	146
Naresh Soni v. Shankar Singh	2022 (1) MPLJ 592	109*	119
Naresh v. State of M.P.	ILR (2022) MP 157 (DB)	124	134

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Naser Bin Abu Bakr Yafai v. State of Maharashtra and anr.	AIR 2021 SC 5076 (Three Judge Bench)	97	102
Nasib Singh v. The State of Punjab & anr.	2021 (4) Crimes 173 (SC)	16	17
Nathu Singh v. State of M.P.	ILR (2021) MP 1388 (DB)	29*	35
National Insurance Co. Ltd. v. Chamundeswari	2021 ACJ 2558	48	54
National Insurance Co. Ltd. v. Sunita Markam and ors.	2022 ACJ 1799	314	370
Nawabzadi Qamar Taj Rabia Sultan through LRs. v. Nawab Mehr Taj Sajida Sultan	AIR 2022 MP 74	220*	251
Neha Tyagi v. Lieutenant Colonel Deepak Tyagi	(2022) 3 SCC 86	127	141
Nirmala Devi v. Anil Kumar Tiwari	AIR 2022 MP 27 (DB)	126	139
Nitin Khandelwal & anr. v. State of M.P.	ILR (2020) MP 1178	10*	13
Oil and Natural Gas Corporation Limited v. Discovery Enterprises Private Limited and anr.	(2022) 8 SCC 42	273	323
Oriental Insurance Co. Ltd. v. Munesh Adiwashi and ors.	2022 ACJ 264	90*	98
Oriental Insurance Co. Ltd. v. Komalbai Chouhan and ors.	2021 ACJ 2473	45	52
P. Meenaraj v. P. Adigurusamy and anr.	2022 ACJ 1001	180*	204
P. Ramasubbamma v. V. Vijayalakshmi and ors.	AIR 2022 SC 1793	269*	318
Pappu @ Dayaram v. State of M.P.	ILR (2021) MP 1571 (DB)	78	85
Pappu Tiwary v. State of Jharkhand	AIR 2022 SC 758	195	222
Parenteral Drugs (India) Ltd. v. Gati Kintetsu Express Pvt. Ltd.	2022 (2) MPLJ 659	219	250
Parvati Devi v. State of Bihar now State of Jharkhand and ors.	AIR 2022 SC 1268 (Three Judge Bench)	194	221
Phool Singh v. State of Madhya Pradesh	(2022) 2 SCC 74	140	155
Pinki v. State of M.P.	ILR (2021) MP 1586	81	90
Pooja Soni v. Dinesh Kumar and ors.	2022 (1) MPLJ 703	110*	120
Poongavanam v. Reliance General Ins. Co. Ltd. and anr.	2022 ACJ 205	93*	100
Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi	AIR 2022 SC 2331	265*	313
Pradeep Sakhawar v. State of M.P. and anr.	2022 CriLJ 1814	199*	228
Prafful Kumar Jain v. Sushila Devi	2022 (2) MPLJ 545	217	249
Prakash Corporates v. Dee Vee Projects Limited	AIR 2022 SC 946	173	195

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Prem Shankar Prasad v. State of Bihar & anr.	2021 (4) Crimes 303 (SC)	19	21
Premlata alias Sunita v. Naseeb Bee and ors.	AIR 2022 SC 1560	222	252
Premlata Jain and ors. v. Nagar Palika Parishad, Barod, Madhya Pradesh and ors.	AIR 2022 MP 111	282*	331
Punjab State Civil Supplies Corporation Ltd. and anr. v. Ramesh Kumar and company and ors.	AIR 2021 SC 5758	57*	65
Pushpa Devi v. Santoshi Lal Sharma	AIR 2021 MP 180 (DB)	7	10
Pushpa Sen v. Manoj Sen	2022 (1) MPLJ 418 (DB)	74*	81
R. Janakiammal v. S.K. Kumarasamy (Deceased) through LRs. and ors.	(2021) 9 SCC 114	27	33
R.K. Akhande v. Special Police Establishment, Lokayukt, Bhopal & anr.	ILR (2021) MP 1613 (DB)	65	71
Raghuraj Singh and ors. v. State of M.P. and ors.	2022 CriLJ 2650	288	339
Rahul v. State of Madhya Pradesh	ILR (2022) MP 941 (DB)	17	18
Rajabeti Sakhwar and ors. v. Darshanlal Sakhwar and ors.	2021 CriLJ 4183	67	73
Rajendra Bajoria and ors. v. Hemant Kumar Jalan and ors.	AIR 2021 SC 4594	6	9
Rajendra v. State of M.P. and anr.	ILR (2020) MP 1172	41*	49
Rajesh Bhoyale v. Mahadevi	AIR 2022 MP 95 (DB)	246	282
Rajesh Prasad v. State of Bihar and anr.	(2022) 3 SCC 471 (Three Judge Bench)	178	200
Rajesh v. State of M.P.	ILR (2021) MP 1910	68*	74
Rajpal Singh v. Saroj (Deceased) through LRs. and anr.	AIR 2022 SC 2707	271	319
Rakesh and anr. v. State of U.P. and anr.	2022 CriLJ 590	137	153
Ram Bahadur Thapa v. State of M.P.	2022 CriLJ 1473	192	219
Ram Ratan v. State of Madhya Pradesh	AIR 2022 SC 518 (Three Judge Bench)	142*	158
Ramesh Chandra Srivastava v. The State of U.P. & anr.	2021 (4) Crimes 61 (SC)	13	15
Ramesh Kumar v. Bhatinda Integrated Cooperative Cotton Spinning Mills and ors.	(2022) 1 SCC 284	147	166
Rameshchandra and ors. v. Rajesh Kumar Sharma and ors.	2022 (3) MPLJ 441	277	325
Ramkrishna Sharma v. State of M.P. and anr.	2022 (3) MPLJ 229	322	386

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Ramrao Shankar Tapase v. Maharashtra Industrial Development Corporation and ors.	(2022) 7 SCC 563	313	369
Ramua (Dead) and anr. v. Kodulal and anr.	2022 (2) MPLJ 331	229	260
Rashid Wali Beg v. Farid Pindari and ors.	(2022) 4 SCC 414	165	186
Ravi Sharma v. State (Government of NCT of Delhi) and anr.	(2022) 8 SCC 536	307*	361
Ravinder Singh alias Kaku v. State of Punjab	(2022) 7 SCC 581	299	350
Ravindranath Bajpe v. Mangalore Special Economic Zone Ltd. and ors. Etc.	AIR 2021 SC 4587	12	14
Rishi Pal Singh v. New India Assurance Co. Ltd. and ors.	2022 ACJ 1868	315	371
Rishipal Singh Solanki v. State of Uttar Pradesh and ors.	AIR 2022 SC 630	145	162
S.G. Vombatkere v. Union of India	2022 (2) Crimes 313 (SC) (Three Judge Bench)	305	360
Sabit Khan v. State of M.P. & ors.	ILR (2021) MP 1871 (DB)	99*	103
Sadakat Kotwar and anr. v. State of Jharkhand	AIR 2021 SC 5747	79	87
Sagar Lolienkar v. State of Goa and anr.	(2022) 1 SCC 161	133	148
Sagar v. State of U.P. and anr.	AIR 2022 SC 1420	236	272
Salim D. Agboatwala and ors. v. Shamalji Oddhavji Thakkar and ors.	AIR 2021 SC 5212	61	68
Sanjay Kumar Singh v. State of Jharkhand	AIR 2022 SC 1372	257	306
Sanjay Kumar v. Sunil and ors.	2022 ACJ 718	152*	169
Sarepalli Sreenivas and ors. v. State of Andhra Pradesh	(2022) 6 SCC 116	306*	361
Sartaj Khan v. State of Uttarakhand	2022 (2) Crimes 96 (SC) (Three Judge Bench)	233	266
Sathyanath and anr. v. Sarojamani	AIR 2022 SC 2242	227	256
Satyanarayan Paliwal v. Mukesh Patel and ors.	AIR 2021 MP 205	62	68
Satye Singh and anr. v. State of Uttarakhand	2022 (1) Crimes 467(SC)	197	225
Saurabh and anr. v. State of M.P. and ors.	2022 (2) MPLJ 615	267	316
SBI Global Factors Ltd. v. State of Maharashtra and ors.	2022 (2) MPLJ 43	261	310
Serious Fraud Investigation Officer v. Rahul Modi & ors.	2022 (1) Crimes 390 (SC)	175	197
Seth Trilokchand Kalyanmal Digambar Jain and anr. v. Sushil Kumar Kasliwal and anr.	2022 (1) MPLJ 266	101	105
SGS India Ltd. v. Dolphin International Ltd.	AIR 2021 SC 4849	24	29

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Shailesh Jain alias Banti v. Sachin Pal and ors.	AIR 2022 (NOC) 628 (MP)	285*	334
Shankar alias Shiva alias Bitniya v. State of M.P.	2022 CriLJ 147	129	142
Shankarrao Bhagwantrao Patil Etc. v. State of Maharashtra	AIR 2021 SC 4962	84	93
Sheethakathi Trust Madras v. Krishnaveni	(2022) 3 SCC 150	212	241
Shenbagam and ors. v. K.K. Rathinavel	AIR 2022 SC 1275	213	242
Shiv Kumar Singh and anr. v. State of M.P.	2022 CriLJ 734	122	131
Shripati Lakhu Mane v. Member Secretary, Maharashtra Water Supply and Severage Board & ors.	AIR 2022 SC 1574	231	264
Shyamlal Vyas (Dead) through LRs. Gopi Vyas and ors. v. Inderchand (Dead) through LRs. Om Prakash Jain and ors.	2022 (2) MPLJ 352	167	190
Shyamnath Sharma v. Kripal Singh Bedi and ors.	AIR 2022 MP 70	225*	256
Siddharth v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2022) 1 SCC 676	118	127
Sitaram v. Kanhaiyalal	2022 (3) MPLJ 387	319	378
Smt. Shakuntla Agrawal and ors. v. Manish Gupta and ors.	2022 (2) MPLJ 505	221	252
Som Dutt & ors. v. State of Himachal Pradesh	2022 (1) Crimes 124 (SC)	254	303
Somakka (Dead) by LRs. v. K.P. Basavaraj (Dead) by LRs.	AIR 2022 SC 2853	301	353
Soman v. Inland Waterways Authority of India and anr.	AIR 2022 SC 104	146*	165
Somesh Chaurasia v. State of M.P. and anr.	ILR (2021) MP 1463 (SC)	69	75
Special Police Establishment v. Umesh Tiwari and anr.	2022 CriLJ 2443 (DB)	286	334
Sripati Singh (Since deceased) through his son Gaurav Singh v. State of Jharkhand and anr.	2021 (4) Crimes 273 (SC)	50	55
State of Chattisgarh and anr. v. Sal Udyog Private Limited	AIR 2021 SC 5503 (Three Judge Bench)	56	65
State of Haryana v. Harnam Singh (Dead) through LRs. and ors.	(2022) 2 SCC 238	105*	113
State of Haryana v. Shiv Shankar Construction Company and anr.	(2022) 3 SCC 109	108	119
State of Kerala and ors. v. M/s. Joseph and Company.	AIR 2021 SC 4486	107	115
State of M.P. & anr. v. Ravi Mohan Trivedi	2022 (1) MPLJ 207 (DB)	149	167

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
State of M.P. v. Anil Sharma and ors.	2021 CriLJ 4720	11*	13
State of M.P. v. Ghisilal	AIR 2022 SC 275	164	184
State of Madhya Pradesh v. Jogendra and anr.	AIR 2022 SC 933 (Three Judge Bench)	198	226
State of Madhya Pradesh v. Mahendra alias Golu	2021 (4) Crimes 289 (SC)	39	46
State of Madhya Pradesh v. Rizwan Khan	2021 CriLJ 4769 (DB)	15*	17
State of Odisha and ors. Etc. v. Sulekh Chandra Pradhan Etc.	(2022) 7 SCC 482	321	383
State of Rajasthan v. Bablu Alias Om Prakash	AIR 2022 SC 1288	193*	221
State of Rajasthan v. Banwari Lal and anr.	2022 (2) Crimes 143 (SC)	252	300
State of Uttar Pradesh v. Subhash @ Pappu	2022 (2) Crimes 86 (SC)	248	288
State of Uttar Pradesh v. Veerpal and anr.	2022 (4) SCC 741	295	347
State of Uttarakhand v. Sachendra Singh Rawat	2022 (1) Crimes 397 (SC)	196	224
Sughar Singh v. Hari Singh (dead) through LRs. and ors.	AIR 2021 SC 5581	104	112
Sumathi and ors. v. National Insurance Co. Ltd. and anr.	2022 ACJ 1315 (SC)	207	236
Sunil Todi and ors. v. State of Gujarat and anr.	AIR 2022 SC 147	159	177
Sunita Palita & ors. v. M/s. Panchami Stone Quarry	2022 (3) Crimes 189 (SC)	320	382
Surendran v. State of Kerala	AIR 2022 SC 2322 (Three Judge Bench)	242	278
Suresh v. State of M.P.	ILR (2021) MP 2319 (DB)	80	88
Suryavir v. State of Haryana	(2022) 3 SCC 260	181	204
Swarit Verma v. Kanchan Verma	2022 (1) MPLJ 371	75*	82
Swarnalatha and ors. v. Kalavathy and ors.	AIR 2022 SC 1585	270*	318
Taijuddin v. State of Assam and ors.	(2022) 1 SCC 395	132	147
Taqdir v. State of Haryana	(2022) 4 SCC 321 (Three Judge Bench)	243*	279
Tarasiya and ors. v. Ramlakhan and ors.	2022 (1) MPLJ 23	148	167
Telangana State Wakf Board and anr. v. Mohamed Muzafar	(2021) 9 SCC 179	55	63
Triyambak S. Hegde v. Sripad	2021 (4) Crimes 34 (SC)	49	54
Union of India & ors. v. Dalbir Singh	2021 (4) Crimes 122 (SC)	54*	63
Union of India & ors. v. Major R. Metri No. 08585N	2022 (1) Crimes 126 (SC)	262	310

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Union of India v. Premlata and ors.	AIR 2022 SC 1693	256*	305
United India Insurance Co. Ltd. v. Anita Devi and ors.	2022 ACJ 1108 (Delhi)	205*	235
United India Insurance Co. Ltd. v. Shalumol and ors.	2022 ACJ 1251 (Kerala)	206*	235
United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar Godara	2021 ACJ 2673 (SC)	87	95
Universal Petro Chemicals Ltd. v. B.P. PLC and ors.	AIR 2022 SC 1183	214	243
Usha Hukumsingh v. Hukumsingh Arjunsingh Shekhawat	AIR 2022 MP 12 (DB)	128	142
Uttam v. State of Maharashtra	(2022) 8 SCC 576	297	349
V. Anantha Raju and anr. v. T.M. Narasimhan and ors.	AIR 2021 SC 5342 (Three Judge Bench)	72	80
V. Prabhakara v. Basavaraj K. (Dead) by LRs. and anr.	AIR 2021 SC 4830	20	22
Vaishno Devi Construction Rep. thr. Sole Proprietor (D) Thr. LRs. and anr. v. Union of India and ors.	AIR 2021 SC 5309	63	69
Varsha Garg v. State of Madhya Pradesh and ors.	2022 (3) Crimes 211 (SC)	287	335
Vasudha Sethi and ors. v. Kiran V. Bhaskar and anr.	AIR 2022 SC 476	186*	209
Vasuki and anr. v. Santhi and anr.	2022 ACJ 244	88*	97
Veerendra v. State of Madhya Pradesh	AIR 2022 SC 2396 (Three Judge Bench)	251	295
Vibha v. Kailash	2022 (2) MPLJ 320 (DB)	185	208
Vidhi Ka Ulaghan Karne Wala Balak v. State of M.P. and anr.	2022 CriLJ 2162	237*	273
Vijay Kumar Ghai & ors. v. The State of West Bengal & ors.	2022 (2) Crimes 36 (SC)	247	284
Vinod Kumar v. Amritpal alias Chhotu and ors.	AIR 2022 SC 244	134*	149
Vipan Kumar Dhir v. State of Punjab and anr.	2021 (4) Crimes 67 (SC)	18	20
Viram alias Virma v. State of Madhya Pradesh	(2022) 1 SCC 341	117	126
Vishnu Prasad Goyal v. Ankit Gupta and ors.	AIR 2022 MP 103	274*	324